



हरिभूमि

दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेश से एक साथ प्रकाशित

समाचार ही नहीं, विचार भी

प्लेटफार्म में लगाई गई 65% स्वदेशी सामग्री, जिसे बढ़ाकर 90% तक किया जा सकता है

डीआरडीओ अध्यक्ष ने दिखाई स्वदेशी उन्नत बख्तरबंद प्लेटफार्म को हरी झंडी



हरिभूमि ब्यूरो ► नई दिल्ली

घरेलू सुरक्षा चुनौतियों के बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने शनिवार को भारतीय सेना की उभरती हुई परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वदेशी रूप से उन्नत दो बख्तरबंद प्लेटफार्म (एपीपी, ट्रैक और पहिएदार) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि पुणे के अहिल्यानगर स्थित वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान (वीआरडीई) में डीआरडीओ अध्यक्ष डॉ. समीर. वी. कामत द्वारा इन प्लेटफार्म को रवाना किया गया। दोनों का डिजाइन के साथ विकास वीआरडीई द्वारा किया गया है।

लगाई गई 65% स्वदेशी सामग्री: मंत्रालय ने बताया कि इन प्लेटफार्म पर 65% तक स्वदेशी सामग्री लगाई गई है। जिसे भविष्य में बढ़ाकर 90% तक करने की योजना है। निर्माण कार्य में पुणे स्थित मेसर्स टोएएसएल और ► शोष पेज 5 पर

संघ ने पीएम मोदी को बताया सबसे 'अच्छा प्रतिनिधि', तारीफ कर कहा

संघ के विचारों को बहुत 'तेजी' से आगे बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, कई उदाहरण भी दिए

► भले ही पीएम मोदी अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विचार संघ का ही होता है

► एक पेड़ मां के नाम अभियान और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाएं संघ का विचार हैं

एजेसी ► वॉशिंगटन
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि संघ के विचारों को पीएम मोदी बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने एक साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगठन के मूल्यों को अपने अनेखे और अलग तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी को आरएसएस का



नरेंद्र मोदी

दत्तात्रेय होसबाले

सबसे अच्छा प्रतिनिधि बताते हुए कहा कि कई सरकारी अभियानों के जरिए इन्होंने विचारों को पीएम आगे बढ़ा रहे हैं, भले ही वे अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण देते हुए होसबाले ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी योजनाओं का जिक्र किया। होसबाले ने यह भी कहा कि आरएसएस के विचार स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए पंच प्रणय में भी दिखाई देते हैं। ये

सभी पहल संगठन की सोच से मेल खाती हैं। उन्होंने कहा कि 1980 में भाजपा के गठन के समय भी आरएसएस के साथ संबंध बनाए रखने की बात कही गई थी और यह जुड़ाव आज भी कायम है। इसके अलावा सरकार्यवाह ने कहा कि संघ ने अगले 25 वर्षों के लिए सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक जागरूकता, नागरिक अनुशासन, पारिवारिक मूल्यों और सतत विकास जैसे ► शोष पेज 5 पर

► संघ ने अगले 25 वर्षों के लिए पांच लक्ष्य तय किए हैं
► 2047 तक भारत आर्थिक रूप से मजबूत होगा और वैश्विक लीडर बनेगा

प्लाट उपलब्ध है
भोपाल की सबसे ज्यादा विकासशील लोकेशन
अयोध्या बायपास
10 लेन रोड और 66 फीट मेन रोड महोली खोज की प्राईम लोकेशन में खययेशन, सर्वसुविधायुक्त,
पीपुल्स मॉल, पीपुल्स हास्पिटल, मीनाल मॉल और मेन मार्केट के नजदीक
संपर्क- 9755600569
8200502943, 7748022609

inh
छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश का सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल देखें
TATA PLAY | airtel
चैनल नं. 1155 | चैनल नं. 366

आज का मुक़ाबला
जीटी सीएसके
दोपहर 3.30 बजे से
एलएसजी केकेआर
शाम 7.30 बजे से

स्वर्ण संक्षेप

पीएम मोदी से मिले नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष

नई दिल्ली। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष डॉ. अशोक लाहिड़ी ने पद संभालने के एक दिन बाद शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह उनका नई जिम्मेदारी में पहली बैठक थी, जिससे संकेत मिलता है कि सरकार नीति आयोग के कामकाज को लेकर सक्रिय है।

अमेरिकी संसद में नया सख्त बिल हुआ पेश

65 से घटाकर 25 हजार वीजा देने का लक्ष्य

एजेसी ► नई दिल्ली

अमेरिका में रिपब्लिकन सांसदों के एक समूह ने एच-1बी वीजा प्रणाली में बड़ा बदलाव कर तीन साल का प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से एच-1बी वीजा एब्यूज एक्ट 2026

बालेंद्र शाह की नई सरकार के ऊर्जा मंत्री से हुई नेपाल में भारत के राजदूत की बैठक

हरिभूमि ब्यूरो ► नई दिल्ली

नेपाल में हालिया गठित हुई बालेंद्र शाह की अगुवाई वाली नई सरकार के ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री बिराज भक्त श्रेष्ठ के साथ नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव की एक अहम मुलाकात हुई है। जिसमें दोनों देशों के आपसी हितों और उसके साथ-साथ ऊर्जा सहयोग से जुड़े मामलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। यहां बता दें कि युवाओं खासकर 'जेन-जेड' के उग्र विरोध



प्रदर्शनों के बाद मार्च महीने में नेपाल में हुए आम चुनावों में बालेंद्र शाह के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) को मिली प्रचंड जीत के बाद ऊर्जा मंत्री के रूप में श्रेष्ठ ने अपना कार्यभार संभाला है। जिसके बाद भारतीय राजदूत की नेपाल में उच्च-स्तरीय बैठकों का सिलसिला जारी है।

ऊर्जा सहयोग को मिलेगी गहराई

सूत्रों ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच हुई वार्ता में भारत और नेपाल के द्विपक्षीय संबंधों, साझा हितों से जुड़े मामलों को शामिल किया गया। ऊर्जा-जल संसाधनों के मुद्दे पर सहयोग पर भी इस दौरान ध्यान केंद्रित किया गया है। यह चर्चा मुख्यतः दोनों देशों की दीर्घकालिक साझेदारी, सतत विकास और क्षेत्रीय ► शोष पेज 5 पर

दूरियों में संवाद : पाक के जरिए ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता फिर लड़खड़ाई

ईरान ने कहा- हम सीधी बात नहीं करेंगे यूएस बोला- आमने-सामने करेंगे बात

एजेसी ► इस्लामाबाद
ईरान और अमेरिका एक बार फिर बातचीत के लिए तैयार नजर आ रहे हैं, हालांकि इस बार वे सीधे नहीं बल्कि दूरी बनाए रखते हुए और दूसरे स्तर के प्रतिनिधियों के जरिए संवाद कर सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अपनी टीम के साथ शनिवार को पाकिस्तान के सेना प्रमुख और मध्यस्थता प्रयासों में अहम भूमिका निभाने वाले फ़िल्ड मार्शल असीम मुनीर से मुलाकात की। हालांकि, बातचीत का ब्यौरा जारी नहीं किया। माना जा रहा है कि ईरान ने अपनी शर्तें असीम मुनीर को बता दी हैं। ईरान के विदेश मंत्री के आगमन ► शोष पेज 5 पर

ईरान ने अपनी शर्तें असीम मुनीर को बताई



ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची एवं पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की हुई मुलाकात

► ट्रंप बोले- अमेरिका मजबूत स्थिति में अब ईरान सीधे हमसे संपर्क करे
► ईरान के समुद्री यातायात पर अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहेगी

ट्रंप ने स्टीव वित्कोफ और जेरेड कुशनर का दौरा रद्द किया

इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूत स्टीव वित्कोफ और दामाद जेरेड कुशनर का दौरा रद्द कर दिया। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि इसमें समय बर्बाद हो रहा था। ट्रंप ने ट्यू सोशल पर पोस्ट कर कहा कि इतनी लंबी यात्रा की जरूरत नहीं थी और उनके पास करने के लिए ज्यादा काम है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के नेतृत्व में अहम और अदृश्य खींचतान है। क्योंकि इसका कोई खास फायदा नहीं था। ये दोनों ईरान से बातचीत के लिए इस्लामाबाद जाने वाले थे। ट्रंप ने कहा कि मौजूदा हालात में अमेरिका मजबूत स्थिति में है और हमारे पास सारे पते हैं। ट्रंप के मुताबिक, ईरान जब चाहे अमेरिका से संपर्क कर सकता है। उन्होंने यह भी साफ किया कि अमेरिकी टीम अब पाकिस्तान जाकर खिना नतीजे वाली बातचीत के लिए इंतजार नहीं करेगी। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची पाकिस्तान में बैठकों के बाद इस्लामाबाद से लौट चुके हैं। वहीं, ईरान ने अमेरिका से सीधे बातचीत करने से इनकार कर दिया है।

बेयरबॉक की यात्रा से पहले भारत ने उठाया आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का मुद्दा



हरिभूमि ब्यूरो ► नई दिल्ली

बीते 22 अप्रैल को पहलवाम आतंकवादी हमले की पहली बरसी थी। यह एक ऐसा भयानक आतंकी हमला था। जिसमें पाकिस्तान की शहर पर लश्कर-ए-तैयबा के छद्म आतंकवादी संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (टीआरएफ) ने कुल 26 बेकसूर लोगों (25 भारतीय, 1 नेपाली नागरिक) को मौत के घाट उतार दिया था। यहां एक चौंकाने वाला तथ्य ► शोष पेज 5 पर

हरियाणा की मंडियों में रिकॉर्ड 81 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक हरियाणा में अब किसानों को व्हाट्सएप पर मिलेगा क्यूआर कोड आधारित 'जे-फॉर्म'

सरकार ने खरीद प्रक्रिया को किया ऑनलाइन, बढ़ी पारदर्शिता: नायब

हरिभूमि ब्यूरो ► नई दिल्ली

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में अगले सप्ताह से सभी किसानों को व्हाट्सएप के माध्यम से क्यूआर कोड आधारित जे-फॉर्म भेजे जाएंगे, ताकि किसानों को ऋण



सहित अन्य प्रकार की सुविधा लेने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। मुख्यमंत्री सैनी शनिवार को

हरियाणा निवास चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले सीजन से किसान एप भी लॉन्च किया जाएगा, जिसमें किसानों को जे-फॉर्म, भुगतान की स्थिति, भूमि बुवाई एवं उपज सत्यापन की स्थिति, गेट पास शेड्यूलिंग (अगली सरसों फसल से प्रारंभ), भूमि सत्यापन की स्थिति तथा सभी सूचनाएं 'किसान ई-खरीद एप' में उपलब्ध ► शोष पेज 5 पर

संकट: एच-1बी वीजा पर 3 साल के लिए लगेगी रोक!

पेश किया है। सांसद एली क्रेन द्वारा पेश किए गए इस बिल का मुख्य तर्क यह है कि वर्तमान वीजा व्यवस्था अमेरिकी कामगारों के हितों को नुकसान पहुंचाकर बड़ी कंपनियों के मुनाफे को बढ़ावा दे रही है। इस प्रस्ताव को ब्रैंडन गिल और पॉल गोसर जैसे प्रमुख रिपब्लिकन सांसदों का समर्थन प्राप्त है, जिनका मानना है कि इस प्रणाली का उपयोग सस्ते विदेशी श्रमिकों को लाने के लिए किया जा रहा है। प्रस्तावित बिल में एच-1बी वीजा की वार्षिक संख्या को 65,000 से घटाकर ► शोष पेज 5 पर

हवाई सफर भी जंग की चपेट में 25% से ज्यादा महंगे हुए एयर टिकट, 'फ्यूल सरचार्ज' लागू

नई दिल्ली। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे

तनाव का असर अब भारत के आम नागरिकों की जेब पर भी साफ दिखाई देने लगा है। इस वैश्विक तनाव ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की कीमतें बढ़ा दी हैं। इसका सीधा असर हवाई किराये पर पड़ रहा है। इंडिया और एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस ने लागत बढ़ाने के ► शोष पेज 5 पर

मेरी दिल्ली नशा मुक्त दिल्ली

सुरक्षित, नशा-मुक्त दिल्ली के लिए प्रतिबद्ध

MANAS

नशीले पदार्थों से जुड़ी जानकारी हेतु **24x7 1933**

14446 नशा मुक्ति हेल्पलाइन

वेबसाइट: www.ncbmanas.gov.in | ईमेल: info.ncbmanas@gov.in

नशीले पदार्थों के नेटवर्क के खिलाफ समन्वित कार्यवाही

हृदय प्रतिक्रिया के साथ, एंटी-नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF), क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस, मादक पदार्थों के नेटवर्क पर रोक लगाने और शहर को सुरक्षित रखने के लिए चौबीसों घंटे कार्यरत है।

संचालन संबंधी प्राथमिकताएँ

- एनडीपीएस अधिनियम का कड़ाई से पालन
- खुफिया जानकारी एकत्र करना
- नेटवर्क की पहचान व अवरोधन
- सभी हितधारकों के साथ समन्वय

जमीनी स्तर पर कार्यवाही

- राजधानी में नशीले पदार्थों की आवक पर निगरानी और रोकथाम
- तम्बकों / नशे के सौदागरों एवं संगठित गिरोहों के विच्छेद कार्यवाही
- मादक पदार्थों की खेप को बाज़ार में आने से पहले ही रोकना

नशा मुक्ति के लिए ई-प्रतिज्ञा लें

नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े <https://pledge.mygov.in/fightagainstdrugabuse>

पुलिस आयुक्त, दिल्ली को ई-मेल करें: cpdelhi@delhipolice.gov.in | लिखें: पुलिस आयुक्त, दिल्ली को, पोस्ट बॉक्स नं. 171, जीपीओ, नई दिल्ली पर

@DelhiPoliceOfficial | @DelhiPolice | @delhi.police_official | @DelhiPoliceofficial | @DelhiPoliceYT | delhipolice.nic.in

तुरंत पुलिस सहायता के लिए 112 नम्बर पर कॉल करें | पुलिस को सूचना देने के लिए 14547 पर कॉल करें

14 लोगों को सुरक्षित निकाला

लक्ष्मी नगर स्थित ट्रांसफॉर्मर में आग लगने से कई इमारतें जलकर नष्ट



एजेंसी नई दिल्ली

पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में शुक्रवार देर रात को बिजली के एक ट्रांसफॉर्मर में लगी भीषण आग ने कई आवासीय इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में 14 लोगों को बचाया गया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के अनुसार, रमेश

पार्क स्थित नानक मोटर के पास रात करीब साढ़े 12 बजे आग लगने की सूचना मिली। दमकल की टीम तुरंत मौके पर पहुंची लेकिन आग जल्द और भड़क गई। आग पर काबू पाने के लिए पानी के सात टैंकर और अन्य अग्निशमन वाहनों को तैनात किया गया। अधिकारी ने बताया कि ट्रांसफॉर्मर से आग आसपास की तीन इमारतों में फैल गई, जिससे 14 फ्लैट प्रभावित हुए।

दमकलकर्मियों ने तुरंत बचाव अभियान चलाया और प्रभावित फ्लैट में फंसे सभी 14 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। उन्होंने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। देर रात करीब दो बजे आग पर काबू पा लिया गया, जिसके बाद शीतलन अभियान चलाया गया। आग लगने का सटीक कारण अब तक पता नहीं चल पाया है।

शकूर बस्ती में आग लगने से 100 से अधिक झुगियां जलकर खाक

नई दिल्ली, एजेंसी। उत्तर-पश्चिम दिल्ली के शकूर बस्ती इलाके में भीषण आग लगने से 100 से अधिक झुगियां जलकर खाक हो गईं। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के अनुसार, आग लगने की सूचना शुक्रवार रात 11 बजकर 14 मिनट पर मिली। उसने बताया कि शुरुआत में दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर भेजी गईं और करीब दो एकड़ क्षेत्र में फैली आग पर काबू पाने के लिए बाद में और गाड़ियों को भेजा गया। डीएफएस के एक अधिकारी ने कहा, "झुगियां में इस्तेमाल अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री के कारण आग तेजी से फैल गई। आग पर देर रात करीब 12 बजकर 40 मिनट पर काबू पा लिया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए शीतलन अभियान जारी है कि आग फिर न भड़के।" उन्होंने बताया कि आग लगने के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है।

रोहिणी में चार मंजिला इमारत में आग लगी कोई हताहत नहीं

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-24 इलाके में स्थित चार मंजिला इमारत में आग लग गई, हालांकि इमारत में मौजूद सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के अनुसार, सेक्टर-24 के पॉकेट-20 में शुक्रवार रात आठ बजे कर 54 मिनट पर आग लगने की सूचना मिली थी। अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिलते ही दमकल की छह गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और दमकल कर्मियों ने रात करीब 11 बजे तक आग पर काबू पा लिया। उन्होंने बताया कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। अधिकारियों के अनुसार, आग लगने के कारणों का अब पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक जांचकर्ता के अनुसार आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है, हालांकि गैस प्लंपाइंगन फटने की भी आशंका जताई गई है।

तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से ई-रिक्शा चालक की मौत, पांच लोग घायल



एजेंसी नई दिल्ली

उत्तर-पश्चिम दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें 33 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई और पांच लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना रिंग रोड पर एक अस्पताल के पास शुक्रवार शाम को लगभग छह बजे हुई।

उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच के अनुसार, तेज रफ्तार कार ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे वह पलट गया। पुलिस से एक बयान में कहा, रटक्कर में ई-रिक्शा चालक और कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। कार चालक की पहचान रोहिणी निवासी और जी बी (गोविंद वल्लभ) पंत अस्पताल में वरिष्ठ रेजिडेंट (रेडियोलॉजिस्ट) डॉ. सिद्धार्थ के रूप में हुई है। कार

अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ गिरोह का मंडाफोड़ तीन तस्कर गिरफ्तार

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए तीन तस्करों को गिरफ्तार किया और लगभग 80 लाख रुपये के अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य की 475 ग्राम हेरोइन जब्त की। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी आपूर्तिकर्ता के रूप में काम करते थे, जिनमें से दो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में और एक दिल्ली में स्थित था। उन्होंने बताया कि गाजीपुर इलाके में स्मैक की आपूर्ति में शामिल मोहम्मद आरिफ के बारे में मिली विशिष्ट जानकारी के बाद पुलिस को सफलता मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने एनएच-24 के पास जाल बिछाया और आरिफ को 270 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी ने बताया, रपूछताछ के दौरान, आरिफ ने अपने आपूर्तिकर्ताओं अमित और विकास के नाम बताए, दोनों शाहजहांपुर के निवासी हैं। सूचना के आधार पर, पुलिस टीम ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर में छापेमारी की, पुलिस टीम ने दोनों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 205 ग्राम हेरोइन बरामद की। पुलिस ने बताया कि आरोपी एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा थे जो आर्थिक लाभ के लिए बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ की आपूर्ति करते थे।

अदालत ने भाई की हत्या के आरोपी को किया बरी



एजेंसी नई दिल्ली

दिल्ली की एक अदालत ने नंद नगरी इलाके में 2022 में अपने छोटे भाई की हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को यह कहते हुए बरी कर दिया कि आरोप साबित करने में विफल रहा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुमार रजत हत्या के मामले में आरोपी रोहित के खिलाफ सुनवाई कर रहे थे। न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष के प्रमुख गवाहों ने मुकदमे के दौरान सहयोग नहीं किया और वे अदालत के समक्ष उसे हमलावर के रूप में पहचानने में

विफल रहे। अदालत ने 24 अप्रैल के एक आदेश में कहा कि सबूतों के माध्यम से रिपोर्ट पर लायूंग एफ सी टी के आधार पर यह पाया गया है कि अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में आरोपी रोहित के खिलाफ संदेह से परे अपना मामला साबित करने में विफल रहा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोप है कि 17 सितंबर, 2022 को घर पर हुए झगड़े के बाद रोहित ने अपने भाई यश पर कैंची से हमला किया था। यश को बाद में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

लोकतांत्रिक सहभागिता : छात्रों के लिए हर शनिवार खुलेगा विधानसभा परिसर



दिल्ली विधानसभा में 'साप्ताहिक यूथ आउटरीच कार्यक्रम' का शुभारंभ

हरिभूमि नई दिल्ली

लोकतांत्रिक सहभागिता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दिल्ली विधानसभा ने शनिवार को 'साप्ताहिक यूथ आउटरीच कार्यक्रम' का शुभारंभ किया। यह पहल विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के मार्गदर्शन में प्रारंभ की गई, जिसकी शुरुआत महापौर वाल्मीकि

कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गीता कॉलोनी के 75 विद्यार्थियों के प्रथम के विधानसभा भ्रमण से हुई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब प्रत्येक शनिवार को विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी दिल्ली विधानसभा का दौरा करेंगे, जिससे उन्हें विधायी कार्यपाली का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उनकी समझ को सुदृढ़ किया जा सकेगा। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को दिल्ली विधानसभा के ऐतिहासिक विकास से अवगत

युवा वर्ग को मिलेगा अवसर, कानून कैसे बनाए जाते हैं : गुप्ता

'यूथ आउटरीच कार्यक्रम' की घोषणा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह पहल नागरिकों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच की दूरी को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से युवा वर्ग को यह समझने का अवसर मिलेगा कि कानून कैसे बनाए जाते हैं और सार्वजनिक जीवन तथा लोकतांत्रिक शासन किन मूल सिद्धांतों पर आधारित है।

इतिहास पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री का भी हुआ प्रदर्शन

कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को विधायी प्रक्रियाओं एवं संस्थागत कार्यपाली पर एक संरचित परिचय सत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर 'एक शताब्दी यात्रा' नामक स्मारक कॉपी टेबल पुस्तक भेंट की गई तथा पद्म भूषण से सम्मानित अमिताभ अनुभव खेर की आवाज में तैयार विधानसभा के संस्थागत इतिहास पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन भी किया गया। इसके अतिरिक्त, छात्रों को विधानसभा भवन का मार्गदर्शित भ्रमण कराया गया, जिससे उन्हें कार्यपाली का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुआ।

कराया गया। उन्हें बताया गया कि वर्तमान विधानसभा भवन का निर्माण वर्ष 1912 में हुआ था, जो पूर्व में केंद्रीय विधान सभा का स्थल रहा है। साथ ही, विट्ठलभाई पटेल की ऐतिहासिक विरासत का उल्लेख करते हुए यह भी रेखांकित किया गया कि वर्ष 1993 में पुनः स्थापना के बाद से दिल्ली विधानसभा लोकतांत्रिक शासन के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य कर रही है।

रोहिणी मेट्रो स्टेशन पर बम की धमकी मरी कॉल अफवाह निकली, एक व्यक्ति लिया हिरासत में

नई दिल्ली, एजेंसी। रोहिणी सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन पर शनिवार शाम बम की धमकी वाले एक फोन कॉल से सुरक्षा को लेकर हड़कंप मच गया, लेकिन गहन जांच के बाद कोई भी सख्त वस्तु नहीं मिली। पुलिस ने यह जानकारी दी। दिल्ली पुलिस के अनुसार, मेट्रो स्टेशन पर बम होने की आशंका के संबंध में शाम लगभग 5:30 बजे सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ते के जवान केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और परिसर को व्यापक तलाशी ली। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, रजाव के दौरान कुछ भी सख्त नहीं मिला।

जांच के दौरान पुलिस ने फर्जी कॉल करने के संदेह में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। अधिकारी के अनुसार, प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है। पुलिस ने बताया कि स्थिति पर तुरंत काबू पा लिया गया और मेट्रो स्टेशन पर सामान्य परिचालन बिना किसी बाधा के जारी रहा।

क्षेत्रवासियों की समस्याओं को हल करें अधिकारी : संदीप

हरिभूमि नई दिल्ली

क्षेत्रवासियों की समस्याओं का जल्द से जल्द और स्थायी समाधान दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है और निवासियों की समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए। मटियाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक संदीप सहारावत ने शनिवार को दीनपुर गांव और दीनपुर-गोयला रोड का निरीक्षण करने के दौरान अधिकारियों को यह



निर्देश दिए। विधायक ने इस मार्ग से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को

लोक निर्माण विभाग और एमसीडी अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण

अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा नेता पवन शर्मा और क्षेत्र के स्थानीय निवासी भी उपस्थित रहे। सभी के साथ मिलकर क्षेत्र की समस्याओं का विस्तार से जायजा लिया गया और उनके शीघ्र समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

कार्यालयों के चक्कर काटते रहे परिजन, आधी पेंशन अब भी लंबित

समाज कल्याण विभाग ने दिया दखल तो सौ प्रतिशत दिव्यांग को मिली बंद पेंशन

दया राम नई दिल्ली

दिल्ली हरिभूमि 3

100 प्रतिशत दिव्यांग को पेंशन से वंचित कर रहा सरकारी सिस्टम

संविधान के अंतर्गत ही है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने जल्द से जल्द पेंशन से वंचित दिव्यांगों को पेंशन से वंचित कर रहा सरकारी सिस्टम को ठीक करने में मदद करने का प्रयास किया है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने जल्द से जल्द पेंशन से वंचित दिव्यांगों को पेंशन से वंचित कर रहा सरकारी सिस्टम को ठीक करने में मदद करने का प्रयास किया है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने जल्द से जल्द पेंशन से वंचित दिव्यांगों को पेंशन से वंचित कर रहा सरकारी सिस्टम को ठीक करने में मदद करने का प्रयास किया है।

लंबे समय से पेंशन बहाली के लिए थे परेशान

दिव्यांग के पिता ने बताया कि वे लंबे समय से पेंशन बहाली के लिए परेशान थे, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हरिभूमि में प्रकृता से खबर छपने के बाद ही अधिकारियों ने स्थिति का संज्ञान लिया। हालांकि, अभी भी करीब छह महीने की पेंशन लंबित बताई जा रही है, जिससे परिवार की आर्थिक मुश्किलें पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं।

अधिकारियों ने जिम्मेदारी निभाई होती तो दिव्यांग को नहीं होती परेशानी

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मामला दिल्ली सरकार के संबंधित विभागों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यदि समय रहते अधिकारियों ने जिम्मेदारी निभाई होती, तो एक दिव्यांग और उसका परिवार इस तरह परेशान नहीं होता। सवाल यह भी है कि क्या आम नागरिक को अपनी बुनियादी हक की सुविधाएं पाने के लिए मीडिया का सहारा लेना ही पड़ेगा? नागरिकों का कहना है कि सरकार और संबंधित विभाग ऐसे मामलों में संवेदनशीलता दिखाएं और समयबद्ध तरीके से समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें, ताकि कमजोर वर्गों को अपने अधिकारों के लिए भटकना न पड़े।

पड़ा और थक हार कर मीडिया का सहारा लेना

पड़ा। दिव्यांग की हालत देखने के बाद हर कोई कह रहा है कि सरकार को चलाने वाले लोग

कहना है कि बार-बार प्रशासन से सभी दस्तावेज दिखाए और गृहार लगाने के बावजूद अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। हालात तब बदले जब हरिभूमि समाचार पत्र में इस मुद्दे को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। खबर सामने आते ही प्रशासन हरकत में आया और दिव्यांग व्यक्ति की एक साल की पेंशन जारी कर दी गई। वहीं, क्षेत्रीय एसडीएम का कहना है कि संबंधित विभाग को लंबित पेंशन के बारे में निर्देशित किया गया है और संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी कर दी जाएगी।

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 देखिए मेरे समक्ष परिवार दिया गया है कि नाम: ओमतोष गंगे श्रीवास्तव, पुत्र: शंभु शरण श्रीवास्तव, निवासी: सी-69, जेबीटीएस मार्ग, चण्डीपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली ने अपराध किया है (या किए जाने का संदेह है) इसके विरुद्ध FIR No.148/2020 U/s 188 IPC & 332/461 DMC ACT के तहत एक मामला थाना मैदान गढ़ी, दक्षिण जिला, नई दिल्ली में दर्ज किया गया है और उसके बाद जारी गिरफ्तारी वारंट को यह कहते हुए वापस कर दिया गया कि अभियुक्त ओमतोष गंगे श्रीवास्तव नहीं मिला या मेरी संतुष्टि के लिए दिखाया गया है कि अभियुक्त ओमतोष गंगे श्रीवास्तव फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा है कि FIR No.148/2020 U/s 188 IPC & 332/461 DMC ACT, थाना मैदान गढ़ी, दक्षिण जिला, नई दिल्ली के अभियुक्त उक्त ओमतोष गंगे श्रीवास्तव को उक्त परिवार का जवाब देने के लिए दिनांक 03.06.2026 को या उससे पहले अदालत के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है। आदेशानुसार, श्री आशीष कुमार मीना न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी-01 (दक्षिण) कमरा संख्या 214, साकेत कोर्ट, नई दिल्ली

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr.P.C. देखिए मेरे समक्ष परिवार दिया गया है कि अभियुक्त मुकेश उर्फ मुंगेरी, पुत्र: हरनाम सिंह, पता: 28 / 129, कस्तूरबा नगर, दिल्ली ने FIR No.97/2020, U/s 392/411/34 IPC, पुलिस थाना विवेक विहार, दिल्ली के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त मुकेश उर्फ मुंगेरी मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त मुकेश उर्फ मुंगेरी फरार हो गया है (या उक्त वारंट कि तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि FIR No. 97/2020, U/s 392/411/34 IPC, पुलिस थाना विवेक विहार, दिल्ली के अभियुक्त मुकेश उर्फ मुंगेरी से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवार का उत्तर देने के लिए दिनांक 04.06.2026 को या इससे पहले हाजिर हो। आदेशानुसार - श्री मोहित शर्मा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शाहदरा जिला, कमरा नं. 59, तीसरी मंजिल कड़कड़बूंगा कोर्ट, दिल्ली DP/5363/SHD/2026

अंडरपास और सड़क परियोजना के बावजूद कब्रों से बाधित है आवागमन

शालीमार बाग में हटेंगे 140 से अधिक अवैध निर्माण, मिलेगी राहत : रेखा गुप्ता

- शालीमार बाग हादसे पर सीएम रेखा गुप्ता ने बताया गहरा दुःख
- मुख्यमंत्री ने सड़कों पर अवैध कब्रों को बताया बड़ा कारण

हरिभूमि न्यूज ►► नई दिल्ली



दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके आधार पर अवैध निर्माणों को हटाने का आदेश पारित किया गया। उन्होंने कहा कि इन कब्रों को हटाए जाने के बाद उत्तरी दिल्ली से आने-जाने वाला यातायात अधिक सुगम होगा और वाहन सौधे रिंग रोड से आउटर रिंग रोड तक पहुंच सकेंगे।

से आजादपुर से आने वाला यातायात इस मार्ग से होकर सीधे आउटर रिंग रोड, मुकरबा चौक तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में दो बड़े अस्पताल, कई

शैक्षिक संस्थान और पुलिस से संबंधित संस्थान स्थित हैं, जिसके कारण यहां यातायात का दबाव अधिक रहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध कब्रों के कारण न

दो माह पहले भी हुई थी एक पांच वर्षीय बालिका की मृत्यु

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार शाम शालीमार बाग क्षेत्र में हुई एक सड़क दुर्घटना में नाबालिग की मौत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यदि इस इलाके में सड़क किनारे अवैध कब्रें न होते, तो यातायात सुचारु रूप से चलता और इस प्रकार की दुर्घटनाओं तथा जान-माल के नुकसान की आशंका कम होती। लगभग दो माह पहले इसी क्षेत्र में एक तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आकर एक पांच वर्षीय बालिका की मृत्यु हो गई थी, जो इस इलाके में यातायात व्यवस्था की गंभीर स्थिति को दर्शाता है।

अवैध कब्रें न हों, तो टाला जा सकता था यह हादसा

मुख्यमंत्री कार्यालय का कहना है कि शालीमार बाग पुलिस के अनुसार शनिवार शाम मोटरसाइकिल पर सवार दो नाबालिग उस क्षेत्र से गुजर रहे थे, जहां नाले और सड़क किनारे अवैध कब्रें किए गए हैं। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने इन कब्रों को हटाने का आदेश भी दिया है। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक टेम्पो ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे एक नाबालिग की मौत पर ही मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री ने अंबेडकर नगर, हैदरपुर निवासी मृतक नाबालिग के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि यदि सड़क किनारे अवैध कब्रें न होते, तो यह हादसा टाला जा सकता था। उन्होंने कहा कि ये कब्रें पूर्ण सरकार के समय सरकारी भूमि पर किए गए थे, जिससे लंबे समय से यातायात बाधित हो रहा है और लोगों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

केवल स्थानीय निवासी, बल्कि राहगीर भी लंबे समय से परेशान यहां से गुजरने वाले वाहन और हैं।

31 साल पुराने अपहरण-हत्या मामले में यूट्यूबर गिरफ्तार

एजेंसी ►► नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस ने 31 साल पुराने अपहरण व हत्या के एक मामले के शिलसिले में स्थानीय स्तर पर एक सामाजिक कार्यकर्ता और यूट्यूबर के रूप में पहचान बना चुके 54 वर्षीय एक व्यक्ति को शनिवार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहचान बदलकर यहां रह रहा था।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान सलीम खान उर्फ सलीम अहमद के रूप में हुई है और उसे सलीम वास्तिक के नाम से भी जाना जाता है। पुलिस ने बताया कि वास्तिक को अपराध शाखा की एक टीम ने उत्तर प्रदेश के लौनी से गिरफ्तार किया।

पुलिस के मुताबिक, वह 2000 में मिली अंतरिम जमानत का उल्लंघन करने के बाद दो दशकों से अधिक समय से गिरफ्तारी से बच रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी को 1997 में उसके साथी अनिल के साथ उत्तर-पूर्वी दिल्ली में एक सीमेंट व्यापारी की 13 वर्षीय पुत्री की अपहरण के बाद हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, रजनवरी 1995 में स्कूल जाते समय लड़के का अपहरण कर लिया गया था और उसकी रिहाई के बदले 30,000 रुपये की फिरोती मांगी गई

पहचान बदल कर रह रहा था आरोपी

थी। अधिकारी ने बताया कि पीड़ित के पिता को अपहरणकर्ताओं का फोन आया था, जिन्होंने उन्हें लौनी पलाईओवर के पास एक बस स्टैंड पर फिरोती की रकम देने को कहा था। उन्होंने बताया कि फोन करने वाले ने उन्हें पुलिस को सूचना न देने की चेतावनी भी दी थी।

अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच के दौरान शक सलीम खान पर गया, जो उस समय लड़के के स्कूल में माशेल आर्ट प्रशिक्षक के रूप में काम कर रहा था। पुलिस की एक टीम ने उससे पूछताछ की और उसके खुलासे के आधार पर दिल्ली के नुरतफाबाद के पास एक नाले से लड़के का शव बरामद किया।

अधिकारी के अनुसार, सह-आरोपी अनिल की पहचान बाद में हुई और उसने फरवरी 1995 में अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। दिल्ली के एक सत्र न्यायालय ने मुकदमे की सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनौती दी।

अपील लंबित रहने के दौरान सलीम खान को नवंबर 2000 में अंतरिम जमानत दी गई लेकिन उसके बाद उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। उच्च न्यायालय ने उसकी

सजा को बरकरार रखा।

अधिकारी ने बताया कि जमानत पर रिहा होने के बाद सलीम खान हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बार-बार अपना ठिकाना बदलकर कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचता रहा। बताया जाता है कि वह करनाल और अंबाला जैसी जगहों पर अलमारी बनाने का काम करता था और लगभग 2010 में लौनी में स्थायी रूप से बस गया। सलीम खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सरकारी रिकॉर्ड भी हटाए और कथित तौर पर मृत घोषित कर दिया और सलीम वास्तिक या सलीम अहमद के नाम से एक नई पहचान अपना ली। इस पहचान के तहत वह महिलाओं के कपड़ों व अन्य सामान की दुकान चलाता था और सोशल मीडिया मंच पर भी सक्रिय हो गया, जहां उसने खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचाना और पेश किया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में सफलता उस समय मिली जब अपराध शाखा की एक टीम को सूचना मिली, जिसका इस्तेमाल आरोपी खान की पुरानी तस्वीरों और फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड के जरिए उसकी पहचान सत्यापित करने के लिए किया गया। पुलिस के मुताबिक, लौनी की स्थानीय पुलिस की सहायता से एक टीम ने अभियान को अंजाम दिया और 31 साल पुराने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

दूसरे दिन भी एफसीआई केंद्र पर फसल लेकर नहीं आए किसान

हरिभूमि न्यूज ►► नई दिल्ली

गेहूं खरीद को लेकर सरकारी तैयारी की कमी एक बार फिर सामने आई है। नरेंद्रा स्थित भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) परिसर में लगातार दूसरे दिन भी कोई किसान अपनी फसल लेकर नहीं पहुंचा, जिससे खरीद प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार, मौसम की अनिश्चितता के बावजूद दिल्ली सरकार समय रहते गेहूं खरीद की उचित व्यवस्था नहीं कर पाई। परिणामस्वरूप, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एसएमएसपी) 2585 रुपये प्रति क्विंटल पर दिल्ली देहात के किसानों से खरीद शुरू नहीं हो सकी। इस देरी का खासियत किसानों को उठाना पड़ा, जिन्हें अपनी फसल खराब होने के डर से अनाज मंडियों में आने-पौने दामों पर बेचनी पड़ी।

किसानों ने सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि समय पर खरीद केंद्र सक्रिय हो जाते, तो उन्हें नुकसान नहीं उठाना पड़ता।



बढ़ते दबाव और आलोचना के बाद दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर गेहूं खरीद शुरू करने की अनुमति मांगी, लेकिन तब तक अधिकांश किसान अपनी उपज बेच चुके थे।

16 करोड़ रुपये के साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क का किया भंडाफोड़

एजेंसी ►► नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस ने 'म्यूल' बैंक खातों और मुखौटा कंपनियों से जुड़े साइबर धोखाधड़ी को बहावा देने वाले एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है और आठ दिनों के भीतर 16 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन का पता लगाने के बाद दो फर्जी निदेशकों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। 'म्यूल' बैंक खाते ऐसे बैंक खाते होते हैं, जिन्हें दूसरों के नाम से खुलवाया जाता है और जिन्का इस्तेमाल अवैध तरीके से अर्जित धन के लेनदेन के लिए किया जाता है। उन्होंने बताया



कि आरोपी सोनू कुमार और अमिंदर सिंह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फर्जी निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। ऐसा पाया गया कि यह कंपनी धनशोधन के केंद्र में थी। यह मामला राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर चिह्नित संदिग्ध 'म्यूल'

दो फर्जी निदेशक गिरफ्तार

यह कई राश्यों में साइबर धोखाधड़ी की 336 शिकायतों से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने बताया कि खातों में असामान्य गतिविधि देखी गई और इसका इस्तेमाल धन के लेन-देन के विभिन्न स्तरों पर किया गया। विस्तृत वित्तीय विश्लेषण से पता चला कि आठ दिनों के भीतर खातों के माध्यम से 16 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन किया गया, जो बड़े पैमाने पर धनशोधन का संकेत देता है। पुलिस ने बताया कि नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान और उन्हें पकड़ने के लिए जांच जारी है।

केवल उपाधियां नहीं, शिक्षा के साथ चरित्र ही 2047 के भारत को देगा दिशा : विजेन्द्र गुप्ता



हरिभूमि न्यूज ►► नई दिल्ली

“विकसित भारत केवल उपाधियों से नहीं बन सकता, इसके लिए शिक्षा के साथ-साथ सुदृढ़ चरित्र की भी आवश्यकता है। शिक्षा हमें मार्ग दिखाती है, जबकि चरित्र उस मार्ग पर दृढ़ता है, जबकि चरित्र उस मार्ग पर चलने की शक्ति देता है।” दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने शनिवार को पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज (प्रा.:), दिल्ली विश्वविद्यालय के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि यह संबोधन दिया।

वास्तविक शिक्षा मनुष्य के भीतर के मानव को करती है जागृत

गुप्ता ने कहा कि पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं, बल्कि महर्षि दयानंद सरस्वती की वैचारिक विरासत का जीवंत प्रतीक है, जिनकी मूल्यों की ओर लौटने की प्रेरणा आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के भीतर निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना है, और वास्तविक शिक्षा वही है जो मनुष्य के भीतर के मानव को जागृत करे।

उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे मूल्यों पर आधारित “विकसित भारत” के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएं। यह कार्यक्रम नेहरू नगर स्थित कॉलेज के नये सभागार में आयोजित किया गया। अपने संबोधन में विधानसभा अध्यक्ष गुप्ता ने कहा कि जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब देश की जिम्मेदारी आज के युवाओं के कंधों पर होगी। छात्रों को प्रेरित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष गुप्ता ने कहा कि उन्हें बड़े सपने देखने चाहिए, लेकिन अपनी जड़ों को मजबूत बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि

असफलता से नहीं, बल्कि बेईमानी से डरना चाहिए; असफलता हमें सिखाती है, जबकि बेईमानी जीवनभर साथ रहती है। उन्होंने मातृभाषा, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति गर्व की भावना को भी आवश्यक बताया और कहा कि जो अपनी जड़ों को भूल जाता है, वह स्थिर नहीं रह सकता। कार्यक्रम में अजय सूरि (अध्यक्ष, प्रबंधन समिति, पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज), प्रो. संजीव कुमार तिवारी (प्राचार्य, महाराजा अग्रसेन कॉलेज) तथा प्रो. देवेंद्र कुमार (प्राचार्य, पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज) सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।

जहांगीरपुरी में कबाड़ में भीषण आग : गुलाब सिंह



हरिभूमि न्यूज ►► नई दिल्ली

दिल्ली नगर निगम के सिविल लाइन जोन के अंतर्गत आने वाले जहांगीरपुरी वार्ड-15 में मजालिस पार्क मेट्रो स्टेशन के निकट एमसीडी फ्लैटों के पीछे कबाड़ में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। सिविल लाइंस जोन के चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर ने शनिवार को सांशाल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने अपने सभी निर्धारित कार्यक्रम स्थगित कर

समय रहते आग पर पाया काबू, कोई जनहानि नहीं

तुरंत घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों और दमकल विभाग से संपर्क कर स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मियों के लगातार प्रयासों से आग पर काबू पा लिया गया। गंभीरता रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि, आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। राठौर ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें और प्रशासन का सहयोग करें, ताकि ऐसे हादसों से समय रहते निपटा जा सके।

एमसीडी ने साइक्लोथॉन का किया आयोजन

करोल बाग जोन : स्वच्छ-हरित दिल्ली मिशन को दिया बहावा

हरिभूमि न्यूज ►► नई दिल्ली

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने शनिवार को करोल बाग जोन में 8 किलोमीटर लंबी साइक्लोथॉन का आयोजन किया, जिससे नागरिकों एवं नगर निगम कर्मियों के बीच फिटनेस को बढ़ावा देने तथा स्वच्छ एवं हरित दिल्ली मिशन को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। निगम प्रशासन ने शनिवार को यह जानकारी दी। प्रशासन ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करना और स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना था। इसी दौरान निर्धारित मार्ग पर विशेष स्वच्छता अभियान भी चलाया गया, जो दिल्ली नगर निगम के नागरिक सहभागिता और जिम्मेदारी के प्रति के समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है। जोन के उपायुक्त दिलखुशा मीणा ने राजेंद्र नगर से हरी झंडी दिखाकर साइक्लोथॉन का शुभारंभ किया। दिलखुशा मीणा ने ऐसे आयोजनों के महत्व पर बल दिया, जो सामुदायिक भागीदारी और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ाते



हैं। इस आयोजन में बड़ी संख्या में उत्साही नागरिकों और निगम कर्मचारियों ने भाग लिया। उनकी सहभागिता और ऊर्जा ने शहर में फिटनेस और स्वच्छता अभियानों के प्रति बढ़ती जागरूकता और समर्थन को प्रदर्शित किया। शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का बना माध्यम निगम प्रशासन के अनुसार यह साइक्लोथॉन न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का माध्यम बना, बल्कि स्वच्छ और हरित शहरी वातावरण बनाए रखने के संदेश को भी सुदृढ़ करने का एक मंच साबित हुआ। दिल्ली नगर निगम में भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजनों को जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, ताकि जनभागीदारी के माध्यम से एक स्वस्थ, स्वच्छ और सतत दिल्ली का निर्माण किया जा सके।

स्वच्छता कर्मियों को सम्मानजनक जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है दिल्ली सरकार : इन्द्राज

हरिभूमि न्यूज ►► नई दिल्ली

दिल्ली सरकार स्वच्छता कर्मियों के जीवन में ठोस सुधार लाने, उनके कार्यस्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। चंडीगढ़ में आयोजित तीन दिवसीय ‘चिंतन शिविर’ के अंतर्गत समाज कल्याण, ससी/एसटी/ओबीसी कल्याण, सहकारिता एवं चुनाव मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस चिंतन शिविर में साझा किए गए अनुभव और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां दिल्ली में



नीतियों को और अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। शनिवार को आयोजित

सत्रों में छात्रवृत्ति वितरण एवं शिक्षा तक पहुंच, नशा मुक्त भारत इकोसिस्टम, स्वच्छता कार्य में

‘स्माइल-बेगरी सर्वे मोबाइल एप्लिकेशन’ का किया शुभारंभ

मंत्री के अनुसार इस दौरान चिंतन शिविर में प्रौद्योगिकी आधारित पहलों पर भी विशेष जोर दिया गया। ‘स्माइल-बेगरी सर्वे मोबाइल एप्लिकेशन’ का शुभारंभ किया गया, जो शिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के सर्वेक्षण, पुनर्वास और निगरानी को डिजिटल रूप से सशक्त करेगा। मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने कहा कि इस प्रकार की डिजिटल पहलें दिल्ली में भी लागू की जाएंगी, जिससे आश्रय गृहों, पुनर्वास केंद्रों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की कारगरिता, निगरानी और प्रभावशीलता में उल्लेखनीय सुधार होगा।

आश्रय गृहों के लिए जारी किए गए आदर्श दिशानिर्देश

मंत्री रविन्द्र ने कहा कि मित्राचार्यों, आश्रय गृहों के लिए जारी किए गए आदर्श दिशानिर्देश दिल्ली में मानवीय और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने को दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। इन दिशानिर्देशों के तहत स्वच्छता, पोषण, कोशल विकास, कानूनी सहायता और सामाजिक पुनर्वास जैसे क्षेत्रों में समग्र सुधार सुनिश्चित किया जाएगा। रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार इन सभी सुझावों और रणनीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करेगी, जिससे योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और ‘अन्नोदय’ के लक्ष्य को साकार किया जा सके।

‘संवाद से ही संबंध, संस्कार और समाधान लेते हैं जन्म’

हरिभूमि न्यूज ►► नई दिल्ली

संवाद से ही संबंध, संस्कार और समाधान जन्म लेते हैं। विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर द्वारका स्थित साहित्य परिक्रमा कार्यालय में ‘पंच परिवर्तन’ पुस्तक पर एक चर्चा के आयोजन पर अखिल भारतीय साहित्य परिषद में संगठन मंत्री एवं मुख्य वक्ता मनोज कुमार ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक केवल भारत ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के कल्याण की सोच प्रस्तुत करती है। उन्होंने परिवार में संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि परिवार में संवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं, अदिति महाविद्यालय की छात्रा श्वेता सिंह ने पंच परिवर्तन पुस्तक में वर्णित स्व-बोध के लिए छह “भ” और स्वदेश का मंत्र- भाषा, भूषा, भजन, भवन, भोजन, भ्रमण पर विस्तार से चर्चा की। साहित्य परिक्रमा टोली द्वारा

आयोजित इस कार्यक्रम में साहित्यकारों, शिक्षाविदों, विचारकों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में मुकुल कानितकर द्वारा लिखित तथा सुरेश्वर प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक ‘पंच परिवर्तन’ पर आयोजित चर्चा में परिवार, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रीय कर्तव्य और स्व-बोध जैसे पाँच प्रमुख विषयों पर गंभीर एवं सार्थक विमर्श हुआ। चर्चा का केंद्रीय भाव सकारात्मक बदलाव पर आधारित रहा, जिसमें वैश्विक और मानवीय दृष्टिकोण को प्रमुखता दी गई।



खबर संक्षेप

हत्या के मामले में फरार चल रहे बाप बेटा गिरफ्तार

फरीदाबाद। क्राइम ब्रांच सेक्टर-30 की टीम ने थाना शहर बल्लभगढ़ के अंतर्गत हत्या के एक पुराने मामले में 10-12 साल से फरार चल रहे बाप लाल सिंह व बेटा कृष्ण उर्फ कारे को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 जुलाई 2012 को थाना शहर बल्लभगढ़ के अंतर्गत चावला कॉलोनी में विजेन्द्र सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

सट्टा खाई करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

फरीदाबाद। विगत 24 मार्च को क्राइम ब्रांच बॉर्डर की टीम ने थाना सराय खवाजा क्षेत्र के अंतर्गत सट्टा खाई करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 24 अप्रैल को क्राइम ब्रांच बॉर्डर की टीम को गुप्त सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि बाईपास रोड यूनिवर्सल अस्पताल के नजदीक सट्टा खाई की जा रही है अमित गुप्ता व शिवम निवासी मौलापुर दिल्ली को यूनिवर्सल अस्पताल के पास से 25350 रूपए सहित काबू किया गया।

गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 24 अप्रैल को क्राइम ब्रांच बॉर्डर की टीम को गुप्त सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि बाईपास रोड यूनिवर्सल अस्पताल के नजदीक सट्टा खाई की जा रही है अमित गुप्ता व शिवम निवासी मौलापुर दिल्ली को यूनिवर्सल अस्पताल के पास से 25350 रूपए सहित काबू किया गया।

जिला अध्यक्ष आसिफ सैफी पर जानलेवा हमला

गाजियाबाद। पिछले चार दिनों से यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद को लेकर चल रहा विवाद शनिवार अचानक हिंसक हो गया। गाजियाबाद यूथ कांग्रेस के निर्वाचित जिला अध्यक्ष आसिफ सैफी पर शुक्रवार की देर शाम जानलेवा हमला किए जाने की घटना से पूरे जिले की राजनीति में सनसनी फैल गई। अध्यक्ष आसिफ सैफी का कहना है कि शाम को वह अपने घर की ओर जा रहे थे। स्थित एलटी चौक पर तीन गाड़ियों में सवार होकर आए कुछ बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। हमलावरों ने बेसबॉल बैट, धारदार हथियारों और अन्य घातक साधनों से उन पर हमला कर दिया।

आवंटियों के हित में अच्छा अवसर

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप संचालित वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना का लाभ ले रहे हैं। अभी तक लगभग 300 आवंटी ओटीएस के लिए आवेदन कर चुके हैं। जीडीए के सचिव विवेक मिश्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई यह विशेष ओटीएस योजना उन आवंटियों के हित में एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिन पर विभिन्न प्रकार के बकाया (जैसे—भूखण्ड/आवास की किराये, ब्याज, दंड शुल्क आदि) लंबित हैं। इस योजना के अंतर्गत आवंटियों को अधिभार एवं दंड में छूट प्रदान करते हुए एकमुश्त भुगतान के माध्यम से बकाया निस्तारण का सरल एवं लाभकारी विकल्प दिया गया है। इससे न केवल आवंटियों को आर्थिक राहत मिलती है, बल्कि उनकी संपत्तियों का वैधानिक स्थिति में नियमितकरण भी सुनिश्चित होता है। उन्होंने बताया कि

जन स्नेह के बीच जन्मदिवस पर विपुल गोयल ने दिया हरित और विकसित फरीदाबाद का संकल्प

खास बातें

■ मंत्री ने स्कूल की छात्राओं के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया

■ बच्चियों के साथ आत्मीय संवाद भी किया

■ उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं

हवन-पूजन, भोजन-प्रसाद वितरण और जरूरतमंदों को राहत सामग्री देकर मनाया जन्मदिवस

हरिभूमि न्यूज ▶▶ फरीदाबाद

कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के जन्मदिवस के पावन अवसर पर सेक्टर 12 स्थित सेंट्रल पार्क लॉन एवं बैंकवेट हॉल में भव्य और गरिमामयी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधि विधान के साथ हवन पूजन संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्र की सुख समृद्धि और लोककल्याण की कामना की गई। इसके पश्चात भोजन प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर मंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस विशेष अवसर पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने स्कूल की बच्चियों के साथ केक काटकर अपना जन्मदिवस मनाया। इस दौरान बच्चियों के साथ आत्मीय संवाद भी किया गया और उन्हें उज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गईं। इस अवसर पर अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि उन्होंने हवन पूजन के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना की

है कि फरीदाबाद और हरियाणा निरंतर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ें और विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दें। उन्होंने कहा कि जन स्नेह और जनविश्वास ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है और यही उन्हें लगातार जनसेवा के लिए प्रेरित करता है। हजारों लोग पौधारोपण कर रहे हैं और सेवा कार्यों में भाग ले रहे हैं। कई लोग पौधा लगाकर यह संकल्प भी ले रहे हैं कि वे 3 साल तक उसका लालन पालन भी करेंगे। उन्होंने इस सराहनीय पहल के लिए सभी का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने आगे पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर बल देते हुए कहा कि आज के समय में एनसीआर क्षेत्र में पर्यावरण को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों में लोगों की भागीदारी से किए गए पौधारोपण के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और फरीदाबाद के वायु गुणवत्ता सूचकांक में



सुधार दर्ज किया गया है। मंत्री जी ने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने जीवन के हर शुभ अवसर पर पौधारोपण जरूर करें और उसके संरक्षण का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि पौधा लगाना ही नहीं बल्कि उसका सही तरीके से पालन करना भी जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिल सके। उन्होंने हरियाणा सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा फरीदाबाद के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता के सहयोग से फरीदाबाद विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। जन्मदिवस के इस अवसर पर सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे जरूरतमंद लोगों के बीच भारी

मात्रा में उपयोगी वस्तुओं का वितरण भी किया गया। इस दौरान गर्मी से बचाव के लिए छत्ररियां और पानी की बोतलें दी गईं। साथ ही आने वाले बारिश के मौसम को देखते हुए रेनकोट, जैकेट और साथ में जूट के बैग भी वितरित किए गए। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि वे फरीदाबाद की जनता के प्रेम और विश्वास के लिए आभारी हैं और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक जनसेवा के लिए समर्पित रहेंगे। उन्होंने कहा कि जनता का यह स्नेह ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है जो उन्हें लगातार काम करने की प्रेरणा देता है। अंत में उन्होंने सभी उपस्थित लोगों और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके प्रेम और शुभकामनाओं ने इस दिन को यादगार बना दिया। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि सभी स्वस्थ रहें और मिलकर एक विकसित, स्वच्छ और हरित फरीदाबाद का निर्माण करें। इस अवसर पर समर्थकों का तांता लगा रहा और सभी ने उत्साह के साथ कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के जन्मदिवस समारोह में भाग लेकर इस दिन को यादगार बना दिया।

नीलम चौक तक विशाल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी, प्रदर्शन किया

नग्न कर्मियों ने गैर बराबरी व भेदभाव का आरोप लगाया

निगम कर्मचारियों का दूसरे दिन भी जारी रहा झाड़ू प्रदर्शन

- आरोप-सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आर्थिक व सामाजिक कमजोर करने का काम किया
- निगम कर्मचारी 27 अप्रैल से 2 दिन की क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे

हरिभूमि न्यूज ▶▶ फरीदाबाद

नगर निगम कर्मचारियों ने शनिवार को दूसरे दिन भी जोरदार झाड़ू प्रदर्शन करते हुए बीके चौक से नीलम चौक तक विशाल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की प्रदर्शन कर रहे निगम कर्मचारियों ने सरकार पर असमानता, गैर बराबरी व भेदभाव का आरोप लगाया। सफाई कर्मचारियों को कहना था कि सरकार ने अपने 13 वर्ष के कार्यकाल में कर्मचारियों को ठेकेदारों के अधीन करने का कानून बना कर सफाई कर्मचारियों को आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर करने का काम किया है। इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा व नगर पालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा के राज्य सचिव अनूप चिंडालिया, राज्य उप प्रधान कमला, नगर पालिका के जिला सचिव अनिल चिंडालिया, सैनितेशन स्टाफ यूनिवर्सल के प्रधान राहुल चिंडालिया मुख्य रूप से शामिल रहे। नगर निगम कर्मचारियों ने भोजन अवकाश के समय निगम मुख्यालय पर सफाई कर्मचारी यूनिवर्सल के प्रधान बलवीर सिंह बालगुहेर की अध्यक्षता में आक्रोश सभा आयोजित की सभा का संचालन नपा. कर्मचारी संघ के जिला कैशियर रघुवीर चौटाला ने किया।



उसके बाद कर्मचारियों ने नगर निगम मुख्यालय बीके चौक से नीलम चौक होते हुए निगम मुख्यालय पर आकर प्रदर्शन का समापन किया। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर नगर निगम कर्मचारी अब 27 अप्रैल से 2 दिन की क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा व नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने कहा कि प्रदेश के पालिका, परिषद, नगर निगमों के कर्मचारियों को सरकार ने आंदोलन के लिए मजबूर किया है। श्री शास्त्री ने कहा कि सरकार ने अपने 13 वर्ष के कार्यकाल में अर्द्ध सफाई कर्मचारियों की नौकरी पक्की एवं पक्की भती नहीं की है, सफाई सीवर के काम को ठेकेदारों के हवाले कर दिया है, ठेकेदार सफाई कर्मचारियों को आर्थिक शारीरिक मानसिक शोषण कर रहे हैं। श्री शास्त्री ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि सभी काम से ठेका समाप्त कर दिया फिर सफाई के काम में ठेका क्यों। शास्त्री ने कहा कि 27 अप्रैल से 11 नगर निगमों, 22 नगर परिषदों, 59 नगर पालिकाओं के कर्मचारी दो दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। श्री शास्त्री ने कहा कि सरकार को दलित, मजदूर, कर्मचारी विरोधी नीतियों से आहत प्रदेश के पालिका परिषद, नगर निगमों के 50 हजार कर्मचारी 1 मई से दो दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल पर चले जायेंगे। आज के प्रदर्शन में अन्य के अलावा कर्मचारी नेता सुदेश जैनवाल, रमेश खट्टान, श्रीरंज डकोलिया, सुरेश मैलांदा, हरिसिंह खडिया, प्रेमपाल, नरेश भगवाना, ललित, सीवर विभाग के नेता विशाल, अनिल भागवाना, सैनितेशन स्टाफ के नेता मदन दोगरा, बेलदार विभाग के नेता हेमवती नंदन, संजय अरोड़ा एवं जयवीर तथा महिला नेता सुरेश देवी, ललिता देवी, शकुंतला, राजवती सहित सैकड़ों कर्मचारी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

जीडीए की ओटीएस योजना का लाभ ले रहे आवंटी, 300 ने किया आवेदन



यह योजना सीमित अवधि के लिए प्रभावी है, जो कि 18 अप्रैल से 17 जुलाई तक लागू रहेगी। इस अवधि के दौरान आवेदन कर आवंटी विभिन्न वित्तीय रियायतों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, समय से निस्तारण करने वाले आवंटियों को भविष्य में होने वाली ब्याज वृद्धि एवं अन्य दंडात्मक कार्यवाहियों से भी राहत

अवैध कालोनी पर प्राधिकरण ने की ध्वस्तीकरण व सीलिंग की कार्यवाई

गाजियाबाद। जीडीए ने मोदीनगर में अवैध कालोनी पर ध्वस्तीकरण व सीलिंग की कार्यवाही की प्रभारी प्रवर्तन जोन-02 के नेतृत्व में श ओमपाल सिंह द्वारा ग्राम-बेगमाबाद बुढाना, निवाडी रोड, मोदीनगर में लगभग 4000 वर्ग मीटर भूमि में सड़के बनाने हेतु मिट्टी भराई का कार्य एवं भूखण्डों के सीमांकन हेतु ब्रिक लाईनिंग का कार्य किया गया। कार्य लगभग 6-7 माह पूर्व किया गया। वर्तमान में 4-5 माह से कार्य बन्द है। एवं बृजेश कुमार नेहरा तथा अनूप सिंह, श्रीमती अनीता सिंह, कृष्णपाल एवं रविंद्र सिंह, गौरव नेहरा, देवेन्द्र सिंह, राजपाल, धीरज पाल, संदीप चौधरी द्वारा खसरा सं-85, याकतपुर मावी, निवाडी रोड, मोदीनगर पर लगभग 7000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अवैध कालोनी विकसित करने के लिए सड़के बनाने हेतु मिट्टी आदि भराई का कार्य एवं बिजली के खम्भे लगाने का कार्य 09 माह पूर्व कराया गया। वर्तमान में लगभग 6-7 माह से कार्य बंद है।

टीम ने खाताधारक को किया गिरफ्तार आरबीआई कर्मचारी बनकर की थी एक करोड़ 90 लाख रुपए की ठगी

आरबीआई कर्मचारी बनकर 1,90,78,699 रूपए की ठगी के एक मामले में साइबर थाना सेंट्रल की टीम ने खाताधारक रशनप्रीत सिंह निवासी तुडी कॉलोनी, अनारदाना चौक पटियाला पंजाब को गिरफ्तार किया है।

बता दें कि साइबर थाना सेंट्रल में सेक्टर 29 वासी एक व्यक्ति ने दी अपनी शिकायत में बताया कि 6 दिसंबर 2025 को उसके पास एक अज्ञान नंबर से कॉल से आया जिसने अपने आप को एयरटेल हेडक्वार्टर गुरुग्राम का कर्मचारी बताया और कहा कि आपका वाई फाई कनेक्शन काटा जा रहा है। जिसके बाद उसके वॉट्सएप पर फिर से एक अज्ञान नंबर से कॉल आई जिसने अपने आप को आरबीआई का कर्मचारी बताया और कहा कि आपके खातों में जो एफडी का पैसा है उस पैसे को आरबीआई सेंट्रल के अनुसार



बताये गए खातों में जमा कर दो ताकि आरबीआई इस पैसे की जांच कर सके। जिस पर शिकायतकर्ता ने अलग-अलग ट्रॉजेक्शन के जरिये 1,90,78,699 रूपए ठगी द्वारा बताए खातों में भेज दिये, जिसके बाद उसे कोई पैसा वापस नहीं मिला। जिसकी शिकायत पर साइबर थाना सेंट्रल में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि रशनप्रीत सिंह खाता धारक है और मोबाइल फोन बेचने की एक दुकान चलाता है। जिसने अपना खाता आगे ठगी को दिया था। इसके खाता में ठगी के 25,018,700 रूपए आए थे।

तीनों आरोपियों को पूछताछ के बाद जेल भेजा

शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 87.60 लाख रुपए की ठगी, 3 खातों की अलग-अलग चैन में 6 गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज ▶▶ फरीदाबाद

शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 87,60,000 रूपए की ठगी करने के मामले में साइबर थाना एनआईटी की टीम ने 3 खातों की अलग-अलग चैन में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिनकी पहचान हरजिन्द सिंह निवासी होशियारपुर पंजाब, अभय सागर निवासी जगतपुरी एक्सटेंशन दिल्ली, प्रोत्खो जस्टीन निवासी सेनापति, मण्णपुर, फुरकन ईलियास निवासी मोहल्ला छोटा बाजार यमुनानगर, शोहेब निवासी पटाकपुरा मोहल्ला यमुनानगर तथा पुनित कुमार निवासी गांव तेलीपुरा यमुनानगर के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि हरजिन्द, अभय सागर और प्रोत्खो जस्टीन एक अन्य साइबर के मामले में दिल्ली जेल में बंद थे,



जिनको प्रोडक्शन वॉरंट पर लेकर पूछताछ की गई है। पहले खाते की चैन में अभय सागर खाताधारक है, जिसका बैंक खाता हरजिन्द सिंह ने अमित से लेकर आगे ठगी को उपलब्ध कराया था। खाते में ठगी के 100000 आगे थे। वहीं दूसरे खाते की चैन में प्रोत्खो जस्टीन खाताधारक है, जिसने अपना बैंक खाता ठगी को उपलब्ध करवाया था, खाते में ठगी के 5.50 लाख रूपए आए थे। तीनों को पूछताछ के बाद जेल भेजा गया

घर से आभूषण व नकदी चोरी करने के मामले में 2 पकड़ाए

फरीदाबाद। सेक्टर 75 स्थित एक घर से आभूषण व नकदी चोरी करने के मामले में क्राइम ब्रांच सेक्टर-85 की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिनकी पहचान संदीप व सचिन निवासी गांव पाडियावाली जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस अनुसार प्रदीप निवासी सेक्टर-75 फरीदाबाद ने थाना बीपीटीपी में दी अपनी शिकायत में बताया कि 2 अप्रैल को वह अपने परिवार सहित उसके सेक्टर-8 स्थित दूसरे घर गया था। जब वह बाथरूम घर आया तो देखा कि किसी अज्ञात द्वारा उसके घर से आभूषण व 4500 रूपए नकद चोरी कर लिए।

मामला ईओडब्ल्यू शाखा में दर्ज 2500 करोड़ का भुगतान करने के बावजूद 4,500 बायर्स को घरों की डिलिवरी में देरी

धर्मौ कौशिक ▶▶ गुरुग्राम

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को करीब 4,500 खरीदारों को घरों की डिलिवरी में देरी से जुड़े 2,500 करोड़ रूपए के कथित धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली-एनसीआर में रहेजा डेवलपर्स, इसके प्रमोटरों और संबंधित संस्थाओं से जुड़े कई परिसरों की तलाशी ली। ईडी के दिल्ली जोनल कार्यालय ने नवीन रहेजा, उनके बेटे नयन रहेजा, परिवार के अन्य सदस्यों और कंपनी निदेशकों से जुड़ी संपत्तियों को निशाना बनाते हुए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सैनिक फार्म और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी सहित सात स्थानों पर छापे मारे। जांच इस आरोप से संबंधित है कि डेवलपर्स ने घर खरीदारों से, विशेष रूप से गुरुग्राम की रहेजा रेवंता परियोजना में, लगभग 2,500 करोड़ रूपए एकत्र किए, लेकिन प्रतिबद्ध समय सीमा के भीतर फ्लैट देने में विफल रहा। ईडी द्वारा रहेजा डेवलपर्स, उसके निदेशकों और संबंधित संस्थाओं के परिसरों पर तलाशी अभियान चल रहा है। महत्वपूर्ण

दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। दरअसल, मामला शुरू में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज किया गया था। इस शिकायत के आधार पर कि डेवलपर्स को लगभग 2,500 करोड़ रूपए का भुगतान करने के बावजूद लगभग 4,500 घर खरीदारों को घर आवंटित नहीं किए गए थे। बाद में ईडी ने मामले को अपने हाथ में ले लिया और प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएएल) के तहत कार्रवाई शुरू की। अधिकारियों ने कहा कि जांच गुरुग्राम में रहेजा रेवंता हाउसिंग प्रोजेक्ट पर केंद्रित है, जहां खरीदारों ने कई वर्षों से भुगतान करने के बावजूद हैंडओवर में लंबी देरी का आरोप लगाया है। ईडी की टीमें खरीदार के धन के उपयोग का पता लगाने के लिए वित्तीय रिकॉर्ड, परियोजना दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डेटा की जांच कर रही हैं। संदेह है कि खरीदारों से एकत्र किए गए धन का उपयोग परियोजना को पूरा करने के लिए पूरी तरह से नहीं किया गया है, जिससे लगभग 4,500 घर खरीदार कब्जे के लिए इंतजार कर रहे हैं।

फायरिंग में गंभीर रूप से घायल 22 वर्षीय युवक को फोर्टिस हॉस्पिटल में मिला नया जीवन

हरिभूमि न्यूज ▶▶ फरीदाबाद

फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद के डॉक्टरों की टीम ने 22 वर्षीय एक ऐसे युवक को नया जीवनदान दिया है, जिसे फरीदाबाद में आयोजित एक जन्मदिवस समारोह के दौरान हुई फायरिंग में गोली लगी थी और यदि समय पर उपचार नहीं मिलता तो यह चोट घातक भी साबित हो सकती है। डॉ मोहसिन खान सीनियर कंसल्टेंट, जीआई, मिनीमल एक्सप्रेस एंड

बेरियाट्रिक सर्जरी फोर्टिस एस्कॉट्स हॉस्पिटल के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने बेहद सावधानीपूर्वक ढंग से मरीज को सर्जरी की। मरीज को स्वास्थ्य लाभ के बाद स्थिर अवस्था में छह दिनों के भीतर अस्पताल से छुटी भी दे दी गई। मरीज को जब फोर्टिस एस्कॉट्स के इमरजेंसी विभाग में लाया गया था तो उनके सीने में दायीं और नीचे की तरफ खून बह रहा था और सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी।

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

घारा 82 Cr.P.C. देखिए

मेरे सम्मक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त आरोपी साजिद उर्फ राहुल पुत्र जाकिर उर्फ जाकिर खान, पता: मकान नं. एफ-213, चूरिया मुहल्ला तुगलकाबाद गांव नई दिल्ली CR. No. 2984/2024, FIR. No. 151/2024, U/s: 25/54/59 A ACT, पुलिस थाना: ओखला औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त साजिद उर्फ राहुल मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त साजिद उर्फ राहुल फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि उक्त अभियुक्त साजिद उर्फ राहुल CR. No. 2984/2024, FIR. No. 151/2024, U/s: 25/54/59 A ACT, पुलिस थाना: ओखला औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली की जाती है कि वे इस न्यायालय के सम्मक्ष (या मेरे सम्मक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 25.05.2026 को या उससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार आकांक्षा गौतम न्यायिक दण्डाधिकारी-02, प्रथम श्रेणी दक्षिण पूर्व, कमरा नं. 513 साकेत कोर्ट परिसर, नई दिल्ली

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

घारा 82 Cr.P.C. देखिए

मेरे सम्मक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त आरोपी संतोष कुमार पुत्र करन सिंह पता: सी-285, शाहबाद डेयरी, दिल्ली FIR. No. 428/2018, U/s: 498A/406/506/34 IPC, पुलिस थाना: शाहीनार बाग, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त संतोष कुमार मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त संतोष कुमार फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि उक्त अभियुक्त संतोष कुमार FIR. No. 428/2018, U/s: 498A/406/506/34 IPC, पुलिस थाना: शाहीनार बाग, दिल्ली से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के सम्मक्ष (या मेरे सम्मक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 28.05.2026 को या उससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार श्रीमती ऐश्वर्या शर्मा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी दक्षिणी कोर्ट, दिल्ली

खबर संक्षेप
अस्पताल की 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या

कोल्हान। झारखंड कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम में मरीजों की खुदकुशी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अस्पताल के इंटरमीडियट विभाग में भर्ती 39 वर्षीय कैदी अशोक कुमार महतो ने सातवीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। उसे 19 अप्रैल को सुबह घाघीडीह सेंट्रल जेल में गला काटकर आत्महत्या के प्रयास के बाद एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

अखिलेश-राहुल का पुतला फूंकने के दौरान हादसा

बहराइच। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सड़क पर उतरतीं भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल के साथ हादसा हो गया। दरअसल, भाजपा विधायक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पुतला फूंक रही थीं। इसी दौरान उनका चेहरा झुलस गया। मौके पर मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें बचाया। इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया।

हाईकोर्ट में अद्वैती जानकारी एसडीएम पर जुर्माना

प्रयागराज। हाईकोर्ट में अद्वैती जानकारी प्रस्तुत करना एसडीएम बलरामपुर हेमंत गुप्ता को मंहंगा पड़ा। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सौरभ लवानीया ने एसडीएम पर 2000 रुपए जुर्माना लगाते हुए पुनः सही तथ्यों के सहायतावेज दखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। बिना बेनामा लिए ही याची के जमीन को सरकार ने प्लनआरपी के नाम घोषित कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ऐवशन

झारखंड टेंडर कमीशन घोटाले की करीब 35 करोड़ राशि की मनी लाउंड्रिंग में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम समेत अन्य से जुड़े मामले में डे-टू-डे सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में मामले की डे-टू-डे ट्रायल शुरू हो चुका है।

पूर्व मंत्री आलमगीर से जुड़े 35 करोड़ कैश कांड में हर दिन सुनवाई शुरू

एजेंसी►रांची झारखंड टेंडर कमीशन घोटाले की करीब 35 करोड़ राशि की मनी लाउंड्रिंग में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम समेत अन्य से जुड़े मामले में हर दिन सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में मामले की डे-टू-डे ट्रायल शुरू हो चुका है। सुनवाई के दौरान जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, संजीव लाल और जहांगीर आलम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाता है।



टेंडर प्रक्रिया में कमीशनखोरी के जरिए अवैध धन अर्जित का मामला
अवैध आरोपियों की ओर से कर्कोल उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। यह मामला उस चर्चित 35 करोड़ रुपए की नकद बरामदगी से जुड़ा है, जो ईडी की छापेमारी के दौरान सामने आई थी। जांच एजेंसी का आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में कमीशनखोरी के जरिए अवैध धन अर्जित कर उसे ठिकाने लगाया गया। बता दें कि इस मामले में ईडी ने पूछताछ के दौरान 15 मई 2024 को गिरफ्तार किया था, तब से वह जेल में है। मामले में गौरीगंज विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम समेत अन्य ट्रायल फेस कर रहे हैं।

अमी और सताएगी चुमती गर्मी और लू

देश का सबसे गर्म जिला बना प्रयागराज

एजेंसी►प्रयागराज प्रदेश में तेज धूप, गर्मी और लू ने सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर रखा है। ज्यादातर जिलों में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है और शुष्क पड़ुआ हवाएं भी अपना असर दिखा रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार, दो दिन और इसी तरह का मौसम रहने की उम्मीद है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते 28 अप्रैल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार हैं जिससे तापमान



विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि शुष्क मौसम के साथ प्रदेश में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंचने या पार होने के आसार बने हुए हैं। एक दिन पहले शुक्रवार को प्रयागराज में तापमान 45 डिग्री पार कर गया था। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आ रही शुष्क पड़ुआ हवाएं जारी रहेंगी। आंतरिक महाराष्ट्र के आसपास बने प्रतिक्रवात के प्रभाव से आगामी 2-3 दिनों के दौरान तापमान में कोई विशेष परिवर्तन न होने की संभावना है।

संजय सरावगी ने दिए बड़े संकेत पलोर टेस्ट के बाद अब मंत्रिमंडल में विस्तार की तैयारी में एनडीए सरकार

एजेंसी►पटना बिहार विधानसभा में एनडीए सरकार द्वारा विश्वास मत हासिल करने के बाद अब राज्य की सियासत में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सरगमियां तेज हो गई हैं। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने स्पष्ट कर दिया है कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने संकेत

दिए हैं कि नई सरकार बिहार के विकास के लिए लंबी योजना पर काम कर रही है और आने वाले समय में एक सशक्त टीम के साथ राज्य को आगे ले जाया जाएगा। संजय सरावगी के इस बयान के बाद अब उन चेहरों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, जिन्हें नई कैबिनेट में जगह मिल सकती है।

दो महीने बाद खत्म हो रहा कार्यकाल सीएम सम्राट से मिलने पहुंचे कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह

एजेंसी►पटना बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से विपक्षी दल कांग्रेस के एक विधान परिषद ने मुलाकात की है। इससे राजनीतिक पारा गर्मा गया है। कांग्रेस एमएलसी समीर कुमार सिंह गुरुवार को सीएम सम्राट से मुलाकात करने उनके कार्यालय में पहुंचे। दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई। इस पर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। समीर सिंह का एमएलसी कार्यकाल दो महीने बाद खत्म होने वाला है। हालांकि, कांग्रेस

एमएलसी ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है। समीर कुमार सिंह का कहना है कि सीएम सम्राट चौधरी उनके क्षेत्रीय विधायक हैं। उनसे मुलाकात के दौरान सीएम के विधानसभा क्षेत्र (तारापुर) की समस्याओं और अन्य कार्यों को लेकर चर्चा की गई।

योगी सरकार 1 मई से चलाने जा रही विशेष अभियान

छूटे हुए बच्चों को चिन्हित कर विद्यालयों में लाने बस्तियों और झुग्गी-झोपड़ियों तक जाएंगी टीमें

यूपी में योगी सरकार ने पहली मई से विशेष अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान के तहत टीमें श्रमिक बस्तियों, ईट-भट्टों और झुग्गी-झोपड़ियों तक जाएंगी। यहां रहने वाले छूटे हुए बच्चों को चिन्हित कर विद्यालयों में दाखिला किया जाएगा।

रॉपआउट बालिकाओं को कस्टर्बा गांधी बालिका विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश प्रशासन, शिक्षक, अभिभावक व समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही

एजेंसी►लखनऊ योगी सरकार पहली मई 2026 से प्रदेशभर में एक विशेष अभियान चलवाने जा रही है। इस अभियान के तहत श्रमिक बस्तियों, ईट-भट्टों और झुग्गी-झोपड़ियों तक टीमें जाएंगी। यहां रहने वाले छूटे हुए बच्चों को चिन्हित कर विद्यालयों में दाखिला किया जाएगा। यह अभियान खास तौर पर आउट-ऑफ-स्कूल और ड्रॉपआउट बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने पर केंद्रित होगा। दिव्यांग बच्चों को स्पेशल एजुकैटर के सहयोग से चिन्हित कर उनका नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा, वहीं



जोड़ना है। 'स्कूल चलो अभियान' को जन आंदोलन बनाकर हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। ड्रॉपआउट बच्चों की वापसी, बालिकाओं की शिक्षा और ट्रांजिशन दर बढ़ाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह समावेशी बने, जहां समाज के हर वर्ग के बच्चों को समान अवसर मिले। इसी उद्देश्य से यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रशासन, शिक्षक, अभिभावक और समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।

कक्षा 5 से 6, 8 से 9 और 10 से 11 तक 100% ट्रांजिशन सुनिश्चित करने के निर्देश

अपर मुख्य सचिव बैसिक एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्येक बच्चे का नामांकन सुनिश्चित कराया जाए। स्कूल चलो अभियान के प्रथम चरण (1 से 15 अप्रैल) में 3 वर्ष पूर्ण करने वाले बच्चों का आंगनबाड़ी/बाल वाटिका में नामांकन, 6 वर्ष के बच्चों का कक्षा-1 में प्रवेश और 7 से 14 वर्ष के ड्रॉपआउट बच्चों की पहचान की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। अब दूसरे चरण में इन्से और तेज करते हुए छूटे हुए बच्चों तक सीधी पहुंच बनाई जाएगी। साथ ही कक्षा 5 से 6, 8 से 9 और 10 से 11 तक 100 प्रतिशत ट्रांजिशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पढ़ाई बीच में न छूटे। आर्ट्स के अंतर्गत विद्यालयों में लॉटरी के माध्यम से चयनित बच्चों का शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी पात्र बच्चा प्रवेश से वंचित न रहे।

विद्यालयों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने 'ऑपरेशन कार्यालय' व 'प्रोजेक्ट अलंकार'

वहीं, विद्यालयों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 'ऑपरेशन कार्यालय' और 'प्रोजेक्ट अलंकार' के तहत व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। पिछले वर्षों में 19 मानकों के आधार पर विद्यालयों का संतुलितकरण किया गया है। अब पुनः विशेष अभियान चलाकर शेष अवस्थाओं संबंधी कमियों की पहचान कर उन्हें सीएसआर और अन्य संसाधनों के माध्यम से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही विद्यालयों पर सभी विद्यालयों को ऑनबोर्ड कर गैप एवालिनेटिंस दर्ज कराते और स्वयंसेवी संस्थाओं/वॉलंटियर्स के सहयोग से सुविधाओं का विस्तार सुनिश्चित करने को कहा गया है।

पेन एक का शेष

संघ के विचारों... पांच प्रमुख लक्ष्य तय किए हैं। सभ्यतागत मूल्यों से मार्गदर्शन करेगा भारत : होसबाले ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत न केवल आर्थिक रूप से मजबूत होगा, बल्कि वैश्विक मंच पर आध्यात्मिक नेतृत्व भी प्रदान करेगा। साक्षात्कार में आरएसएस के शताब्दी वर्ष के अवसर पर उन्होंने कहा कि संगठन का मानना है कि भारत धीरे-धीरे ऐसी स्थिति की ओर बढ़ रहा है, जहां वह अपनी आर्थिक शक्ति को अपनी सभ्यतागत मूल्यों के साथ जोड़कर दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है। होसबाले ने यह भी कहा कि आरएसएस का राष्ट्रीय जीवन के केंद्रीय मंच पर पहुंचना राजनीति, समाज और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उसके बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। उनके अनुसार यह विकास राष्ट्रीय एकता और वैश्विक सद्भाव के व्यापक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है।

ईरान ने कहा...

के बाद यह पहली कार्य बैठक थी। उन्होंने पाकिस्तान के डिटी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में पाकिस्तान की ओर से गृह मंत्री मोहसिन नकवी और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बार्चेई ने उनके बीच सीधी मीटिंग से मना कर दिया। बार्चेई ने 'एक्स' पर लिखा कि ईरान और अमेरिका के बीच कोई मीटिंग होने का प्लान नहीं है। ईरान के अब्दुल्वहेसन पाकिस्तान को बताए जाएंगे। ईरानी प्रतिनिधिमंडल में शामिल विदेश मंत्री अब्बास अराघची, उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी, राजदूत रजा अमीरी मोहदम और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बार्चेई शुक्रवार देर रात इस्लामाबाद पहुंचे थे। ईरानी प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान में रुकने के बाद अराघची युद्ध को खत्म करने के प्रयासों पर चर्चा के करने के लिए ओमान और रूस का दौरा करेंगे।

पूर्व पीएम इमरान के बेटे का दावा: पाक दुनिया में 'गुड' पर अपने देश में ही 'बेड' : जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के बेटे सुलेमान खान ने देश के नेतृत्व पर गहरे होते लोकतांत्रिक संकट को छिपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी विरोधी की आवाज को दबा रहे हैं, जबकि विदेशों में अपनी बेहतर छवि पेश कर रहे हैं। सुलेमान ने दावा किया कि सरकार वैश्विक मंच पर अपनी छवि चमकाने पर ज्यादा ध्यान दे रही है, जबकि, उनके अनुसार, पाकिस्तान में मानवाधिकारों का उल्लंघन जारी है और लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आम नागरिकों को बिना किसी उचित कानूनी प्रक्रिया के हिरासत में लिया जा रहा है। गिरफ्तारियां उन लोगों को निशाना बना रही हैं जो उस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं जिसे उन्होंने बढ़ता हुआ तानाशाही तंत्र बताया।

ईरान से युद्ध 'दुनिया के लिए बेहतर उपहार': अमेरिकी के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान के साथ जारी संघर्ष को 'दुनिया के लिए एक उपहार' करार दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान के समुद्री यातायात पर अमेरिकी नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी, जब तक इसकी आवश्यकता है। हेगसेथ ने कहा कि समुद्री प्रतिबंध

अंतरराष्ट्रीय स्थिरता के लिए ईरान के कथित खतरे को बेअसर करने के उनके साहसी और खतरनाक मिशन का हिस्सा है।

डीआरडीओ अध्यक्ष ने ...

मेसर्स बीएफएल द्वारा कई लघु और मध्यम उद्योगों के सहयोग लिया गया है। जिसकी मदद से अंत में रक्षा परिस्थितिकी तंत्र को ही मजबूती मिली है। इन भूमिकाओं को निभाने में सक्षम: यह प्लेटफॉर्म इन्फैट्री कॉम्बैट व्हीकल और आर्मेट परसॅनल कैरियर दोनों भूमिकाओं को निभाने में सक्षम हैं। दोनों स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकास के साथ तैयार किए गए 30 मिमी क्रूलेस टॉरेंट से लैस हैं। उच्च-शक्ति वाले इंजन और स्वचालित ट्रांसमिशन से युक्त होने के कारण इनमें अत्यधिक शक्ति-भार अनुपात, उच्च गति क्षमता, ढलान और बाधाओं को पार करने की क्षमता, मॉड्यूलर विस्फोट और बैलिस्टिक सुरक्षा के साथ 'STANAG' स्तर 4 और 5 की सुरक्षा है। प्लेटफॉर्म की गतिशीलता, मारक क्षमता और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनमें उन्नत विशेषताओं का समावेश किया गया है। हाइड्रो जेट्स सहित जल बाधाओं को पार करने की बेहतर क्षमता वाला उभयचर मॉडल इन दोनों को परिचालन लचीलापन प्रदान करता है। जबकि 30 मिमी. क्रूलेस टॉरेंट और 7.62 मिमी. पीकेटी गन को टैंक रोधी गाइडेड मिसाइलों को लॉच करने के लिए इनमें शामिल किया गया है।

बेयरबॉक की यात्रा से ...

यह है कि भारत के कई प्रयासों के बावजूद आज तक टीआरएफ को संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित आतंकी संगठन की सूची में शामिल नहीं किया है। लेकिन अब एक बार फिर से देश के कूटनीतिक गलियारों में इस मुद्दे से जुड़ी चर्चाओं ने जोर पकड़ा है। जिसके पीछे कहीं न कहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 80 वें सत्र की अध्यक्ष एन्नालेना बेयरबॉक की आगामी भारत यात्रा को अहम वजह माना जा रहा है। 28 अप्रैल को वह नई दिल्ली पहुंचेंगी। लेकिन उससे ठीक पहले विदेश मंत्रालय सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने बेयरबॉक से न्यूयॉर्क में एक महत्वपूर्ण मुलाकात की है। जिसमें भारत की तरफ से आतंकवाद के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय लड़ाई के मामले को उठाया गया है। जॉर्ज इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं। जिसके तहत उनकी यूएन के कई उच्च अधिकारियों के साथ बैठकें हो रही हैं।

सकारात्मक और उत्पादक रही बैठक : विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शनिवार को 'एक्स' पर पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी है। जिसमें बताया कि मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज की यूएनजीए के 80 वें सत्र की अध्यक्ष एन्नालेना बेयरबॉक के साथ विभिन्न मुद्दों पर एक सकारात्मक और उत्पादक बैठक हुई है। जिसमें शांति, सुरक्षा, विकास, बहुपक्षीयता और आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय लड़ाई मुख्य रूप से शामिल किए गए। इससे पहले बीते शुक्रवार को जॉर्ज ने आतंकवाद विरोधी मामलों के अवर महासचिव एलेक्जेंडर जुएवे के साथ भी बैठक की थी। जिसमें आतंकवाद के खतरे से मुकाबला करने के लिए यूएन के समक्ष भारत के मजबूत सहयोग को दोहराया। साथ ही

संयुक्त राष्ट्र में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में बहुपक्षवाद को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए वैश्विक-दक्षिण की भागीदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।

यूएन महासचिव से भी हुई मुलाकात : रणधीर ने अपनी एक अन्य पोस्ट में बताया कि विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) ने अपनी यात्रा के दौरान बीते गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव (यूएनएसजी) एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की थी। जिसमें संयुक्त राष्ट्र में सुधारों और वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूती प्रदान को लेकर विचार-विमर्श किया गया। यह एक ऐसा मुद्दा है, जिसे भारत ने लगातार प्रोत्साहित किया है। इसमें भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष जैसी पहल भी शामिल है। यहां बता दें कि इन बैठकों के पूर्व में 20 अप्रैल को यूएन में हुई एक अन्य उच्च-स्तरीय बैठक में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में लंबे समय से अटक पड़े सुधारों के मामले को भी उठाया।

हरियाणा में अब...

होंगी। जिससे खरीद कार्य में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी। उन्होंने इस दौरान प्रदेश में अब तक हुई गेहूं खरीद का ब्यौरा देते हुए कहा कि रबी सीजन 2026-67 में प्रदेश की मंडियों में गेहूं की बंपर आवक हुई है। इसने पिछले चार साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सरकार ने खरीद प्रबंधों को लेकर पुख्ता बेतजाम किए, जिसके चलते प्रदेश में गेहूं खरीद का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है और किसानों को समय पर भुगतान भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक प्रदेश की मंडियों में 21 हजार 44 करोड़ रुपये मूल्य की 81 लाख 48 हजार मीट्रिक टन गेहूं की आवक दर्ज की जा चुकी है, जो पिछले 4 वर्षों में सर्वाधिक है। अकेले 11 अप्रैल को एक ही दिन में 7 लाख 71 हजार मीट्रिक टन गेहूं की रिकॉर्ड आवक हुई। उन्होंने कहा कि अब तक 5 लाख 80 हजार किसान अपनी उपज लेकर मंडियों में पहुंच चुके हैं। वह किसानों की पहचान डिजिटल गेट पास के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही 79 लाख 14 हजार मीट्रिक टन गेहूं का बायोमेट्रिक सत्यापन हो चुका है, जो लगभग 97 प्रतिशत है। प्रदेश का किसान तकनीक को तेजी से अपना रहा है और पारदर्शी व्यवस्था पर भरोसा जता रहा है। प्रदेश की मंडियों में 70 लाख 23 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद पूरी हो चुकी है, साथ ही प्रदेश की मंडियों से 34 लाख 56 हजार मीट्रिक टन गेहूं का उठान हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 अप्रैल से उठान प्रक्रिया में और तेजी आई है। प्रतिदिन साढ़े 3 लाख मीट्रिक टन का उठान हो रहा है। पिछले वर्ष से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि रबी सत्र 2025-26 में जहां कुल 72 लाख 89 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी। वहीं, इस वर्ष अब तक 81 लाख 48 हजार मीट्रिक टन की आवक दर्ज हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों के समय न डिजिटल व्यवस्था थी, न पारदर्शीता थी, न समय पर भुगतान होता था। किसानों को मंडियों में लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता था, कामगो टीएन बनते थे और भुगतान के लिए हफ्तों, कभी-कभी महीनों का इंतजार करना पड़ता था। वर्ष 2014 से अब तक फसल खरीद की प्रक्रिया में बड़ा सुधार हुआ है। इससे पहले, केवल गेहूं और धान की ही खरीद एम.एस.पी. पर होती थी। आज हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां सभी फसलों की एम.एस.पी. पर खरीद होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर इस वर्ष 10 लाख 7 हजार 657 किसान

पंजीकृत है। सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए ई-खरीद पोर्टल और मोबाइल एप के माध्यम से डिजिटल गेट पास और एगिजेंट पास का व्यवस्था लागू की है। इस सीजन में अब तक 13 लाख 47 हजार डिजिटल गेट पास जारी किए गए हैं।

संक्र: एच-1बी वीजा ..

मात्र 25,000 करने, लॉटरी सिस्टम को खत्म कर न्यूनतम वेतन सीमा को 2 लाख डॉलर सालाना करने और सभी प्रकार की छूटों को समाप्त करने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा, बिल में बेहद सख्त प्रावधान किए गए हैं, जैसे वीजा धारकों द्वारा परिवार को साथ लाने पर रोक, ओपीडी कार्यक्रम को समाप्त और ग्रीन कार्ड के रास्ते को बंद करना। नियोजताओं के लिए यह साबित करना अनिवार्य होगा कि उन्हें कोई योग्य अमेरिकी कर्मचारी नहीं मिला है। इमिग्रेशन विशेषज्ञों ने इसे अब तक का सबसे सख्त बिल करार दिया है। यूकै भारतीय पेशेवर इस वीजा के सबसे बड़े लाभार्थी रहे हैं, इसलिए इस कानून के पारित होने पर भारतीय आईटी क्षेत्र और विशेषज्ञों पर इसका गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

25% से ज्यादा महंगे...

चलते 'फ्यूल सरचाज' लागू कर दिया है। इसके बाद से ही मध्य प्रदेश सहित देशभर में फ्लाइट टिकट 15 से 20% तक महंगे हो गए हैं। इंडैर से चलने वाली घरेलू और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स के किराए में औसतन 20% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुछ रूट्स पर यह और ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर इंदौर से मुंबई का किराया 4500 रुपये से बढ़कर करीब 6500 रुपये तक पहुंच गया है। कोलकाता जाने वाला किराया सबसे ज्यादा बढ़ा है। जहां पहले टिकट 6500-7500 रुपये में मिल जाता था, वहीं अब 8500 से 12,000 रुपये तक पहुंच गया है। ट्रेवल एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस रूट पर कम प्रतिस्पर्धा और ज्यादा मांग की वजह से किराए तेजी से बढ़े हैं।

ऊर्जा सहयोग को ...

कर्नेक्टिविटी को आगे बढ़ाने वाले साझा विजन पर केंद्रित रही हैं। बैठक में नेपाल के मंत्री विराज श्रेष्ठ और भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने दोनों देशों के बीच सहयोग को और अधिक गहराई प्रदान करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है। साथ ही भारत, नेपाल के आम लोगों की संयुक्त रूप समृद्धि और आपसी लाभ के लिए समन्वय को और अधिक बढ़ाने पर भी सहमति प्रदान की गई है। नेपाल के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि भारत के साथ निरंतर संवाद, सहयोग के जरिए अपनी साझेदारी को और अधिक मजबूती प्रदान करने जा रहे हैं।

दोनों देशों के बीच ...

की दो दिवसीय नेपाल यात्रा से जुड़ा हुआ है। चीन के राजदूत से भी की मुलाकात: सूत्रों ने कहा कि भारत के राजदूत के साथ ही नेपाल के ऊर्जा मंत्री की चीन के राजदूत झांग माओमिंग से भी मुलाकात हुई थी। जिसमें दोनों देशों के साझा रूप से लाभप्रद सहयोग को और अधिक उन्नत बनाने से जुड़े हुए कई मुद्दों पर चर्चा की गई थी। वर्तमान में क्षेत्रीय ऊर्जा चुनौतियों से कैसे मुकाबला किया जा सकता है? इस मामले पर भी दोनों पक्षों के बीच विचारों का आदान-प्रदान किया गया।

एनआईए करेगी मामले की जांच पाकिस्तान में बैठकर भारत के नंबर से व्हाट्सएप चला रहे आईएसआई हैंडलर

एजेंसी►मेरठ आतंकी घटनाओं को अंजाम देने और बाकी देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भारत के नंबर पर व्हाट्सएप एक्टिव कर इन्हें पाकिस्तान में आईएसआई के जासूस और हैंडलर चला रहे हैं। यूपी एटीएस ने जिस समीर खान को गिरफ्तार किया है, उसने फर्जी आईडी पर कुछ सिम कार्ड एक्टिव किए और इनका कोड पाकिस्तान में शहजाद भट्टी को दिया था। इसके बाद से इन नंबरों का इस्तेमाल पाकिस्तान में किया जा रहा है। पूर्व में गाजियाबाद में पकड़े गए मॉड्यूल ने भी इसमें इसी तरह से कुछ नंबर को व्हाट्सएप पर एक्टिव कराकर पाकिस्तान में शहजाद भट्टी और सरदार को कोड दिए थे। आईएसआई और गैंगस्टर शहजाद भट्टी के लिए काम करने वाले



आरोपी समीर खान और तुषार उर्फ हिजबुल्लाह अली से पछुताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप है कि समीर ने शहजाद भट्टी और आईएसआई के मेजर के कहने पर दो मोबाइल सिम लिए थे। इन्हें एक्टिव कराया था। इन मोबाइल नंबर से पाकिस्तान में बैठे आईएसआई एजेंट ने अपने यहां व्हाट्सएप शुरू किया। व्हाट्सएप एक्टिव करने के लिए कोड समीर के पास मौजूद मोबाइल नंबर पर आये, जो पाकिस्तान में बैठे साथियों को दे दिए थे। इसके बाद से इन मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप का इस्तेमाल पाकिस्तान में ही किया जा रहा है। यह पहला मामला नहीं है।

सीवरेज लाइन के गड़्ढे की खुदाई के दौरान अलीगढ़ में मिट्टी की ढाय गिरने से तीन मजदूर दबे, एक की मौत

एजेंसी►अलीगढ़



जिले में दर्दनाक हादसा हो गया। दो दिनों से जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए चल रहे सीवर लाइन मरम्मत कार्य के दौरान 20 फीट गहरे गड़्ढे में उतरते श्रमिक को ऊपर मिट्टी गिर गई, जिसके मलबे के नीचे दबकर श्रमिक दब गया। आनन-फानन में अन्य मजदूरों ने उसे निकालने का प्रयास किया, लेकिन मलबा ज्यादा होने के कारण असफल रहे। जैसीबीबी की भद्र से मिट्टी हटाई गई, तब तक उसकी मौत हो गई। घटना का खौफनाक मंजर कैमेरे में कैद हो गया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। जानकारी के अनुसार रेलवे रोड पर चोक हो चुकी सीवर लाइन को ठीक करने का कार्य किया जा रहा था। सीवर चोक होने के कारण इलाके में भारी जलभराव हो रहा था, जिसे सुलझाने के लिए जलकल विभाग को टीम जुटी थी। खुदाई के दौरान

स्थिति तब गंभीर हो गई जब सीवर लाइन के साथ-साथ पानी की पाइपलाइन भी उभेज हो गई। शनिवार दोपहर श्रमिक सीवर लाइन को जोड़ने के लिए करीब 20 फीट गहरे गड़्ढे में उतरा था। कार्य के दौरान सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं था। अचानक ऊपर से मिट्टी की एक भारी लेयर भरभरा कर श्रमिक को ऊपर गिर गई। श्रमिक को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वह टनों वजनी मिट्टी के नीचे दब गया।

विशेष: अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस
29 अप्रैल

आवरण कथा / प्रस्तुति: रेणु खंतवाल

नृत्य ऐसी कला है, जो जीवन को उमंगित कर देती है। जिनके जीवन में नृत्य शामिल होता है, वे हर पल संतुलित, आनंदित महसूस करते हैं। नृत्य दिवस के अवसर पर यहां अलग-अलग शैली के नर्तक और नृत्यांगनाएं बता रहे हैं नृत्य का उनके जीवन में क्या महत्व है? यानी, नृत्य ने उनके जीवन को किस-किस स्तर पर बदला, उसे अलग दिशा प्रदान की? जब नृत्य के दौरान वे उसमें पूरी तरह खो जाते हैं तो उस समय किस तरह की अनुभूति होती है? और शारीरिक-मानसिक सेहत बेहतर करने में नृत्य की भूमिका को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?

जीवन की सरगम पर तन-मन की थिरकन

नृत्य से जीवन में निखार आता है

कविता द्विवेदी, ओडिसी नृत्यांगना

नृत्य मेरे लिए जीवन है और मेरे जीवन में नृत्य है। मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि अगर मेरे जीवन में नृत्य नहीं होता तो मेरे जीवन का कोई अस्तित्व भी नहीं होता। नृत्य ने समय-समय पर मेरे जीवन को बदला, स्थापित किया। मुझे अलग-अलग स्तर पर पहचान दी, आगे बढ़ाया। इसी की वजह से मुझे कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली और देश दुनिया में अपनी कला दिखाने का अवसर मिला। मैं दृढ़ विश्वास से आगे बढ़ पाई। सन 2013 में मुझे ओडिसी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। इस पुरस्कार का भी मेरे जीवन में बहुत महत्व रहा है। नृत्य के माध्यम से मैंने खुद को खोजा, समझा कि मुझमें क्या अच्छाई है, क्या कमी? जब भी मैं नृत्य करती हूँ, उसमें खो जाती हूँ। उसके बाद मैं नृत्य के शिखर बिंदु पर पहुंच जाती हूँ। वहां तो मुझे अपनी कोई सुधबुध नहीं रहती। पूर्ण समर्पण के साथ मैं नृत्य में डूबी होती हूँ। उस दौरान एक दिव्य शक्ति को महसूस करती हूँ। जब मैं अपनी प्रस्तुति पूरी करती हूँ, उसके बाद मुझसे कुछ बोला ही नहीं जाता, मैं चुप हो जाती हूँ। कभी महसूस करती हूँ कि अब मुझे एकांत चाहिए। जिस शक्ति के साथ मैं नृत्य कर रही थी, उसी शक्ति के साथ मैं कुछ वक्त बिताऊँ। नृत्य से मुझे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। हर व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में नृत्य को शामिल करना चाहिए। नृत्य से जीवन में निखार आता है। नृत्य के माध्यम से आप समाज में अलग पहचान, महत्व बनाते हैं। बहुत त्याग और तपस्या से मैंने नृत्य के माध्यम से देश-दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। *

तन-मन-जीवन के लिए जरूरी है नृत्य

श्रुति सिन्हा, कथक नृत्यांगना

नृत्य मेरे जीवन का महत्वपूर्ण, बहुआयामी हिस्सा है। नृत्य ने मुझे जीने का सकारात्मक नजरिया दिया। मेरा शरीर, मन और आत्मा पूरे तरीके से नृत्य में डूबे रहते हैं। मैं नृत्य के जरिए खुद को बहुत मजबूत महसूस करती हूँ। जीवन में जितने भी उतार-चढ़ाव आते हैं, उससे उबरने में नृत्य मेरी बहुत सहायता करता है। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और पेशेवर स्तर पर नृत्य का मुझ पर बहुत प्रभाव रहा। आज नृत्य के कारण ही सामाजिक स्तर पर मुझे इतना मान-सम्मान मिलता है। नृत्यांगना, नृत्य शिक्षिका और कोरियोग्राफर के रूप में मेरी पहचान है। नृत्य ने ही मुझे सकारात्मक, ऊर्जावान बनाया। आत्म खोज व अनुशासन के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ना सिखाया। रचनात्मक नई सोच और कल्पनाशक्ति प्रदान की। इस तरह नृत्य ने मुझे जीवन में बहुत कुछ दिया है। कई बार नृत्य करते हुए मैं जब उसमें पूरी तरह खो जाती हूँ, उस समय जो अनुभूति होती है उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। उस अनुभूति को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उस समय मैं सिर्फ अपने आप में लीन होकर नृत्य में डूबी होती हूँ। शायद इसे ही नृत्य के जरिए मनुष्यत्व का देवत्व तक पहुंचना कहते हैं। नृत्य बहुत अच्छा व्यायाम भी है, जिससे शरीर लचीला, मजबूत और ऊर्जावान बनता है। नृत्य आत्मविश्वास बढ़ाता है, तनाव, चिंता व अवसाद कम करता है। नृत्य, संगीत और ताल के साथ जुड़कर मन को खुशी व शांति देता है। मन को संतुलित करने के साथ-साथ पूरे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। इस तरह नृत्य शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों के लिए बहुत लाभकारी होता है। मेरा मानना है कि नृत्य को अपने डेली रूटीन में शामिल करने से सकारात्मक सोच बढ़ती है। आलस नहीं रहता। शरीर बीमारियों से दूर रहता है। अतः हम किसी भी उम्र के हों, नृत्य जरूर करना चाहिए। *



नृत्य मेरी अभिव्यक्ति का माध्यम है

बीके अतुल गोस्वामी, कटेपेरी डांस-कोरियोग्राफर



मेरे लिए नृत्य केवल एक कला नहीं बल्कि मेरी पहचान है। नृत्य ने मेरे शरीर को शक्ति, मन को शांति और मेरी आत्मा को झुझसे जोड़ा है। जहां शब्द रुक जाते हैं, वहां से मेरा नृत्य शुरू होता है यानी नृत्य मेरी अभिव्यक्ति का माध्यम है। जब मैं नृत्य करता हूँ और पीक पर पहुंच जाता हूँ, उस समय मुझे यह महसूस होता है कि मैं डांस नहीं कर रहा हूँ बल्कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से डांस करवा रही है। उसके बाद हर बीट दिल की धड़कन बन जाती है और दुनिया कुछ पलों के लिए ठहर सी जाती है। डांस करते हुए मैं इस पीक को हमेशा महसूस करता हूँ क्योंकि उन पलों में मैं खो जाता हूँ। नृत्य केवल शरीर की ही नहीं बल्कि मन की थरपी भी होती है। नृत्य वो ताकत है, जो तनाव को भी ऊर्जा में बदल देता है। जैसे ही आप डांस करना शुरू करते हैं, शरीर में जितनी भी नकारात्मकता है, वह अपने आप रिलीज होने लगती है और आप बहुत हल्का महसूस करते हैं। अगर आप रूटीन में अपनी पसंद का कोई भी डांस शामिल करें तो यह आपको फ्रीडम का एहसास कराएगा। डांस के हर बीट पर आप अपने तनाव को कम करते जाते हैं। यह आपको शारीरिक रूप से तो फिट रखता ही है, साथ ही सोच व विचारों को सकारात्मक भी बनाता है। जब भी मैं तनाव महसूस करता हूँ तो डांस करके खुद को हल्का और खुश महसूस करता हूँ। इसलिए मैं तो यही सबसे कहता हूँ कि हर इंसान को डांस जरूर करना चाहिए। *

नृत्य अध्यात्म से जोड़ता है और ईश्वर के करीब ले जाता है

ऐश्वर्य हरीश, भरतनाट्यम नृत्यांगना

मेरे लिए नृत्य केवल जीवन का हिस्सा नहीं है बल्कि मेरा जीवन ही है। मैं अपने परिवार की पांचवीं पीढ़ी से हूँ, जो नृत्य कला से जुड़ी है। नृत्य मेरे खून में रचा-बसा है। बचपन से मैं देखती आ रही हूँ कि यह मेरे साथ इस तरह जुड़ गया कि कभी लगा ही नहीं कि मैं कुछ अलग काम कर रही हूँ। नृत्य ने मुझे अनुशासन और धैर्य सिखाया। खुद को समझना सिखाया। जैसे-जैसे मैं नृत्य करती गई यह मेरे लिए केवल नृत्य नहीं रहा बल्कि साधना बन गया। नृत्य हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। नृत्य अध्यात्म से जोड़ता है और ईश्वर के करीब ले जाता है। कई बार लगता है कि जो मैं शब्दों में नहीं कह पाती, वह नृत्य अपने आप कह देता है। नृत्य में जो पीक स्टेट होती है, उसे शब्दों में कह पाना मुश्किल है। क्योंकि उस समय आप नृत्य कर नहीं रहे होते बल्कि नृत्य बन जाते हैं। एक अलग ही स्थिति होती है, जहां अहंकार धीरे-धीरे मिट जाता है। उस समय न तो समय का, न दर्शकों का और न ही मंच का बोध रहता है। बस लय भाव और एक प्रवाह रह जाता है। कभी लगता है कि बाहर और भीतर का भेद ही मिट गया है और जो कुछ भी हो रहा है, वह अपने आप हो रहा है और आप उसका आनंद ले रहे होते हैं। अगर आप कृष्ण और यशोदा का संवाद दिखा रहे हैं तो आप ही कृष्ण, आप ही यशोदा हो जाते हैं। यह बहुत गहरा आनंद होता है। यह वह पल होता है, जहां कला साधना और अध्यात्म, तीनों एक हो जाते हैं। नृत्य शरीर का संतुलन अभ्यास भी है। इससे स्ट्रेच और स्ट्रेमिना बढ़ता है। नृत्य की मुद्राएं शरीर में एक संतुलन उत्पन्न करती हैं और धीरे-धीरे यही संतुलन आपके जीवन जीने के तरीके और व्यवहार में भी आता है। जब आप नियमित रूप से नृत्य करते हैं तो एकाग्रता अपने आप बढ़ने लगती है। मन स्थिर हो जाता है। जीवन में तनाव भी कम होने लगता है। मेरा मानना है कि कला इंसान को सकारात्मक बनाती है। जब आप संगीत के साथ थोड़ी देर लय ताल में थिरकते हैं तो आपकी ऊर्जा अपने आप बदलने लगती है। *



मोबाइल स्क्रीन पर सिमटता सिनेमा माइक्रो-सीरीज का चढ़ता सूरज!



न्यू ट्रेड
गौरव द्विवेदी

फिल्म, टीवी सीरियल, वेब-सीरीज और शॉर्ट फिल्मों के बाद अब माइक्रो-सीरीज का ट्रेंड तेजी से पॉपुलर हो रहा है। इसके पॉपुलर होने की वजह वजहें हैं। यह किस तरह से एंटरटेनमेंट स्टाइल को पूरी तरह बदल रहा है, इस पर एक नजर।



भारत में मनोरंजन की दुनिया एक दिलचस्प मोड़ पर है। सिनेमा अब बड़े पर्दे से निकलकर मोबाइल स्क्रीन में सिमट रहा है। इस बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा है माइक्रो-सीरीज और वॉट्सएप वीडियो। यह केवल एक ट्रेंड नहीं, बल्कि एक वैश्विक बदलाव है। अनुमान है कि 2025 तक दुनिया के कुल इंटरनेट ट्रैफिक का लगभग 82% वीडियो कंटेंट का रहा, जिसमें शॉर्ट, 'टुकटुक', 'कॉमिंग' भी 2-5 मिनट के एपिसोड्स के साथ तेजी से उभर रहे हैं, और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार हाल के महीनों में ही 150 मिलियन व्यूअर्स ने माइक्रो-सीरीज कंटेंट देखा, जबकि रोजाना एपिसोड व्यूज 100 मिलियन तक पहुंच गए। अन्य देशों में भी यह रुढ़ी पॉपुलैरिटी: चीन इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां 'डुआंजु' (माइक्रो ड्रामा) इंस्टी टेजी से एक समानांतर फिल्म उद्योग बन चुकी है। वहीं अमेरिका में भी 'ड्रामा बॉक्स' जैसे प्लेटफॉर्म करोड़ों व्यूअर्स के साथ पारंपरिक ओटीटी को चुनौती दे रहे हैं। इतना ही नहीं, यूट्यूब शॉर्ट्स पर रोजाना दो सौ अरब व्यूज तक का आंकड़ा सामने आता है, जो इस बदलाव की गति को दर्शाता है।



वॉट्सएप वीडियो का दबदबा सबसे ज्यादा था। वह रहा शॉर्ट वीडियो मार्केट: इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्मों से देखने की आदत को पूरी तरह बदल दिया है। अब दर्शक 'देखता' नहीं, बल्कि 'स्कॉल' करता है, और हर स्कॉल में कहानी फिट होनी चाहिए। भारत में इस बदलाव की गति और भी तेज है। एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में 100 मिलियन (10 करोड़) से अधिक दर्शक पहले ही माइक्रो-ड्रामा कंटेंट देख रहे हैं। यानी यह अब मनोरंजन की मुख्यधारा बन चुका है। वैश्विक स्तर पर शॉर्ट वीडियो मार्केट का आकार 2026 में लगभग 59 अरब डॉलर आंका जा रहा है, जो 2033 तक बढ़कर 118 अरब डॉलर से ज्यादा हो सकता है। सिर्फ वॉट्सएप वीडियो सेगमेंट ही 2025 में लगभग 67% हिस्सेदारी तक पहुंच चुका है, जो इस फॉर्मेट की ताकत को दर्शाता है।

घरेलू प्लेटफॉर्म की बड़ी भूमिका: भारत में इस उभार के पीछे घरेलू प्लेटफॉर्मों की बड़ी भूमिका है। 'कुकु टीवी' जैसे प्लेटफॉर्म ने वॉट्सएप माइक्रो-ड्रामा को एक नई पहचान दी है। इसके 1.2 करोड़ (12.7 मिलियन) से अधिक डाउनलोड्स हो चुके हैं, जबकि इसके ऑडियो प्लेटफॉर्म 'कुकु एफएम' ने 1 करोड़ से अधिक पेड सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। इसी तरह 'मोज' और 'जोश' जैसे भारतीय शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्मों ने मिलकर 300 मिलियन (30 करोड़) से अधिक यूजर इकोसिस्टम तैयार कर लिया है। नई श्रेणी के प्लेटफॉर्म जैसे 'क्विक टीवी',



तेजी से बढ़ रहा ट्रेंड: भारत में यह ट्रेंड और तेजी से बढ़ रहा है। सस्ते डेटा, 5जी और स्मार्टफोन के प्रसार ने इसे जन-आंदोलन बना दिया है। टियर-2 और टियर-3 शहरों में युवा दर्शक अब माइक्रो-सीरीज को न केवल देख रहे हैं, बल्कि बना भी रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से भी यह मॉडल बेहद आकर्षक है। जहां एक पारंपरिक टीवी शो के एक एपिसोड पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वहीं एक वॉट्सएप सीरीज का पूरा सीजन कुछ लाख में बन सकता है। हालांकि, इस तेजी के साथ कुछ खतरों भी हैं। जैसे-कहानियों की गहराई कम हो रही है और एल्गोरिथम यह तय कर रहा है कि क्या बदलाव अस्थायी नहीं है। यह भारतीय मनोरंजन उद्योग के नए ढांचे की नींव है। आने वाले समय में बड़ी फिल्में और वेब-सीरीज पहले माइक्रो-फॉर्मेट में अपनी लोकप्रियता साबित करेगी। अब सिनेमा देखा नहीं जाता, स्कॉल किया जाता है। और जो स्कॉल में फिट हो जाए, वही नया सिनेमा है। * (लेखक फिल्म पॉलिसी के जानकार हैं)

खंभय / सूर्य कुमार पांडेय

जब वही धंधा शहर में रह कर भी किया जा सकता है, तो बीहड़ में छिपकर क्यों रहा जाए? एक रोज गम्बर की शांतिर अंतरात्मा से आवाज आई, 'रे मुख, परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। तू देखता ही होगा कि राजनेता आए दिन अपनी दलीय निष्ठाएं बदलते रहते हैं। बयानवीर अपने बयान बदल लेते हैं। सरकार में मंत्रियों के विभाग बदल जाते हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले होते रहते हैं। जिनका स्थानांतरण किया जाता है, वे जब दूसरी जगहों पर तैनाती पाते हैं तो क्या उनके गुण-धर्म बदल जाते हैं? भ्रष्टाचारी को कहीं भी भेज दो, वह भ्रष्टाचारी ही रहेगा। उसे सदाचारियों की भीड़ के बीच बांध दो, तब भी वह स्वयं तो सुधरेगा नहीं, वहां के लोगों को अपने जैसा जरूर बना लेगा। यह काम तो तू ही कर सकता है। तू स्वभाव से डकैत है, डकैत ही रहेगा। इसलिए स्थान-परिवर्तन कर ले और अपने कर्म-परिवर्तन को यथावत बना रहने दे। चल, सम्मानित जिंदगी जीने की राह पकड़ ले!' जब गम्बर की अंतरात्मा से यह आवाज बार-बार उठने लग गई, तब उसने एक शाम अपने गैंग के सदस्यों का एक पैनाल बनाया और स्वयं एंकर की भूमिका में रहते हुए एक धुआंधार बहस की। एक बहसबाज दस्यु ने कहा, 'डकैती डालना घृणित कार्य है। अब हमें वैकल्पिक रोजगार की तलाश करनी चाहिए।' यह सुनकर दूसरे दुर्दांत बहसबाज ने धोर आपत्ति की, 'तुम बकवास कर रहे हो। डकैती तो हमारा पवित्र धर्म है। कोई हमारे धर्म को लेकर ऐसी बात कहेगा, तो मैं उसका धर्म कलम कर दूंगा।' तीसरे बहसबाज डकैत ने कहा, 'अब डकैती के धंधे में पहले जैसी बरकत नहीं रही। मैं कल सरदार के आदेश पर एक गांव में गया था। वहां पर पहले हमारे जाते ही लोग अपने घरों से अनाज की बोरायें लाकर हमारे चरणों में धर दिया करते थे। इस

शांतिर अंतरात्मा गम्बर की

गम्बर की अंतरात्मा ने झकझोरते हुए कहा, 'तू स्वभाव से डकैत है, डकैत ही रहेगा। इसलिए स्थान-परिवर्तन कर ले और अपने कर्म-परिवर्तन को यथावत बना रहने दे। चल, सम्मानित जिंदगी जीने की राह पकड़ ले!'



बार मुझे पता चला कि सभी लोग खुद खाली थैले लेकर पांच किलो अनाज पाने के लिए सरकारी गल्ले की दुकानों पर गए हुए थे।' चौथे बहसबाज डकैत ने कहा, 'सरदार, अब आप ही बताइए, आपका निर्णय ही हमें दिशा दिखा सकता है।' गम्बर ने बहस का समापन करते हुए कहा, 'मैंने तुम सबकी बातें ध्यानपूर्वक सुनी हैं और इस निर्णय पर पहुंचा हूँ कि हमें अपना यह डकैती वाला धंधा छोड़ देना चाहिए और दूसरे वैकल्पिक रास्ते तलाशने चाहिए। हम इस घटाटोप जंगल में अड़े बदलते-बदलते

आजिज आ चुके हैं। ऊपर से हमेशा पुलिस का डर बना रहता है। साथ में मुखबिरी के खतरे तो हैं ही। क्या पता, अपने ही गैंग का कौन बंधा कब दगा दे जाए और हम सब एक दिन किसी एनाकांडर में मार दिए जाएं। क्यों कालिया?' तब कालिया कहने लगा, 'सरदार, मैंने आपका नमक खाया है। घोर महंगाई में आपने हमें नीबू भी खिलाए हैं। आपकी कृपा बनी रहेगी तो हम आपके फार्म हाउस में बैठकर कल पिज्जा-बर्गर भी खाएंगे। वैसे भी यह कोई हमारा पुरतैनी धंधा है नहीं कि इसे छोड़ देने में डकैतों की बिरादरी में हमारी नाक काट जाएगी। हम बीहड़ की जगह शहर में रहकर भी वहां के सम्मानित डकैतों जैसी शानदार जिंदगी जी सकते हैं।' उन सभी की बातें सुनकर गम्बर ने खैनी मलते हुए पूछा, 'अरे ओ सांभा, तू क्यों चुप है? तू भी तो बता कि हमें क्या करना चाहिए।' सांभा बोला, 'सरदार, आपने जो फैसला लिया है, वही सही है।'

इसके बाद उस इलाके में अपने बर्बर आतंक के चलते कुख्यात हो चुका गम्बर अब एक शरीफ डकैत बन चुका है। यूं भी कुख्यात और विख्यात होने में कोई खास अंतर नहीं होता है। मात्र जंगल और नगर का फर्क होता है। तो गम्बर और उसका गैंग अब सम्मानित डकैत बन चुके हैं। अब उस पर सरकारें इनाम नहीं घोषित करती हैं। अब वह खुद सरकारों को मदद-इमदाद करता है। अब पुलिस भी उसे ठोकने की फिराक में नहीं रहती, अलबत्ता वह उसे ही सलाम ठोकती है। लेकिन कल गम्बर के साथ एक बुरी बात हो गई। उसके घर पर सीबीआई और इंडी का छापा पड़ गया। उसकी हवेली पर बुलडोजर चल गया। गम्बर अपने पूरे गैंग के साथ जेल में है और अपनी शांतिर अंतरात्मा को तलाश रहा है। वह मिल जाए तो उसे गोली मार देगा। लेकिन गम्बर यह बात नहीं जानता है कि उसकी अंतरात्मा तो डकैती के धंधे में आते ही मर चुकी थी। यह उसका आंतरिक भय था, जिसको वह गलती से अपनी शांतिर अंतरात्मा समझ बैठा था। *

लघुकथा / शीला श्रीवास्तव

एहसास



सड़क पर दूर से ही पुलिस वालों की चेकिंग होती देख कमलेश ने अपनी मोटरसाइकिल वापस घुमा ली। 'क्या हुआ, गाड़ी क्यों वापस घुमा रहे हो?' पीछे बैठे दोस्त ने पूछा। 'आगे चेकिंग चल रही है। इन पुलिस वालों को कोई काम धंधा है नहीं। जब देखो चौराहे पर खड़े होकर चेकिंग करना शुरू कर देते हैं। हेल्मेट क्यों नहीं पहना? लाइसेंस कहाँ है? बिना नंबर की गाड़ी कैसे चला रहे हो? डेरों सवाल पूछने लगते हैं। उनको तो बस लोगों को तंग करना होता है और कुछ नहीं।' कमलेश झुंझलाते हुए बोला। 'ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो तो बेचारे अपनी ड्यूटी करते हैं।' दोस्त ने कमलेश को समझाने की कोशिश की। 'अरे, काहे की ड्यूटी! इनको तो बस अपनी जेब भरनी होती है और कुछ नहीं।' कमलेश खीझ भरे स्वर में बोला।

इस घटना के कुछ दिनों बाद कमलेश के बेटे का एक्सिडेंट हो गया। बिना नंबर वाली गाड़ी चला रहे किसी टपो ड्राइवर ने पीछे से उनके बेटे की बाइक पर जोरदार टक्कर मार दी थी। हेल्मेट न पहनने की वजह से उनके बेटे के सिर पर गंभीर चोट लग गई थी। 'ये पुलिस वाले आखिर करते क्या हैं? बिना लाइसेंस, नंबर वाले अवैध वाहनों के खिलाफ, चेकिंग करके उन पर नियंत्रण क्यों नहीं करते?' कमलेश की पत्नी बिचलते हुए अपने पति से पूछ रही थी। आज कमलेश को अपनी उस दिन की गलती का एहसास हुआ। अब उसे पुलिस वालों की चेकिंग का महत्व समझ में आ गया था। *

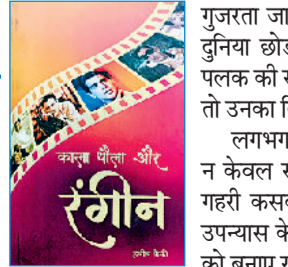
कथा साहित्य में किस्सागोई का एक विशिष्ट स्थान रहा है।

कारण इसका यह है कि किस्सागोई में बात से बात निकलती चली जाती है। इस तरह इसमें रोचकता के साथ ही साथ जिज्ञासा भी बनी रहती है। वरिष्ठ कथाकार और शांतिर हबीब केफ़ी का नया उपन्यास 'काला, धौला और रंगीन' इसी किस्सागोई शैली में लिखा गया एक उम्दा उपन्यास है। इस कथा की मुख्य पात्र पलक है। फिल्मि दुनिया की यह सफल अभिनेत्री, जब एक साहित्यकार के आगे खुलने लगती है तो प्रायः बंद ही रहने वाली यह स्त्री जिंदगी की कई परतें खोलती चली जाती है। पता चलता है कि एक नामी राजघराने से ताल्लुक रखने वाली यह अभिनेत्री अपने क्षेत्र, फिल्मि दुनिया के साथ ही साहित्य, कला और संगीत

पुस्तक चर्चा / कुलदीप सिंह भाटी

ग्लैमर की दुनिया का किस्सा

आदि से भी बड़ी हद तक लगाव और जुड़ाव रखती है। संवेदनशील अभिनेत्री पलक इस बीच सहज ही अपनी जिंदगी की परतें भी खोलती चली जाती है तो पता चलता है कि एक्सट्रा जूनियर आर्टिस्ट से नामी अभिनेता बने, समीर से यह गहरे प्रेम में है। मानवीय गुणों से संपन्न नैसर्गिक अभिनेता समीर मस्त मोला स्वभाव के कारण पलक के प्रेम का ठीक-ठीक जवाब नहीं दे पाता। समय अपनी गति से



पुस्तक: काला, धौला और रंगीन (उपन्यास), लेखक: हबीब केफ़ी, मूल्य: 299 रुपए, प्रकाशक: कोटिल्य बुक्स, दिल्ली

गीत / कृष्ण बिहारी

सबकी अपनी सीमाएं हैं

कोई साथ कहां तक देगा सबकी अपनी सीमाएं हैं, हर कोई रीता-रीता है कड़ने को सभी ग्रथाएं हैं। अतृप्त जिंदगी छूँछी-सी ऊपर से दिखती सजी-धजी गर पास बुलाकर बैठा लो तो लगती कितनी बुझी-बुझी भ्रम के सात में सभी यज्ञी भ्रम देता परधान बनाए हैं। पेट काट जो तन टंकती थी वही भरे पेट अब नंगी है नाच-नाचकर करे सभ्यता दुनिया यह रंग-बिरंगी है रंग-रोगन से पुते हुए सब भीतर-भीतर मुरझाए हैं। जब देह में मन अनुपस्थित हो औ' रूप गिष्ट केवल पीड़ा मेलों में भी तनखई हो औ' प्राण रीन हो हर क्रीड़ा तो बात समझनी क्या मुश्किल अपनी से भेद छिपाए हैं। कोई साथ कहां तक देगा सबकी अपनी सीमाएं हैं।

डेयरी से 26 हजार गांवों को जोड़ने और प्रतिदिन 52 लाख किग्रा दुग्ध संकलन का लक्ष्य

हरिभूमि न्यूज गोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि दुग्ध उत्पादन से जुड़ी गतिविधियां किसानों की आय बढ़ाने में प्रभावी रूप से सहायक हैं। किसानों की आय दोगुना करने के लिए किसान कल्याण वर्ष में राज्य सरकार डेयरी गतिविधियों को विशेष रूप से प्रोत्साहित कर रही है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने प्रदेश के दुग्ध संघों को दिए जा रहे सहयोग से दुग्ध संकलन में वृद्धि हुई है। किसानों को भी दूध के बेहतर दाम मिल रहे हैं। सहकार के भाव से डेयरी गतिविधियों का विस्तार किया जा रहा है।

दुग्ध समितियों में महिला सदस्यता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ये निर्देश मप्र स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की राज्य स्तरीय संचालन समिति की द्वितीय बैठक में दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेयरी सहकारी कवरेज के विस्तार और सुदृढ़ीकरण, नई डेयरी प्रसंस्करण, उत्पाद निर्माण और पशु चारा संयंत्र के आधुनिकीकरण, डेयरी वैल्यू चेन के डिजिटलाइजेशन, पारदर्शिता और दुग्ध उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए समय-समया निर्धारित करते हुए कार्ययोजना बनाई जाए। डेयरी विकास योजना के तहत 26 हजार गांवों को जोड़ने, प्रतिदिन दुग्ध संकलन 52 लाख किग्रा तक करने का लक्ष्य रख, गतिविधियां संचालित की जाएं। मुख्यमंत्री निवास के समतल भवन में हुई बैठक में सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री लखन पटेल, वरिष्ठ विधायक एवं अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मुख्य सचिव अनुराग जैन तथा अध्यक्ष नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड मीनेष शाह मौजूद थे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन की अध्यक्षता में हुई स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक

खास बातें

- दुग्ध क्षेत्र में पारदर्शिता और ब्रांड सुदृढ़ीकरण पर होगा विशेष फोकस
- जिला स्तर पर कार्यक्रमों में होगा आदर्श पशुपालकों का सम्मान



हानि को कम करने
मानक संचालन
प्रक्रिया लागू

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में दूध की गुणवत्ता में सुधार, उत्पादन में हानि को कम करने और एक समान उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया लागू की गई है। इंदौर में स्थापित 30 मीट्रिक टन क्षमता का दुग्ध चूर्ण संयंत्र आरंभ किया जा चुका है। शिवपुरी में 20 हजार लीटर क्षमता के डेयरी संयंत्र और ग्वालियर डेयरी संयंत्र के सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर है।

उत्पादों की पहुंच का अधिक से अधिक विस्तार किया जाए: सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के दुग्ध क्षेत्र में अनुभव का लाभ राजधानी से लेकर ग्राम स्तर तक सुनिश्चित किया जाए। दूध और दुग्ध उत्पादों के बिक्री में सुधार के लिए ब्रांड सुदृढ़ीकरण और नई पैकेजिंग डिजाइन कर उत्पादों की पहुंच का अधिक से अधिक विस्तार किया जाए। मुख्यमंत्री ने दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और विभिन्न दुग्ध उत्पादों के निर्माण के लिए किसानों को नवाचार करने के लिए प्रेरित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदर्श पशुपालकों को सम्मानित करने, दूधारू पशुओं की प्रदर्शनी आयोजित करने और डेयरी के संबंध में सूचना सम्प्रेषण के लिए जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

701 निष्क्रिय दुग्ध समितियों को किया गया क्रियाशील

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा एमपी स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और दुग्ध संघों का कार्यअनुबंध करने के बाद वर्ष 2025-26 में 1752 नई दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया तथा 701 निष्क्रिय दुग्ध समितियों को क्रियाशील किया गया। प्रदेश में प्रतिदिन 9 लाख 67 हजार किग्रा दुग्ध संकलन किया जा रहा है, साथ ही 153 नवीन बल्क मिल्क कूलर की स्थापना की गई है। दूध और दूध उत्पादों का क्रेडिट पर विक्रय बन्द कर दिया गया है। प्रदेश में दुग्ध संकलन मोबाइल एप से शुरू किया जा रहा है।

डॉ. यादव ने जनता को दिया संदेश: किसान कल्याण वर्ष में मप्र को कृषि के क्षेत्र में ले जाएंगे नई ऊंचाइयों तक

किसानों से जो वादा किया, वह पूरा करके भी दिखाया कृषकों की समृद्धि ही मप्र की है असली ताकत: सीएम

हरिभूमि न्यूज गोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मप्र का समृद्ध किसान ही विकसित भारत 2047 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सच्चा वादा और पक्का काम, यही हमारी सरकार का संकल्प है। हमने किसानों से जो वादा किया, वह पूरा करके भी दिखाया है। जब हमारे खेतों से लेकर कारखाने तक समृद्धि आएगी। तभी तो हमारे किसान भी समृद्ध और खुशहाल होंगे। मैं प्रदेश के सभी किसान भाइयों-बहनों को आश्चर्य करता हूँ कि उनकी मेहनत, पसीना और आपका भविष्य हमारी सरकार को सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुक्रवार को प्रदेश की जनता के नाम यह संदेश दिया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि मैं अपने आपको सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे मप्र की सेवा का अवसर मिला है और उसी सेवा भाव से मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ। जब से मैंने मुख्यमंत्री के रूप में इस महत्वपूर्ण पद की शपथ ली है, तब से पूरा मप्र ही मेरा परिवार है, प्रदेशवासियों का सुख ही मेरा सुख है और उनकी दुख ही मेरा दुख है। इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में समर्पित किया गया है।

सच्चा वादा और पक्का काम, यही मप्र सरकार का है संकल्प



गेहूँ उपार्जन का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 100 लाख मीट्रिक टन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेशवासियों से यह साझा करना चाहता हूँ कि प्रदेश में रिकॉर्ड गेहूँ उत्पादन को देखते हुए हमने केंद्र सरकार से खरीदी की सीमा बढ़ाने का आग्रह किया था। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि किसानों के हित को सर्वोपरि रखते हुए गेहूँ उपार्जन का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। यह 22 लाख मीट्रिक टन की अभूतपूर्व वृद्धि न केवल हमारे किसानों की मेहनत का सम्मान है।

हर परिस्थिति में आखिरी दम तक रहेंगे अन्नदाताओं के साथ: सीएम

प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में निरंतर नवाचार मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में हम निरंतर नवाचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने दुग्ध उत्पादन से लेकर संकलन बढ़ाने के भी प्रयास किए हैं और 1752 नई दुग्ध समितियों का गठन किया है। हमारा प्रतिदिन का दूध संकलन 10 लाख किलोग्राम से अधिक पहुंच गया है और दुग्ध उत्पादक किसानों को 1600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया गया है। किसानों को अब दूध का दाम प्रतिकिलो 8 से 10 रुपए बढ़कर मिल रहा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल युद्ध की स्थिति के बावजूद प्रदेश में यूरिया की उपलब्धता 5.90 लाख मीट्रिक टन है, जो पिछले साल से भी अधिक है। इसी प्रकार अन्य उर्वरक के भी पर्याप्त भंडारण किए गए हैं।

गेहूँ उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग पूरी तरह से खोली जा चुकी है

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मुझे यह बताते हुए भी अत्यंत प्रसन्नता है कि आज से पूरे प्रदेश के छोटे-बड़े सभी किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग पूरी तरह से खोली जा चुकी है। गेहूँ उपार्जन अब सप्ताह में 6 दिन होगा और शनिवार को अवकाश नहीं रहेगा। साथ ही 30 अप्रैल तक होने वाली स्लॉट बुकिंग को अब 9 मई तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने भू-अर्जन को भी लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब किसानों को उनकी भूमि के बदले 4 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। अब किसानों को रात के बदले दिन में ही सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली मिलेगी।

मुख्यमंत्री से मिले भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी



भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से शुक्रवार को भारतीय विदेश सेवा के वर्ष 2025 बैच के चार प्रशिक्षु अधिकारियों ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समतल भवन में सीटने बैठ कर की। मुख्यमंत्री ने सभी प्रशिक्षु अधिकारियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देकर स्मृति चिन्ह भी दिए। इस अवसर पर आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल के संचालक मुर्जीबुरहमान खान सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

दिल्ली में कॉमेडी नाटक बलावपुर की रूपकथा का मंचन तीन मई को

नई दिल्ली। VRIKSH The Theatre द्वारा Ballavpur Ki Roopkatha, प्रख्यात नाटककार Badal Sircar की एक मनोरंजक हॉरर नाटक का मंचन तीन मई को किया जाएगा। जिस प्रकार एक वृक्ष अपनी जड़ों को धरती में गहराई से जमाए रखते हुए आकाश को छूने का सपना देखता है, उसी प्रकार VRIKSH रचनात्मकता को पोषित करते हुए कलात्मक उत्कृष्टता की ओर अग्रसर है। VRIKSH The Theatre एक सशक्त और सक्रिय रंगमंच समूह है, जिसकी स्थापना 16 अगस्त 2015 को Kerala Club में हुई थी। "VRIKSH" (अर्थात् वृक्ष) नाम विकास, समावेशिता और कलात्मक अभिव्यक्ति का प्रतीक है। अपने खुले और स्वागतपूर्ण स्वरूप के साथ, VRIKSH थिएटर कला के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास करता है। धर्म, जाति और राजनीति की सीमाओं से परे। यह दिल्ली के रंगकर्मीयों के लिए एक साझा मंच के रूप में कार्य करता है, सहयोग को बढ़ावा देता है और प्रदर्शन कला की भावना का उत्सव मनाता है।

सिरूपुरा में पेयजल की समस्या का निवारण, त्वरित बहाल हुई पेयजल व्यवस्था, मंत्री उड़के ने की कार्रवाई

हरिभूमि न्यूज गोपाल

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उड़के ने नर्मदापुरम के सिवनी मालवा के ग्राम सिरूपुरा में पेयजल समस्या की जानकारी मिलते ही तत्काल संज्ञान लेते हुए विभागीय अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री के निर्देशों के अनुपालन में विभागीय अमला तुरंत सक्रिय हुआ और मौके पर पहुंचकर आवश्यक सुधार कार्य प्रारंभ किया गया। निरीक्षण के दौरान तकनीकी कारणों एवं जल स्तर में कमी के चलते प्रभावित हैंडपंपों को प्राथमिकता से दुरुस्त किया गया। सभी बंद पड़े हैंडपंपों का सुधार कार्य पूर्ण कर उन्हें पुनः चालू कराया गया। साथ ही नलकूप में आवश्यक पाइप बढ़ाकर नलजल योजना को भी पुनः क्रियाशील किया गया।

परिजनों ने लगाया प्रताड़ना और अमर व्यवहार का गंभीर आरोप

हरिभूमि न्यूज रायपुर

राजधानी की सेंट्रल जेल में महिला बंदी द्वारा आत्महत्या की कोशिश की खबर सामने आने के बाद जेल प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए हैं। महिला कैदी आशिमा राव के हाथ की नस काटने की घटना ने जेल सुरक्षा और अंदरूनी व्यवस्थाओं को लेकर नई बहस छेड़ दी है। मिली जानकारी के मुताबिक, महिला प्रकोष्ठ में बंद कैदी ने कथित तौर पर मानसिक तनाव के बीच आत्मघाती कदम उठाया। घटना के बाद जेल प्रशासन ने उसे तत्काल उपचार उपलब्ध कराया, जहां प्राथमिक इलाज के दौरान उसके हाथ में टांके लगाए गए। घटना कुछ दिन

महिला कैदी के सुसाइड के प्रयास से सेंट्रल जेल में मचा हड़कंप



पुरानी बताई जा रही है, लेकिन मामला सामने आने के बाद परिजनों में नाराजगी बढ़ गई है। परिवार ने जेल के भीतर प्रताड़ना और अमर व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि तलाशी और चेंकिंग के दौरान महिला बंदी के साथ

जेल प्रशासन ने किया आरोपों से इकार

इधर जेल प्रशासन ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि बंदी सुरक्षित है और स्थिति नियंत्रण में है। अधिकारियों के मुताबिक नियमों के तहत कार्रवाई की गई थी और घटना को लेकर सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि संबंधित महिला पिछले करीब छह महीने से एक आपराधिक मामले में जेल में बंद है। अब इस पूरे प्रकरण में जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि आत्महत्या प्रयास के पीछे वास्तविक वजह क्या थी।

अफवाहों के बीच खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने स्पष्ट की स्थिति राज्य में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध

एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं

हरिभूमि न्यूज रायपुर

छत्तीसगढ़ में पेट्रोल-डीजल की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का पर्याप्त भंडारण मौजूद है और आपूर्ति की निर्यात स्पष्ट करते हुए कहा है कि राज्य में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक घबराहट से बचें। विभाग के अनुसार पश्चिम एशिया में बने हालात को देखते हुए राज्य सरकार



लगातार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संपर्क में है, ताकि प्रदेश में ईंधन आपूर्ति निर्बाध बनी रहे। अधिकारियों ने बताया कि एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडारण मौजूद है और आपूर्ति की निर्यात स्पष्ट करते हुए कहा है कि राज्य में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक घबराहट से बचें। विभाग के अनुसार पश्चिम एशिया में बने हालात को देखते हुए राज्य सरकार

राज्य और जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष सक्रिय

खाद्य विभाग के मुताबिक फिलहाल प्रदेश में लगभग 22 दिनों की जरूरत के बराबर पेट्रोल और 15 दिनों की खपत के लिए डीजल उपलब्ध है। विभाग ने कहा कि किसी भी तरह के संकट की स्थिति नहीं है और उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। जमाखोरी और कालबाजारी पर रोक के लिए जिलों में आकस्मिक निरीक्षण और छापेमारी भी जारी है। राज्य और जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष सक्रिय हैं, वहीं शिकायतों के लिए विभागीय कॉल सेंटर भी संचालित किया जा रहा है। हाल ही में तीनों अंचल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा रिटेल आउटलेट से डीजल खरीदने से अस्थायी ढाबा बनने की बात सामने आई, जिस पर कंपनियों को मांग के अनुरूप सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

जापान की तकनीकी दक्षता को प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए बताया महत्वपूर्ण जापान के प्रतिनिधि मंडल ने की मुख्यमंत्री साय से मुलाकात

विदेशी निवेश और औद्योगिक विस्तार को मिलागी नई दिशा

हरिभूमि न्यूज रायपुर

छत्तीसगढ़ में विदेशी निवेश और औद्योगिक विस्तार को नई गति देने की दिशा में शनिवार को महत्वपूर्ण पहल देखने को मिली, जब जापान के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर निवेश, तकनीकी सहयोग और औद्योगिक संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री निवास में हुई इस बैठक में प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल, नई औद्योगिक नीति और जापानी तकनीक के



उपयोग पर विशेष फोकस रहा। बातचीत के दौरान औद्योगिक परियोजनाओं, रोजगार सृजन और तकनीकी साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगोन्मुखी नीतियों के जरिए छत्तीसगढ़ को वैश्विक निवेशकों के लिए मजबूत डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर रही है। उन्होंने जापान की तकनीकी दक्षता को प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए सहयोग बढ़ने पर भरोसा जताया।

रोजगार के नए अवसर के साथ औद्योगिक आधार मजबूत होगा

बैठक में यह भी माना गया कि जापानी निवेश और तकनीकी भागीदारी से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे और औद्योगिक आधार मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ने अपने जापान दौरे के अनुभवों का जिक्र करते हुए निवेश संबंधों को और मजबूत करने की बात कही। जापानी प्रतिनिधिमंडल ने भी छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति और निवेश अनुकूल वातावरण की सराहना की। प्रतिनिधियों ने राज्य में उद्योग विस्तार और मजबूत निवेश बढ़ाने की इच्छा जताई। मुलाकात के दौरान उद्योग, लॉजिस्टिक्स और खनन क्षेत्र से जुड़े कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक को छत्तीसगढ़ और जापान के बीच आर्थिक सहयोग की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

भारत मजबूत घरेलू विकास के दम पर बेशक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, लेकिन इसमें कमजोरियाँ भी हैं। एक ओर अमेरिका-ईरान युद्ध ने उद्योगों में आपूर्ति बाधाओं, तेल और एलपीजी की आपूर्ति पर प्रतिबंध और कच्चे तेल व कच्चे माल की ऊंची कीमतों के कारण आयातित महंगाई का डर बढ़ा दिया है। वहीं, दूसरी ओर कमजोर मानसून के शुरुआती संकेत से खेती की लागत और उत्पादन दोनों पर खतरा बढ़ गया है। यदि कमजोर मानसून से फसल उत्पादन प्रभावित होता है तो खाद्य कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी होगी, जो महंगाई को और बढ़ा सकती है। स्वाभाविक है कि इससे देश के समूचे आर्थिक तंत्र और चक्र पर खराब असर पड़ेगा। मौसम विभाग ने इस साल मानसून के 'सामान्य से कम' यानी करीब 92 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। माना जा रहा है कि इससे अल नीनो की स्थिति उत्पन्न होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गिरावट आ सकती है। उर्वरकों की कमी इस स्थिति को और खराब कर सकती है, जिससे इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में खाद्य कीमतें, खासकर दालें, तिलहन और जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं महंगी हो सकती हैं। कह सकते हैं कि यह समय कृषि मंत्रालय के लिए केवल नीति निर्धारण का नहीं, बल्कि त्वरित क्रियान्वयन का है। *इन्हीं हालातों की पड़ताल करता आजकल का यह खास अंक...*

कमजोर मानसून व युद्ध के कॉफटेल से बढ़ा खतरा



विश्लेषण

सेंट्रल डेस्क

भारत में मौसमी वर्षा दीर्घकालिक औसत (एलपीए) के लगभग 92% रहने का अनुमान है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार कमजोर मानसून पहले से ही ऊंचे कच्चे तेल के दाम और उर्वरक आपूर्ति में बाधाओं के असर को और बढ़ा सकता है। मध्य पूर्व के संघर्ष का असर उसकी अवधि पर निर्भर करेगा, लेकिन आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएं तुरंत खत्म नहीं होंगी, माले ही अमेरिका और ईरान युद्ध समाप्त करने पर सहमत हो जाएं। यदि कमजोर मानसून से फसल उत्पादन प्रभावित होता है तो खाद्य कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी होगी, जो महंगाई को और बढ़ा सकती है।

मजबूत घरेलू विकास के दम पर भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसमें कमजोरियाँ नहीं हैं। अमेरिका-ईरान युद्ध ने उद्योगों में आपूर्ति बाधाओं, तेल और एलपीजी की आपूर्ति पर प्रतिबंध और कच्चे तेल व कच्चे माल की ऊंची कीमतों के कारण आयातित महंगाई का डर बढ़ा दिया है।

इसके बावजूद अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत की घरेलू खपत की कहानी अभी भी मजबूत बनी हुई है। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने इस वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.5% कर दिया है, जबकि अधिकांश अन्य अर्थव्यवस्थाओं के अनुमान घटाए गए हैं। हालांकि भारत के सामने एक नया खतरा सामान्य से कम मानसून का भी है। सवाल यह है कि क्या इससे महंगाई और बढ़ेगी और भारत की विकास गति पर असर पड़ेगा? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान अल नीनो जैसी स्थितियों की आशंका जताई है।

खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी होगी

भारत में मौसमी वर्षा दीर्घकालिक औसत (एलपीए) के लगभग 92% रहने का अनुमान है। एसबीआई रिसर्च के अनुसार यह 2002 के बाद सबसे कम अनुमान है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार कमजोर मानसून पहले से ही ऊंचे कच्चे तेल के दाम और उर्वरक आपूर्ति में बाधाओं के असर को और बढ़ा सकता है। मध्य पूर्व के संघर्ष का असर उसकी अवधि पर निर्भर करेगा, लेकिन आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएं तुरंत खत्म नहीं होंगी, भले ही अमेरिका और ईरान युद्ध समाप्त करने पर सहमत हो जाएं।

यदि कमजोर मानसून से फसल उत्पादन प्रभावित होता है तो खाद्य कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी होगी, जो महंगाई को और बढ़ा सकती है। बता दें कि अल नीनो समुद्र की



सतह के तापमान में वृद्धि की एक प्रक्रिया है, जो प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से में समय-समय पर होती है। इससे वैश्विक मौसम पैटर्न प्रभावित होते हैं। भारत में इसका असर दक्षिण-पश्चिम मानसून को कमजोर करने के रूप में दिखता है, जिससे कम वर्षा और कभी-कभी सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है।

गुणवत्ता और उत्पादन पर प्रभाव

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार अल नीनो के दौरान भारत का मानसून सामान्य से कमजोर रहता है। 1950 के बाद 16 अल नीनो वर्षों में से 7 बार मानसून सामान्य से कम रहा। अर्थशास्त्री युविका सिंघल के अनुसार अगस्त के आसपास अल नीनो होने पर मानसून की शुरुआत सामान्य रह सकती है और खरीफ बुवाई भी ठीक हो सकती है, लेकिन अगस्त-सितंबर में बारिश की कमी से फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। मध्य पूर्व संकट के कारण उर्वरकों की कमी इस स्थिति को और खराब कर सकती है, जिससे इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में खाद्य कीमतें, खासकर दालें, तिलहन और जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं महंगी हो सकती हैं। सरकार द्वारा खुले बाजार

में चावल और गेहूँ के भंडार जारी करने से अनाज की कीमतों पर कुछ नियंत्रण रह सकता है। एसबीआई रिसर्च के अनुसार अल नीनो के कारण टमाटर की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि आलू की कीमतों पर असर नहीं होगा। प्याज की कीमतें सामान्य वर्षों में भी आम लोगों को परेशान करती हैं।

महंगाई और जीडीपी पर असर

एलएंडटी के मुख्य अर्थशास्त्री सचिदानंद शुकला के अनुसार घरेलू फसलों के अलावा कफो, कॉफी, चीनी और पाम ऑयल जैसी वैश्विक वस्तुओं की कीमतों भी बढ़ सकती हैं। ऊंचे कच्चे तेल के दाम ईंधन, उर्वरक और लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ाकर अतिरिक्त दबाव डालते हैं।

कच्चे तेल, गैस, उर्वरक और संभावित रूप से फसलों की आपूर्ति झटकों के कारण महंगाई अपेक्षा से ज्यादा हो सकती है और जीडीपी वृद्धि दर कम हो सकती है। एसबीआई रिसर्च के अनुसार केवल अल नीनो का असर सीमित हो सकता है, लेकिन अल नीनो और सूखे की स्थिति में जीडीपी में 0.20% से 0.65% तक की गिरावट संभव है। पीडब्ल्यूसी इंडिया के रणेश बनर्जी के अनुसार

यदि मानसून में 8-10% की कमी होती है और जलाशयों का स्तर पहले से ही कम है, तो खाद्य महंगाई बढ़ सकती है और इसका असर खरीफ के साथ-साथ रबी फसलों पर भी पड़ सकता है। उनके अनुसार डेडलाइन महंगाई 5% से ऊपर जा सकती है, लेकिन आरबीआई की 6% की सीमा के भीतर रह सकती है। यदि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी होती है, तो सीपीआई महंगाई में 0.20-0.25% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल सरकार ने कीमत बढ़ाने की कोई योजना नहीं बताई है।

आगे का अनुमान

अगर कच्चा तेल 85 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहता है और मानसून सामान्य से कम होता है, तो 2026-27 में सीपीआई महंगाई 4.5% और जीडीपी वृद्धि 6.6% रह सकती है। कमजोर मानसून से ज्यादा खतरा लंबे समय तक ऊंचे कच्चे तेल के दाम से है, क्योंकि इससे व्यापक महंगाई बढ़ सकती है। कमजोर मानसून और ऊंचे कच्चे तेल की कीमतों का संयोजन लोगों की आय और खपत पर दबाव डाल सकता है।

अल नीनो से जोखिम

वित्त वर्ष की पहली छमाही में वृद्धि थोड़ी धीमी हो सकती है। फिर भी, एसबीआई रिसर्च के अनुसार भारत 6.8% से 7.1% की दर से वृद्धि बनाए रख सकता है, जो वैश्विक औसत से बेहतर है। मजबूत घरेलू मांग, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और सेवाओं का क्षेत्र इसकी ताकत बने हुए हैं, जबकि भू-राजनीतिक तनाव, उर्वरक की कमी, आपूर्ति बाधाएं और अल नीनो जोखिम बने हुए हैं। इसके अलावा, सरकार की पूंजीगत व्यय (केपेक्स) पर निरंतर जोर अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है। निजी क्षेत्र का निवेश भी धीरे-धीरे गति पकड़ रहा है। कुल मिलाकर, बाहरी जोखिमों के बावजूद भारत की आर्थिक बुनियाद मजबूत बनी हुई है और मध्यम अवधि में स्थिर वृद्धि की उम्मीद काम है।

खेती की लागत और उत्पादन पर होगा असर



चुनौती
रवि शंकर
स्वतंत्र पत्रकार

कमजोर मानसून के शुरुआती संकेत और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने खेती की लागत और उत्पादन दोनों पर खतरा बढ़ा दिया है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि कम बारिश फसल उत्पादन, खाद्य कीमतों और ग्रामीण आय पर असर डाल सकती है, खासकर तब, जब ग्रामीण बाजार हाल में ही लंबी सुस्ती के बाद सुधार दिखा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून के लिए अपने पहले दीर्घकालिक पूर्वानुमान में वर्षा को नॉर्मल परिचय घरेज (एलपीए) का 92 फीसदी रहने का अनुमान जताया है, जो सामान्य से कम है। यह पिछले लगभग 25 वर्षों में सबसे कमजोर शुरुआती अनुमान माना जा रहा है और 2024-25 में दर्ज सामान्य से अधिक बारिश के उद्घान के उलट है। ऐसे में खरीफ सीजन की फसलों पर इसका सीधा असर पड़ने की आशंका जलाई जा रही है, जिससे कृषि उत्पादन और ग्रामीण मांग दोनों प्रभावित हो सकते हैं। यह स्थिति देश के लगभग 60 प्रतिशत किसानों के लिए गंभीर चिंता का विषय हो सकती है, जो खरीफ फसलों के लिए पूरी तरह मानसूनी वर्षा पर निर्भर रहते हैं। कई क्षेत्रों के लिए यह दोहरी मार जैसी स्थिति है, क्योंकि वे पहले ही 2026 के प्री-मानसून मौसम में ओलावृष्टि और बाद के कारण नुकसान झेल चुके हैं। बारिश कम होने से खेती की लागत और भी बढ़ सकती है, जिससे दलहन और तिलहन की फसलों के दाम बढ़ सकते हैं, जिससे देश में खाद्य महंगाई में इजाफा हो सकता है। हालांकि पर्याप्त बफर स्टॉक के कारण सरकार को ध्यान उत्पादन को लेकर ज्यादा चिंता नहीं होगी, लेकिन अन्य फसलों के उत्पादन में गिरावट से इनकी कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी खाद्य महंगाई

पर दबाव बढ़ा सकती है। अलनीनो या सुपर चार्ज्ड अलनीनो की आशंका से अर्थशास्त्री इत्यदि भी चिंतित हैं, क्योंकि इससे पहले ही अल नीनो के कारण अभियमित वर्षा पैटर्न से 2023-24 फसल वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन 6.1 फीसदी तक घट गया था। 1980 के बाद के लगभग 70 फीसदी अल नीनो वर्षों में देश में कम वर्षा दर्ज की गई है। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले महर्नों में न सिर्फ गर्मी नया रिकॉर्ड बनाएगी, बल्कि देश के कुछ इलाकों को सूखे का सामना भी करना पड़ सकता है। बहरहाल, मानसून को लेकर आईएमडी का यह पूर्वानुमान मौसम ही नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक चेतावनी भरा संकेत है, क्योंकि कमजोर मानसून का असर आम तौर पर खाद्य मुद्रास्फीति, ग्रामीण आय और वित्तीय स्थिति के जरिए व्यापक अर्थव्यवस्था तक पहुंचता है। इससे एफएमसीजी, ट्रेक्टर, दोपहिया और उपभोगिता टिकाऊ वस्तुओं की मांग पर दबाव बन सकता है, हालांकि विक्रियन क्षेत्रों और उत्पाद श्रेणियों पर असर एक जैसा नहीं होता। और

पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव (ईरान युद्ध) के कारण यह चिंता और भी बढ़ गई है, क्योंकि युद्ध ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चैन) को बाधित किया है। इसके कारण उर्वरक और ऊर्जा की लागत बढ़ने से कृषि के खर्च (इनपुट कॉस्ट) को पहले ही बढ़ा दिया है। साथ ही, अगर हालत बिगड़ते हैं तो कच्चे तेल के दाम बढ़ सकते हैं। भारत में तेल महंगा होने का मतलब है ट्रान्सपोर्ट और खेती की लागत बढ़ना। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है। एक अनुमान के मुताबिक मानसून पर दो खरब करोड़ की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है और कम से कम 50 प्रतिशत कृषि को पानी वर्षा के जरिए ही हासिल होता है। अगर मानसून अफसल रहता है तो देश के विकास और अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सामान्य से उच्च मानसून रहने पर कृषि उत्पादन और किसानों की आय दोनों में बढ़ोतरी होती है, जिससे ग्रामीण बाजारों में उत्पादों की मांग को बढ़ावा मिलता है। अच्छी बारिश न सिर्फ कृषि क्षेत्र के लिए जरूरी है, बल्कि इससे उद्योग जगत में भी बहाव आती है। मालूम हो कि खेत से लेकर खाने की टेबल तक एक बड़ी चेन जुड़ी होती है। ऐसे में कमजोर मानसून पूरी चेन को बिगाड़ सकता है। इससे पूरी आर्थिक एक्टिविटी गड़बड़ जाती है। अब आने वाले समय में मानसून कैसा रहता है, अल नीनो किंता असर डालता है और दुनिया के हालात कैसे रहते हैं, इन सब फैक्टर्स पर आगे महंगाई दर निर्भर करेंगी। आने वाले कुछ महीने इस लिहाज से बहुत अहम रहने वाले हैं।



चिंतन
उमेश चतुर्वेदी
वरिष्ठ पत्रकार

मानसून को लेकर मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान अगर सही रहा तो तय है कि आने वाले दिनों में खेती-किसानी को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। स्वाभाविक है कि इससे देश के समूचे आर्थिक तंत्र और चक्र पर खराब असर पड़ेगा। मौसम विभाग ने इस साल मानसून के 'सामान्य से कम' यानी करीब 92 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। माना जा रहा है कि इससे अल नीनो की स्थिति उत्पन्न होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गिरावट आ सकती है। भारत की तकरीबन 45 फीसद खेती चूँकि मानसूनी बारिश पर निर्भर है, लिहाजा कमजोर मानसून की वजह से फसल की पैदावार कम हो सकती है।

इससे ग्रामीण क्रयशक्ति में कमी हो सकती है। इससे उपभोक्ता मांग भी प्रभावित होगी। हकीकत यह है कि मानसून भारतीय

नीति निर्धारण नहीं, बल्कि त्वरित क्रियान्वयन आवश्यक



दृष्टिकोण
विकेश कुमार बड़ोला
स्वतंत्र सभकार

भारतीय कृषि वर्तमान में एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है। प्रकृति की प्रतिकूलता तथा वैश्विक भू-राजनीतिक अस्थिरता ने मिलकर एक दोहरी मार की स्थिति उत्पन्न कर दी है। कम व असंतुलित मानसून के कारण जलभराव तथा सिंचाई की अनिश्चितता ने बुवाई चक्र को प्रभावित किया है, वहीं खाड़ी युद्ध की विध्वंसिता ने उर्वरक उत्पादन को बाधित किया है। देश में उर्वरक उत्पादन में 25 प्रतिशत से अधिक की कमी हुई है, जो प्रत्यक्ष रूप में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए एक गंभीर चेतावनी है।

इस संकट की तीव्रता को हेमूज के गतिधरो ने अधिक जटिल बना दिया है। कतर तथा ओमान जैसे प्रमुख उर्वरक निर्यातक देशों से होने वाला आयात लगभग बंद है, जिससे आपूर्ति पूरी तरह छिन्न-भिन्न

अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मानसून आधारित कृषि देश के समूचे कार्यबल के करीब आधे हिस्से को रोजगार देती है। रेंटिंग एजेंसी आईसीआरएफ का कहना है कि कम वर्षा से खरीफ फसलों की बुवाई पर असर पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन तो कम होगा ही, किसानों की आय घटेगी और खाद्य पदार्थों की कीमतों बढ़ोतरी होगी। आशंका है कि वित्त वर्ष 2027 में खाद्य मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत से अधिक रह सकती है। फसलों की पैदावार कम होने की आशंका के चलते, अनाज और दालों की कीमतों में बढ़ोतरी होना तय है, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। कमजोर मानसून से कृषि श्रमिकों की मजदूरी पर भी असर पड़ सकता है। निश्चित तौर पर इसका असर देश की विकास दर, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी और मुद्रास्फीति पर असर पड़ सकता है। इसके लिए अभी से ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने तैयारियों शुरू कर दी हैं। मंत्रालय का कहना है कि औसत से कम मानसून रहता है तो उससे फसल पैदावार में आने वाली गिरावट और अर्थव्यवस्था के नुकसान को कम करने की वह कोशिश कर

रहा है। हालांकि मंत्रालय का मानना है कि देश के जलाशयों का मौजूदा जल स्तर



सूक्ष्म सिंचाई की तकनीक, वैज्ञानिक सलाह और फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा देकर आशंकित संकट को कम किया जा सकता है।

सामान्य स्तर से 127.01 प्रतिशत ज्यादा है, लिहाजा सिंचाई के लिए पर्याप्त जल भंडार उपलब्ध हैं। इस वजह से मंत्रालय को लगता है कि आशंका की बजाय कृषि पर

है। ऐसे कठिन समय में, जब कृषक पहले से ही प्रतिफल जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे हैं, उर्वरकों की कमी तथा इनके बढ़ते मूल्यों ने उनकी आजीविका को असुरक्षित कर दिया है। इन परिस्थितियों में, कृषि मंत्रालय की भूमिका केवल एक नियामक की न होकर, एक संकट प्रबंधक की होनी चाहिए। मंत्रालय को अब तात्कालिक राहत तथा दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता के बीच संतुलन साधने के लिए कुछ असाधारण कार्य करने की आवश्यकता है। इसमें न केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक मांगों से वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतों की खोज सम्मिलित है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर 'नेनो यूरिया अर्थात् सूक्ष्म तरल उर्वरक' जैसे विकल्पों को प्रोत्साहन देना तथा वितरण प्रणाली में स्थायी पारदर्शिता लाना भी अनिवार्य है। भारत जैसी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए उर्वरक केवल एक आयात आधारित आगत नहीं, बल्कि ग्रामीण समृद्धि का महत्वपूर्ण कारक भी है। इस संदर्भ में यह आशंका विचारणीय है कि यदि समय रहते कठोर तथा नवीन कृषि नीतिक कार्य संपन्न नहीं किए गए तो उर्वरक संकट



मंत्रालय को देशभर के 'उर्वरक विक्रय स्थानों' का मशीन आधारित आंकड़ा बनाकर उसका वास्तविक समय में विश्लेषण करना चाहिए।

चाहिए। इनके अतिरिक्त रूस, मोरक्को तथा कनाडा जैसे वैकल्पिक उर्वरक उत्पादक देशों के साथ दीर्घकालिक आयात-अनुबंध करने होंगे। साथ ही, इनकी बाधामुक्त

किसानों के लिए चलाएं जागरूकता अभियान



उम्मीद
योगेश कुमार सोनी
वरिष्ठ पत्रकार

जै से ही कृषि से संबंधित किसी भी घटना का प्रभाव माना जाता है तो हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्यों की ही बात होती है। चूँकि नॉर्थ इंडिया में यह जो राज्य हैं जो लगभग अनाज की आपूर्ति के लिए पर्याप्त माने जाते हैं। जब कमजोर मानसून आता है तो इससे इन राज्यों के किसानों के मन में एक निराशा सी छा जाती है व आपूर्ति पर भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन अब सवाल यह है कि बीते कई वर्षों से हम कई बार फसल की बर्बादी देख चुके, जिससे आर्थिक नुकसान के अलावा किसानों की जाने तक भी घबरी जा जाती है। जब हम इस दृश्य को कई बार खुली आंखों से देख चुके हैं तो क्या अब इसके लिए किसानों के पास कोई समाधान है? तकनीकी व पुरानी घटनाओं के आधार पर विशेषज्ञों के अनुसार कुछ ऐसी बातें हैं जिससे फसल बच सकती है। सबसे पहले बारिश के बाद गेहूँ की फसल को सबसे ज्यादा खतरा खेत में ठंढे हुए पानी से माना जाता है क्योंकि अगर फसल की जड़ों में ज्यादा देर तक पानी जमा रहा तो जड़ें मलने लगेंगी, साथ ही नमी की वजह से दाने काले पड़ सकते हैं व फंगस लग जाएगा। इसलिए जैसे ही बारिश रुक जाए तो सबसे पहला काम यह करें कि खेत के निचले हिस्सों में फावड़े से छोटो-छोटो नालियाँ बना दें।

बारिश के बीच या ठीक बाद काटी गई फसल में नमी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। यदि मीने हुए गेहूँ को बारिश में भर देने से तो वह कुछ ही समय में सड़ने लगेगा व बर्दबू मारेंगी। इसलिए कटाई के बाद फसल को किसी ऊंचे स्थान या पक्के फर्श पर फैला कर दाने को बार-बार ऊपर-नीचे करते रहें ताकि धूप और हवा हर दाने तक पहुंचे। अक्सर देखा जाता है कि तेज हवा और बारिश की वजह से गेहूँ की फसल खेत में बिछ जाती है। यदि फसल गिर जाती है तो उसे ज्यादा दिनों तक जमीन पर न रहने दें। चूँकि मिट्टी की नमी गिरी हुई बालियों को जल्दी खराब कर देती है जिससे पकड़ने में भारी गिरावट आ जाती है। ऐसी स्थिति में धूप निकलते ही जितनी जल्दी हो सके गिरी हुई फसल की कटाई शुरू कर दें। कई बार लगातार बारिश और नमी की वजह से बालियों में लगे हुए दाने खेत में ही अंकुरित होने लगते हैं। यदि बालियों में हल्का भी अंकुरण दिखाई दे तो इसे फसल के लिए बाहर खतरा समझें और एक मिन्ट की बर्बाद न करें, क्योंकि अंकुरित गेहूँ न तो मंडी में अच्छे भाव बिकता है और न ही खाने लायक बचता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नुस्खे जिससे फसलों की बर्बादी बचाई जा सकती है। वहीं, यदि इन सब उपायों के बाद भी फसल नहीं बचती अथवा बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो फसल बर्बादी होने पर सरकार मुख्य रूप से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वित्तीय सहायता देती है।

इसमें ओलावृष्टि, बाढ़, सूखे या कीटी के हमले से नुकसान पर मुआवजा मिलाता है, लेकिन किसान बीमा दावा पाने के लिए किसानों को 72 घंटे में नुकसान की सूचना देनी होती है। इसके अलावा राज्य सरकारें अलग से राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत मदद करती हैं। लेकिन इसके लिए किसान को भी जानसूच होना आवश्यक है। चूँकि अब सारे कार्य एप से होते हैं और सब कुछ ऑनलाइन है। यह सब होने से सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि किसानों और सरकारों के बीच की दूरी कम हो गई। किसानों के लिए सरकारों के तत्वावधान में हमेशा सार्विक कदम उठाए जाते रहें हैं। यदि इस प्रणाली में किसानों को एप चलाने की जानकारी और दे दी जाए तो किसानों को योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिलेगा।

जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया का मुख्य अनाज मुख्यतः गेहूँ पर ही आधारित है और इसके लिए सबसे ज्यादा भरपाई हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश जैसे राज्य करते हैं तो इसलिए यहां किसानों के लिए एक विशेष टीम को गठित करते हुए किसानों को जागरूक किया जाए और उनकी सभी योजनाओं का लाभ देने में मदद की जाए। हमारे देश में किसानों को अंबेदादा का दर्जा दिया गया है। किसानों की जमीन गरीब व मुफलिस्सों के चरते न बिके व उनकी हर सही जरूरत का ध्यान रखा जाए, जिससे हमारे देश को मिला कृषि प्रधान देश का तमगा हमेशा बना रहे।

जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया का मुख्य अनाज मुख्यतः गेहूँ पर ही आधारित है और इसके लिए सबसे ज्यादा भरपाई हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश जैसे राज्य करते हैं तो इसलिए यहां किसानों के लिए एक विशेष टीम को गठित करते हुए किसानों को जागरूक किया जाए और उनकी सभी योजनाओं का लाभ देने में मदद की जाए। हमारे देश में किसानों को अंबेदादा का दर्जा दिया गया है। किसानों की जमीन गरीब व मुफलिस्सों के चरते न बिके व उनकी हर सही जरूरत का ध्यान रखा जाए, जिससे हमारे देश को मिला कृषि प्रधान देश का तमगा हमेशा बना रहे।

बारिश किस इलाके में किताब होती है। किसी इलाके में बेहतर बारिश होगी तो वहां का स्थानीय अन्न उत्पादन बेहतर होगा, बनिस्वत जहां कम बारिश होगी। इससे हो सकता है कि अन्न उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर उतनी कमी ना दिखे, जैसी आशंका जताई जा रही है। देखा गया है कि अपेक्षाकृत अच्छी बारिश वाले वर्षों में भी खाद्य मुद्रास्फीति अधिक रही है, जैसे वित्त वर्ष 2009 में 98 प्रतिशत बारिश के साथ 8.43 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2011 में 102 प्रतिशत बारिश के साथ 15.25 प्रतिशत खाद्य मुद्रास्फीति रही। वहीं, कम बारिश वाले वर्षों, जैसे वित्त वर्ष 2013 में 93 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2019 में 91 प्रतिशत बारिश के साथ खाद्य मुद्रास्फीति क्रमशः 6.33 प्रतिशत और 0.09 फीसद रही। रिजर्व बैंक की एमपीसी ने इन हालात का ध्यान रखते हुए ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं करने का फैसला लिया है। हालांकि रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा का कहना है कि अगर मानसून की स्थिति खराब होती है या फिर पश्चिम एशिया संकट के चलते ऊर्जा की कीमतें बढ़ती हैं, तो वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही में मौद्रिक नीति को सख्त किया जा सकता है।

बनाकर उसका वास्तविक समय में विश्लेषण करना चाहिए। इस हेतु डिजिटल सूचना-पट तैयार करना होगा, ताकि राज्य स्तर पर उर्वरक की उपलब्धता की पारदर्शी निगरानी संभव हो सके। संकट के समय में उर्वरकों का अपव्यय रोकना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। कृषकों को मृदा स्वास्थ्य पत्र के आधार पर केवल आवश्यक मात्रा में ही पोषक तत्व डालने के लिए प्रेरित किया जाए। इससे न केवल उर्वरक की बचत होगी, बल्कि खेती की लागत में भी कमी आएगी। भारत में उर्वरक का कच्चा माल (जैसे रॉक फॉस्फेट तथा प्राकृतिक गैस) की कमी है। इसीलिए इसके लिए हम आयात पर निर्भर हैं। देश में अपशिष्ट से कृषिधन प्रतिरूप अपनाकर गोबर व कृषि अवशेषों से बढ़े स्तर पर 'कंपोस्ट' तथा 'तरल जैव-उर्वरक' का उत्पादन किया जा सकता है। साथ ही, हरित हाइड्रोजन आधारित अमोनिया संश्रयंत्र लगाकर विदेशी कच्चे माल तथा गैस पर निर्भरता समाप्त की जा सकती है। यह समय कृषि मंत्रालय के लिए केवल नीति निर्धारण का नहीं, बल्कि त्वरित क्रियान्वयन का है।

केंद्रीय गृह मंत्री पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले के जमालपुर गांव में एक चुनावी रैली के दौरान टीएमसी पर साधा निशाना ममता के शासनकाल में सबसे ज्यादा कष्ट माताओं और बहनों ने झेला: अमित शाह

हरिभूमि ब्यूरो नई दिल्ली

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले के जमालपुर गांव में एक चुनावी रैली के दौरान राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। शाह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा ममता के शासनकाल के पिछले पंद्रह वर्षों में अगर किसी ने सबसे ज्यादा कष्ट झेला है, तो वो हमारी माताएं और बहनें हैं। शाह ने ममता बनर्जी पर राज्य में हुए कई अपराधों का आरोप लगाया और जनता द्वारा सत्ता में चुने जाने पर इन्हें रोकने का वादा किया।

शाह ने कहा कि आरजी कार, संदेशखाली, कलकत्ता लॉ कॉलेज और दुर्गापुर कॉलेज जैसी घटनाएं दर्शाती हैं कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हर जगह हुए हैं। और अब 'दीदी' कहती हैं कि महिलाओं को शाम 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 तारीख के बाद तो एक युवती भी रात 1 बजे तक घर से बाहर निकल सकेगी और कोई गुंडा उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। गृह मंत्री ने दावा किया कि 'कोई भी भाजपा मुख्यमंत्री महिलाओं को 'शाम 7 बजे के बाद घर से बाहर न निकलने' के लिए नहीं कहता और ममता बनर्जी पर 'महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहने' का आरोप लगाया। शाह ने आगे कहा कि देश



केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले के जमालपुर गांव में एक चुनावी रैली के दौरान राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा।

के किसी भी राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, वहां के मुख्यमंत्री ने कभी नहीं कहा कि महिलाएं शाम 7 बजे के बाद घर से बाहर न निकलें।

ममता दीदी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक महिला मुख्यमंत्री हैं, फिर भी आप महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी वादा करती है कि अगर कोई गुंडा मां और बहनों को बुरी नजर से देखने की भी हिम्मत करेगा, तो उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा।

इस बीच, शाह को पूरा भरोसा है कि पहले चरण के मतदान में भगवा पार्टी को 110 से अधिक सीटें मिलेंगी, जिसमें 152 निर्वाचन

घुसपैठ और तुष्टीकरण पर कड़ा रुख

शाह ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी का लक्ष्य बंगाल को घुसपैठ से मुक्त करना है और इसके लिए सीमाओं को सख्त किया जाएगा। उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार का काम सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना है, न कि किसी विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाना।

भ्रष्टाचार और गिरोह राज पर प्रहार

उन्होंने राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार और कथित गिरोह तंत्र पर भी निशाना साधा और कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर इस व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। व्यापारियों और आम नागरिकों को किसी प्रकार के अवैध दबाव या वसूली का सामना नहीं करना पड़ेगा।

ममता सरकार से जनता परेशान

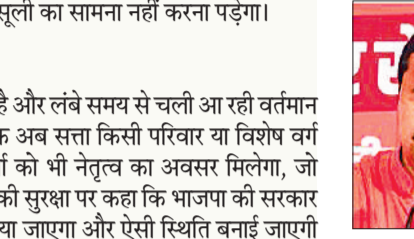
शाह ने कहा कि राज्य की जनता अब परिवर्तन चाहती है और लंबे समय से चली आ रही वर्तमान सरकार से परेशान हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि अब सत्ता किसी परिवार या विशेष वर्ग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एक सामान्य कार्यकर्ता को भी नेतृत्व का अवसर मिलेगा, जो जनता के बीच से उठकर आया हो। शाह ने महिलाओं की सुरक्षा पर कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और ऐसी स्थिति बनाई जाएगी कि महिलाएं दिन हो या रात, किसी भी समय बिना भय के बाहर निकल सकें।

क्षेत्रों में मतदान हुआ। उन्होंने कहा कि हमें जो प्रतिक्रिया मिली है, उससे पता चलता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने पहले चरण में ही अपना फैसला कर लिया है। 16 जिलों की 52

केजरीवाल के प्रचार पर नबीन का तंज

जनता भाजपा के साथ, इबती नाव में कौन रहना चाहेगा? बरानगर। यहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के बंगाल में चुनाव प्रचार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस नेता की छवि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हो, उसके लिए प्रचार करने का नैतिक आधार बचा नहीं है। राघव

चट्टा और आप के कुछ राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इबती हुई नाव में कोई सवार नहीं होता। उन्होंने दावा किया कि पहले आप कमजोर हुई और अब टीएमसी भी उसी राह पर है।



नबीन चट्टा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के बंगाल में चुनाव प्रचार पर निशाना साधा।

सीटों पर 92.98 प्रतिशत मतदान से संकेत मिलता है कि 'दीदी' सत्ता से बाहर होने वाली हैं और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने वाली है। डर खत्म होगा और विश्वास की जगह लेगी।

खबर संक्षेप

छठी मंजिल पर लगी आग से 15 को बचाया

जयपुर। जयपुर के मुहाना थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक अपार्टमेंट में भीषण आग लगने से अफरातफरी मच गई। मुहाना मंडी के पास स्थित 'घर आंगन' नामक अपार्टमेंट की छठी मंजिल पर करीब 2:15 बजे एक फ्लैट में आग लगी, इससे 15 लोगों को बचा लिया गया।

मणिपुर में किया बवाल आंसू गैस छोड़नी पड़ी

इंफाल। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को इंफाल में स्थायी शांति की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर रहे हजारों प्रदर्शनकारियों को पुलिस के साथ झड़प हुई। सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। प्रदर्शन मैतेई संगठन ने किया था।

डीके का दौरा सरकारी मई क्रांति सिर्फ अफवाह

नई दिल्ली। कर्नाटक में फिर नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज है। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के दिल्ली दौरे को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। कैबिनेट मंत्री प्रियांक खरगे ने सरकार का रुख स्पष्ट किया है। प्रियांक ने अटकलों को खारिज कर दिया, जिनमें राज्य नेतृत्व परिवर्तन की बात थी।

वाराणसी से पुणे चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल को बरेका में जनसभा स्थल से बनारस-पुणे अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पहले दिन यह गैर वातातुलकित प्रीमियम ट्रेन उद्घाटन स्पेशल बनकर जाएगी। बनारस स्टेशन पर इसका सजीव प्रसारण होगा। बोर्ड के निदेशक संजय आर. नीलम के पत्र बाद तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।

राष्ट्रवाद की हुंकार से हिला दीदी का किला

उत्तर 24 परगना। बंगाल चुनाव के रण में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरते हुए ममता सरकार पर तीखा हमला बोला। एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने बंगाल को भारत की 'आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्राणवायु' बताया। अब ममता का किला हिलने वाला है।

यह बंगाल ही नहीं देश के लिए खतरा

कोलकाता में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर यह जारी रहा तो पूरे देश की जनसंख्या संरचना पर असर पड़ेगा। बंगाल चुनाव का प्रभाव पूरे भारत पर पड़ेगा।

विकास के लिए डबल इंजन सरकार की जरूरत

यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल का उदाहरण देते हुए डबल इंजन सरकार की जरूरत बताई और कहा कि इससे विकास तेज होगा, सुरक्षा मजबूत होगी और रोजगार बढ़ेगा।

असम के डिस्टेंशन कैंपों में बंगाली हिंदू...तो इस्तीफा

सरमा ने कहा कि टीएमसी के लोग कभी-कभी कहते हैं कि असम के डिस्टेंशन कैंपों में कई बंगाली हिंदू हैं। कैंपों में एक भी बंगाली हिंदू नहीं है। एक भी बंगाली हिंदू नहीं है, तो मैं आज ही इस्तीफा देने को तैयार हूँ।

वर्मा ने केजरीवाल के लोधी एस्टेट के नए सरकारी आवास पर खर्च को लेकर उठाए सवाल

केजरीवाल के नए घर को दूसरा 'शीशमहल' बताया, आप ने तस्वीरों को फर्जी करार दिया

प्रवेश वर्मा और इन तस्वीरों को दिखाने वाले टीवी चैनल मानहानि के मुकदमों के लिए तैयार रहें: संजय

भाजपा ने शनिवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को निशाना साधा

हरिभूमि ब्यूरो नई दिल्ली

भाजपा ने शनिवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को निशाना साधते हुए उनके नए घर में हुए खर्च पर कई सवाल खड़े किये। कोर्ट के आदेश के बाद केजरीवाल को 95, लोधी एस्टेट में सरकारी आवास आवंटित हुआ था। कल शुक्रवार उन्होंने परिवार के साथ इस घर में शिफ्टिंग की थी। प्रवेश वर्मा ने नए घर की तस्वीरें देखकर हैरानी जताई और कहा, वहां भी उन्होंने खूब खर्च किया है। यह सरकारी घर है, लेकिन इसमें सरकारी पैसा नहीं लगा है। उधर, आम आदमी पार्टी के नेता एवं सांसद संजय सिंह ने इन दावों को खारिज कर दिया और उन्हें पूरी तरह से फर्जी बताया। सिंह ने कहा कि प्रवेश वर्मा और इन तस्वीरों को दिखाने वाले टीवी चैनलों को मानहानि के मुकदमों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल वीके सक्सेना और प्रवेश वर्मा को भी चुनौती दी कि वे अपने घरों को जनता के लिए खोल दें। उन्होंने कहा कि इसके बाद केजरीवाल भी ऐसा ही करेंगे। सिंह ने कहा कि तब जनता देखेगी कि किसका घर सचमुच आलीशान है। प्रवेश वर्मा ने यह भी कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में केजरीवाल सबसे



दिल्ली सरकार के मंत्री वर्मा ने तथाकथित यह तस्वीर दिखाई



मंत्री प्रवेश वर्मा (बाएं) और संजय सिंह (दाएं)

पहले शीशमहल (6, फ्लैग स्टाफ रोड) पर भारी खर्च को लेकर जब सवाल उठे तो केजरीवाल ने दावा किया था कि सजावट का फैसला पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर ने लिया था और उन्हें खर्च की जानकारी नहीं थी। अब नए घर पर वे ऐसा दावा नहीं कर सकते।

जो नेता कभी साधारण बंगला भी नहीं लेने की बात करते थे और कहते थे कि किसी अन्य पार्टी के नेता का पैसा घर नहीं होगा, आज खुद शीशमहल में रह रहे हैं। दिल्ली में कोरोना महामारी, पानी और बिजली की कमी के समय भी केजरीवाल जनता से गायब होकर शीशमहल बनाने में लगे रहे। शीशमहल केजरीवाल के भ्रष्टाचार का सबूत है। मुख्यमंत्री के वेतन से ऐसा आलीशान घर नहीं बन सकता। उन्हें बताना चाहिए कि इस घर पर शराब घोटाले का पैसा लगाया गया या नहीं। वर्मा ने आगे कहा कि केजरीवाल के अंदर शीशमहल बस चुका है। इस कारण उन्हें दिल्ली और पंजाब की जनता का दुख दिखाई नहीं देता। आप कार्यकर्ता पूरी जिंदगी मेहनत करें तब भी ऐसा मकान नहीं बना सकते।

प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल और आप से चार सीधे सवाल भी पूछे...लोधी रोड वाले बंगले में जितना पैसा लगा है, वह पैसा कहां से आया और किसका है? क्या आपकी विवासिता के कारण आप के कार्यकर्ता केजरीवाल को छोड़ रहे हैं? बार-बार आलीशान शीशमहल बनाने की उन्हें क्या जरूरत पड़ रही है? पहले शीशमहल में शराब का पैसा लगा था, इस बार किसका पैसा लगा है?

कहा, नकली बीज-खाद पर सख्ती, छोटे किसान की भलाई पर विशेष जोर

केंद्र का राज्यों के सहयोग से बीज मिट्टी, उपज खरीद और किसान कल्याण पर साफ फोकस: चौहान

हरिभूमि ब्यूरो नई दिल्ली

लखनऊ में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब खेती-किसानी के मुद्दे केवल बैठकों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उन पर समयबद्ध अमल होगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मेलन सत्र में साफ कहा कि यह सम्मेलन औपचारिकता नहीं, बल्कि निर्णय, कार्ययोजना, जवाबदेही और किसान-केंद्रित परिणामों का मंच है। शिवराज सिंह ने केंद्र और राज्यों को 'टीम इंडिया' की भावना से मिलकर काम करने का आह्वान

सभी मुद्दों पर कार्ययोजना बनेगी और समीक्षा भी होगी

उन्होंने स्पष्ट किया कि सम्मेलन में उठाए गए सभी मुद्दों पर कार्ययोजना बनाई जाएगी और उसकी हर तीन महीने में समीक्षा होगी। साथ ही, राज्यों से कहा गया कि वे कृषि और बागवानी से जुड़े अपने मुद्दे, प्रस्ताव और आवश्यकताएं सीधे केंद्र सरकार के सामने रखें और बैठकों का इंतजार न करें। चौहान ने राज्यों को निर्देश दिया कि केंद्रीय योजनाओं के प्रस्ताव समय पर भेजे जाएं, ताकि स्वीकृति और पहली किस्त जारी करने में देरी न हो। उन्होंने यह भी कहा कि योजनाओं की राशि समय पर खर्च करना जरूरी है, क्योंकि व्यय की गति का सीधा असर अगली किस्त और मित्य के बजट पर पड़ता है। केंद्रीय मंत्री ने अरुंधे बीज को बेहतर खेती की बुनियाद बताते हुए कहा कि बीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सॉर्टिफाइड सीड की पूरी श्रृंखला को मजबूत करना होगा। उन्होंने राज्यों से अपेक्षा की कि वे आवंटित बीडर सीड समय पर उठाएं और इन्हें किसानों को केवल जारी करने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें खेत तक पहुंचाने की व्यवस्था भी मजबूत करें। चौहान ने संतुलित उर्वरक उपयोग पर विशेष जोर देते हुए कहा कि किसानों को मिट्टी की वास्तविक जरूरत के अनुसार ही खाद उपयोग की सलाह दी जानी चाहिए। उन्होंने सॉल्व हेल्थ कार्ड को व्यावहारिक बनाने, जिलेवार मुदा की जानकारी साझा करने और वैज्ञानिक सलाह को किसान तक पहुंचाने की जरूरत बताई। उन्होंने नकली बीज, नकली खाद और घटिया कीटनाशकों के खिलाफ सख्त अभियान चलाने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि उपलब्ध प्रयोगशालाओं का पूरा उपयोग हो, सैप्लों की समस्याओं में जांच हो, और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई प्रभावी ढंग से आगे बढ़े। किसान क्रेडिट कार्ड के मुद्दे पर चौहान ने कहा कि अभी भी बड़ी संख्या में किसान, विशेषकर छोटे किसान, इससे बाहर हैं और उन्हें जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष राहुल का संघ पर तंज संस्था को राष्ट्रीय सरेंडर संघ बताया राममाधव ने वास्तविकता बता दी

एजेसी नई दिल्ली

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संघ नेता और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव राम माधव द्वारा अमेरिका में दिए गए बयान पर संघ पर तीखा तंज कसा। राहुल ने कहा कि राम माधव ने केवल संघ के वास्तविक स्वरूप को उजागर किया है। राम माधव ने भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव पर हैरानी जताई।

राहुल ने बोला हमला

राहुल ने संघ पर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट किया राष्ट्रीय आत्मसमर्पण संघ। नागपुर में फर्जी राष्ट्रवाद। अमेरिका में सरासर गुलामी। उन्होंने आगे लिखा कि राम माधव ने 'संघ का असली चेहरा' ही उजागर किया है। इन टिप्पणियों के चलते भाजपा-संघ को निशाना बनाया। उसे राष्ट्रीय सरेंडर संघ तक कह दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने आईसीयू की व्यवस्था पर उठाए सवाल देशभर में समान मानक हों, राज्य 3 हफ्तों में दें प्लान

एजेसी नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में गहन चिकित्सा इकाइयों की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आईसीयू के लिए तय न्यूनतम मानकों को लागू करने सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश व्यावहारिक और यथार्थवादी कार्ययोजना तैयार करें। शीर्ष अदालत की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन शामिल थे, कहा कि गहन देखभाल सेवाओं के संगठन और वितरण के लिए दिशानिर्देश तैयार कर ली गई हैं, जिन पर व्यापक सहमति है।

सभी राज्य, केंद्रशासित प्रदेश व्यावहारिक व यथार्थवादी कार्ययोजना तैयार करें

जयपुर में सीजेआई का दिवा थायराणा अंदान

जिसको तूफानों से उलझने की हो आदत... रिटायर्ड जजों को बताया 'बावड़ी' की तरह जयपुर। सीजेआई ने शनिवार को कहा 'न्यायपालिका व उससे जुड़ी संस्थाओं में जनता का गहरा विश्वास है और इस विश्वास को बनाए रखना हमारा दायित्व है। पूर्व न्यायाधीशों की तुलना 'बावड़ी' से करते हुए उन्हें ज्ञान का भंडार बताया जो चुनौतीपूर्ण समय में व्यवस्था का मार्गदर्शन कर सकते हैं।

सारी जनता का विश्वास रहे, आप आगे बढ़ें

न्यायपालिका व उससे जुड़ी संस्थाओं पर उन्होंने मोहसिन नकवी के शेर 'जिसको तूफानों से उलझने की हो आदत, ऐसी करती को समंदर भी दुआ देता है' का उल्लेख करते हुए कहा, आप भी ऐसा कुछ कीजिए सारी जनता का विश्वास आप में रहे। आगे बढ़ें।

शेयर बाजार और फिक्स्ड डिपॉजिट से आगे बढ़ते हुए अब निवेशक सोना, चांदी, मल्टी-एसेट एलोकेशन फंड और अन्य कमोडिटी विकल्पों की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं। महंगाई, वैश्विक अनिश्चितता और बाजार में उतार-चढ़ाव के दौर में ये एसेट क्लास पोर्टफोलियो को संतुलन देने का काम करते हैं। लेकिन समस्या तब पैदा होती है, जब निवेशक अलग-अलग विकल्पों कमोडिटी फंड, गोल्ड-सिल्वर इंटीएफएफ और मल्टी-एसेट फंड को एक जैसा मान लेते हैं। यही भ्रम कई बार गलत निवेश फैसलों और नुकसान की वजह बनता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कमोडिटी फंड्स वास्तव में सीधे सोने या चांदी में निवेश नहीं करते। ये फंड उन कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाते हैं जो माइनिंग, मेटल या एनर्जी सेक्टर से जुड़ी होती हैं। यानी इनका प्रदर्शन केवल कमोडिटी की कीमत पर नहीं, बल्कि उन कंपनियों के बिजनेस, मैनेजमेंट और मार्केट कंडीशन पर भी निर्भर करता है। इस कारण ये फंड तकनीकी रूप से इक्विटी फंड की श्रेणी में आते हैं और इनमें जोखिम भी उसी के अनुरूप अधिक होता है।

सोना-चांदी या मल्टी-एसेट फंड? निवेश से पहले जानें पूरा गणित

- ▶ उच्च रिटर्न के लालच में न करें गलती, जोखिम और रिटर्न का संतुलन ही समझदारी
- ▶ बाजार की चाल, जोखिम और लक्ष्य के हिसाब से चुनें सही विकल्प, वरना होगा नुकसान
- ▶ गोल्ड इंटीएफ, कमोडिटी फंड और मल्टी-एसेट फंड के फर्क को समझना गेहद जरूरी
- ▶ कमोडिटी फंड्स वास्तव में सीधे सोने या चांदी में निवेश नहीं करते
- ▶ ये उन कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाते हैं जो माइनिंग, मेटल या एनर्जी सेक्टर से जुड़ीं

कमोडिटी फंड : हाई रिस्क, साइकिल पर निर्भर रिटर्न

कमोडिटी फंड्स का प्रदर्शन 'कमोडिटी साइकिल' पर आधारित होता है। जब मेटल या एनर्जी सेक्टर में तेजी आती है, तो ये फंड अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन गिरावट के समय इनका प्रदर्शन तेजी से नीचे भी आ सकता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ इन्हें लॉन्ग टर्म कोर इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं देखते। आमतौर पर 1 से 3 साल के लिए, किसी खास सेक्टर में तेजी का फायदा उठाने के लिए ही इनका उपयोग किया जाता है। निवेश सलाहकारों के अनुसार, पोर्टफोलियो में इनका हिस्सा 5% से 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अधिक निवेश सलाहकों को बचना चाहिए। साथ ही, इनमें निवेश करने से पहले बाजार की स्थिति और सेक्टर ट्रेंड को समझना बेहद जरूरी है।



गोल्ड और सिल्वर इंटीएफएफ कीमत से जुड़ा निवेश

अगर आपका उद्देश्य सीधे सोने या चांदी की कीमतों में होने वाले बदलाव का लाभ उठाना है, तो गोल्ड इंटीएफएफ और सिल्वर इंटीएफएफ बेहतर विकल्प हैं। ये फंड फिजिकल गोल्ड या सिल्वर की कीमत को ट्रैक करते हैं, यानी इनका रिटर्न सीधे धातु की कीमत पर निर्भर करता है। इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको फिजिकल गोल्ड खरीदने, स्टोर करने या उसकी सुरक्षा की चिंता नहीं करने पड़ती। साथ ही, इनकी पारदर्शिता और लिक्विडिटी भी अधिक होती है, क्योंकि इन्हें शेयर बाजार में आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है। हालांकि, इनका रिटर्न आमतौर पर स्थिर और सीमित होता है। ये तेजी से मल्टीबैरर रिटर्न देने के बजाय पोर्टफोलियो को स्थिरता देने का काम करते हैं। इसलिए इन्हें 'रोफ हेवन' या हेजिंग टूल के रूप में देखा जाता है।

मल्टी-एसेट एलोकेशन फंड : संतुलित निवेश का विकल्प
अगर आपका उद्देश्य सीधे सोने या चांदी की कीमतों में होने वाले बदलाव का लाभ उठाना है, तो गोल्ड इंटीएफएफ और सिल्वर इंटीएफएफ बेहतर विकल्प हैं। ये फंड फिजिकल गोल्ड या सिल्वर की कीमत को ट्रैक करते हैं, यानी इनका रिटर्न सीधे धातु की कीमत पर निर्भर करता है। इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको फिजिकल गोल्ड खरीदने, स्टोर करने या उसकी सुरक्षा की चिंता नहीं करने पड़ती। साथ ही, इनकी पारदर्शिता और लिक्विडिटी भी अधिक होती है, क्योंकि इन्हें शेयर बाजार में आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है। हालांकि, इनका रिटर्न आमतौर पर स्थिर और सीमित होता है। ये तेजी से मल्टीबैरर रिटर्न देने के बजाय पोर्टफोलियो को स्थिरता देने का काम करते हैं। इसलिए इन्हें 'रोफ हेवन' या हेजिंग टूल के रूप में देखा जाता है।

पिछले आंकड़ों पर न जाएं

बाजार में आईसीआईआईआईआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, एफबीआई म्यूचुअल फंड और व्वांट म्यूचुअल फंड जैसे कई कमोडिटी या मल्टी-एसेट फंड्स उपलब्ध हैं, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में 20-22% तक का रिटर्न दिया है, लेकिन विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि केवल पिछले प्रदर्शन के आधार पर निवेश का फैसला लेना गलत हो सकता है। कमोडिटी सेक्टर स्वभाव से ही अस्थिर होता है। इसलिए इसमें औसतन 10-12% सीधीआर की उम्मीद रखना ज्यादा व्यावहारिक है।

समझदारी से करें संतुलन

निवेश का कोई एक 'सही' विकल्प नहीं होता। यह पूरी तरह आपके लक्ष्य, जोखिम क्षमता और निवेश अवधि पर निर्भर करता है। गोल्ड इंटीएफ और मल्टी-एसेट फंड्स आम निवेशकों के लिए बेहतर और सुरक्षित विकल्प माने जाते हैं, जबकि कमोडिटी फंड्स केवल समझदार और अनुभवी निवेशकों के लिए ही उपयुक्त हैं। अतः, एक संतुलित पोर्टफोलियो ही लंबे समय में बेहतर रिटर्न और कम जोखिम सुनिश्चित करता है। इसलिए निवेश से पहले जरूरतें समझें, जल्दबाजी से बचें और जहां जरूरी हो, वित्तीय सलाहकार की मदद लें ताकि आपका पैसा सही दिशा में काम कर सके।

एमएफ के नाम में छिपा पूरा खेल : 'डायरेक्ट रेगुलर और ग्रोथ' का सही मतलब समझें

म्यूचुअल फंड में निवेश करना आजकल बहुत आसान हो गया है, लेकिन सही फंड का चुनाव करना आज भी कई लोगों के लिए बड़ी चुनौती है। बता दें कि जब आप किसी ऐप या वेबसाइट पर फंड सर्च करते हैं, तो एक ही नाम के कई ऑप्शन नजर आते हैं। दरअसल, इन नामों में निवेश की पूरी रणनीति छिपी होती है। अगर आप इन बेसिक शब्दों का मतलब समझ लेते हैं, तो आप अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार सही फंड का चुनाव कर सकते हैं।

निवेश की कैटेगरी को पहचानें

म्यूचुअल फंड के नाम की शुरुआत एफएमसी से होती है, जैसे एफबीआई, अक्षम या आईसीआईआई प्रूडेंशियल। यह वो संस्था है जो आपके पैसे को मैनेज करती है। नाम के अलावे हिस्से में फंड की कैटेगरी होती है। जैसे लार्ज कैप का अर्थ है कि पैसा देश की टॉप 100 सुरक्षित कंपनियों में लगेगा। वहीं, स्मॉल कैप या मिड कैप में पैसा उन कंपनियों में लगाया जाता है जो तेजी से बढ़ रही हैं, हालांकि इनमें जोखिम थोड़ा ज्यादा होता है।

खर्च और मुनाफे का अंतर

फंड के नाम में डायरेक्ट और रेगुलर सबसे अहम शब्द हैं। डायरेक्ट का मतलब है कि आप सीधे फंड हाउस के साथ निवेश कर रहे हैं। इसमें कोई एजेंट नहीं होता, इसलिए एक्सपेंस रेशियो कम होता है और आपका मुनाफा बढ़ जाता है। इसके विपरीत, रेगुलर प्लान किसी बैंक या ब्रोकर के जरिए लिया जाता है, जहां आपको दी जाने वाली सुविधाओं के बदले कंपनी एजेंट को कमीशन देनी है, जिससे आपका शुद्ध मुनाफा थोड़ा कम हो जाता है।

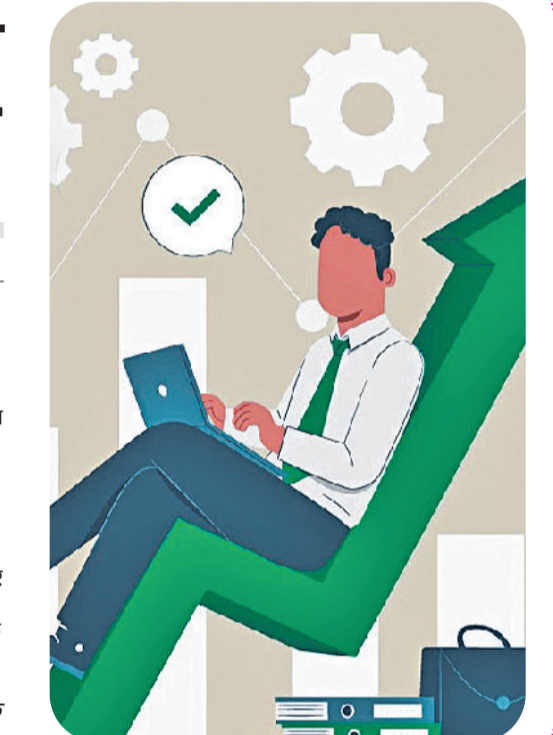
रिटर्न पाने का तरीका चुनें

नाम के आखिरी हिस्से में आपको ग्रोथ या आईडीडब्ल्यूसी लिखा मिलेगा। बता दें कि अगर आप लंबे समय के लिए पैसा जोड़ना चाहते हैं, ग्रोथ ऑप्शन चुनें क्योंकि इसमें मुनाफे पर कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको निवेश के बीच-बीच में कुछ कमाई मिलती रहे, तो आईडीडब्ल्यूसी प्लान लिया जा सकता है।

स्मार्ट निवेशक बनने के लिए जरूरी टिप्स

म्यूचुअल फंड चुनते समय सिर्फ पिछले रिटर्न को ना देखें, बल्कि इन चारों यानी एफएमसी, कैटेगरी, प्लान टाइप और रिटर्न मोड को परखें। अपनी रिस्क लेने की क्षमता और समय सीमा के आधार पर ही सही ऑप्शन का चुनाव करें। हमेशा कोशिश करें कि डायरेक्ट और ग्रोथ ऑप्शन पर गौर करें जिससे लंबी समय में आपकी जमा पूंजी पर कमीशन का बोझ न पड़े और आपकी अधिकतम लाभ मिल सके। म्यूचुअल फंड का नाम भले ही जटिल लगे, लेकिन इसमें निवेश का पूरा ब्लूप्रिंट छिपा होता है। म्यूचुअल फंड में सफल होने के लिए जरूरी है कि आप इन बुनियादी शब्दों को समझें और सोच-समझकर फैसला लें। सही जानकारी के साथ किया गया निवेश ही लंबे समय में संपत्ति निर्माण का मजबूत आधार बनता है।

बिजनेस डेस्क



अब आईटीआर में गलती की तो पड़ सकती है भारी

गलत इनकम बताई तो 200% तक जुर्माना

बिजनेस डेस्क

आयकर रिटर्न यानी आईटीआर भरना अब केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं रह गया है, बल्कि यह पूरी तरह जिम्मेदारी और सतर्कता का काम बन चुका है। आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए नया पेनल्टी फ्रेमवर्क लागू किया है, जिसमें गलत जानकारी देने वाले टैक्सपेयर्स पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इस नए सिस्टम का मकसद साफ है। टैक्स अनुपालन को सख्ती से लागू करना और किसी भी तरह की लापरवाही या हेरफेर को हतोत्साहित करना।

गलत इनकम दिखाना पड़ सकता है भारी

नए नियमों के तहत यदि कोई टैक्सपेयर अपनी वास्तविक आय से कम इनकम दिखाता है, तो उसे देय टैक्स पर 50 प्रतिशत तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह जुर्माना उन मामलों में लागू होता है जहां गलती को अनजाने में हुई चूक माना जाता है। लेकिन अगर यह चूक गलती को अनजाने में हुई चूक माना जाता है। लेकिन अगर यह चूक गलती को अनजाने में हुई चूक माना जाता है। लेकिन अगर यह चूक गलती को अनजाने में हुई चूक माना जाता है। लेकिन अगर यह चूक गलती को अनजाने में हुई चूक माना जाता है।

जानबूझकर गलती और सामान्य चूक में फर्क

सरकार ने इस बार नियमों में यह स्पष्ट किया है कि जानबूझकर की गई गलती और सामान्य चूक में अंतर किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने भूलवश कोई इनकम जोड़ना रह गया, तो उसे जमाना सख्ती से नहीं देखा जाएगा। हालांकि, यदि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर गलती की है, तो उसे देय टैक्स पर 50 प्रतिशत तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह जुर्माना उन मामलों में लागू होता है जहां गलती को अनजाने में हुई चूक माना जाता है। लेकिन अगर यह चूक गलती को अनजाने में हुई चूक माना जाता है। लेकिन अगर यह चूक गलती को अनजाने में हुई चूक माना जाता है।

- छोटी चूक भी बन सकती है बड़ी सजा का कारण
- जानबूझकर जानकारी छिपाने पर दोगुना तक जुर्माना
- लेट फाइलिंग व दस्तावेजों में कमी पर भी कड़ा प्रावधान



लेट आईटीआर पर भी सख्त नियम

समय पर आईटीआर फाइल न करने पर भी अब जुर्माने का प्रावधान पहले से स्पष्ट और कड़ा कर दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति तय समय सीमा के बाद आईटीआर भरता है, तो उसे अधिकतम 5000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। हालांकि, जिन टैक्सपेयर्स की सालाना आय 5 लाख रुपये तक है, उनके लिए राहत देते हुए जुर्माना 1000 रुपये तक सीमित रखा गया है। इसका उद्देश्य छोटे करदाताओं को अनावश्यक बोझ से बचाना है, लेकिन समय पर फाइलिंग की जिम्मेदारी से छूट नहीं दी गई है।

टीडीएस और अन्य दस्तावेजों में देरी भी महंगी

सिर्फ आईटीआर ही नहीं, बल्कि टीडीएस और अन्य जरूरी स्टेटमेंट समय पर जमा न करने पर भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे मामलों में 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है, जो समय के साथ बड़ी राशि में बढ़ल सकता है। इससे साफ है कि टैक्स रिटर्न अब पूरी तरह समयावद्ध और अनुशासित हो चुका है, जहां हर देरी की कीमत चुकानी पड़ सकती है।

राहत के प्रावधान भी मौजूद

हालांकि सख्ती के बीच सरकार ने कुछ राहत के विकल्प भी दिए हैं। यदि कोई टैक्सपेयर यह साबित कर देता है कि उससे हुई गलती किसी वाजिब कारण से हुई थी, जैसे तकनीकी समस्या या वास्तविक भूल, तो उस पर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा, कुछ मामलों में अपील और स्पष्टीकरण के आधार पर भी जुर्माने में राहत मिल सकती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि ईमानदार करदाता अनावश्यक रूप से परेशान न हों।

सतर्कता ही बचाव का सबसे बड़ा तरीका

इन नए नियमों के बाद यह साफ हो गया है कि आईटीआर भरते समय लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। हर जानकारी को सही दस्तावेजों के साथ जांचकर ही भरना चाहिए। विशेषज्ञों की सलाह है कि यदि टैक्स फाइलिंग को लेकर किसी भी तरह का संदेह हो, तो पेशेवर सलाह लेना बेहतर है। छोटी सी गलती भी बड़े जुर्माने में बदल सकती है, इसलिए सतर्क रहना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है।

आयकर विभाग का स्पष्ट संदेश

नए पेनल्टी नियम यह संकेत देते हैं कि टैक्स रिटर्न अब ज्यादा पारदर्शी और सख्त हो चुका है। आयकर विभाग का स्पष्ट संदेश है ईमानदारी से टैक्स भरें या मारपीट न करें। सरकार का स्पष्ट संदेश है ईमानदारी से टैक्स भरें या मारपीट न करें। सरकार का स्पष्ट संदेश है ईमानदारी से टैक्स भरें या मारपीट न करें। सरकार का स्पष्ट संदेश है ईमानदारी से टैक्स भरें या मारपीट न करें।

अलग नाम, लेकिन निवेश वही

जब आप कई फंड्स में निवेश करते हैं, तो एक बड़ी समस्या होती है—पोर्टफोलियो ओवरलैप। मान लीजिए आपने दो या तीन लार्ज-कैप फंड्स ले रखे हैं। इनमें से हर फंड में रिलायंस, इन्फोसिस या एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े शेयर टॉप होल्डिंग में हो सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अलग-अलग फंड्स के जरिए एक ही कंपनियों में बार-बार निवेश कर रहे हैं।

इससे दो नुकसान होते हैं

जोखिम कम होने की बजाय बढ़ सकता है, क्योंकि बाजार गिरने पर सभी फंड्स एक साथ प्रभावित होते हैं। आप हर फंड का अलग-अलग एक्सपेंस रेशियो (खर्च) भी देते हैं, जिससे कुल रिटर्न घटता है। इस तरह, ज्यादा फंड्स रखने से निवेश का भ्रम तो बनता है, लेकिन रखने पर फायदा नहीं मिलता।

छोटी एसआईपी से कंपाउंडिंग कमजोर

यदि 25,000 की मासिक एसआईपी को आप 8 या 10 फंड्स में बाँटते हैं, तो हर फंड में बहुत कम राशि जाएगी। उदाहरण के तौर पर 8 फंड्स में निवेश करने पर हर फंड में सिर्फ 3,125 ही जाएंगे। इतनी छोटी राशि में कंपाउंडिंग

25,000 की एसआईपी के लिए 3 से 5 फंड ही काफी

छोटी एसआईपी में बंटवारे से कंपाउंडिंग पर पड़ता है असर

बिजनेस डेस्क

अक्सर निवेशक यह मान लेते हैं कि ज्यादा म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने से जोखिम कम हो जाता है और रिटर्न बेहतर मिलता है। इसी सोच के चलते कई लोग 10 से 12 या उससे भी ज्यादा फंड्स में एसआईपी शुरू कर देते हैं। लेकिन हकीकत इससे उलट है। जरूरत से ज्यादा फंड्स रखने से न तो जोखिम कम होता है और न ही रिटर्न बढ़ता है, बल्कि आपका पोर्टफोलियो उलझ जाता है और मुनाफा कम हो सकता है। खासतौर पर अगर आपकी मासिक एसआईपी 25,000 रुपये के आसपास है, तो 3 से 5 अच्छे फंड्स का चयन ही बेहतर रणनीति मानी जाती है।

ज्यादा फंड्स रखना क्यों नुकसान का सौदा

म्यूचुअल फंड निवेश का मूल सिद्धांत है विविधता, लेकिन कई निवेशक इस सिद्धांत को गलत तरीके से समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि अलग-अलग (एसेट मैनेजमेंट कंपनी) के ज्यादा फंड्स खरीदना ही विविधता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 10-12 फंड्स हैं, तो संभव है कि उनमें से कई एक ही सेक्टर या एक जैसे शेयरों में निवेश कर रहे हों। ऐसे में आपका पोर्टफोलियो देखने में तो बड़ा लगता है, लेकिन असल में वह विविध नहीं होता। विशेषज्ञ मानते हैं कि सीमित और चुने हुए फंड्स के जरिए बेहतर नियंत्रण और संतुलन बनाना ज्यादा आसान होता है। इससे निवेश की दिशा स्पष्ट रहती है और अनावश्यक जटिलता से बचाव होता है।

आदर्श पोर्टफोलियो कैसा हो

विशेषज्ञों के अनुसार 25,000 रुपये की एसआईपी के लिए 3 से 5 फंड्स का पोर्टफोलियो पर्याप्त होता है। इससे निवेश में संतुलन बना रहता है और जोखिम भी नियंत्रित रहता है। एक संतुलित पोर्टफोलियो के लिए आप इन कैटेगरी पर विचार कर सकते हैं।

- लार्ज-कैप या इंडेक्स फंड स्थिरता के लिए
- लार्ज एंड मिड-कैप फंड ग्रोथ और स्थिरता का मिश्रण
- मल्टी-कैप या फ्लेक्सि-कैप फंड अलग-अलग मार्केट कैप में निवेश
- इक्विटी हाइब्रिड फंड इंटिविटी और डेट का संतुलन
- इंडेक्स-एसेट फंड (टैक्स सेविंग) टैक्स बचत के साथ निवेश
- हर निवेशक अपनी जोखिम क्षमता, लक्ष्य और समय अवधि के अनुसार इन कैटेगरी में 3-5 फंड्स चुन सकता है।

25,000 की एसआईपी के लिए 3 से 5 फंड ही काफी

म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में भीड़ बढ़ाना पड़ सकता है भारी, घट सकता है रिटर्न

बिजनेस डेस्क

अक्सर निवेशक यह मान लेते हैं कि ज्यादा म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने से जोखिम कम हो जाता है और रिटर्न बेहतर मिलता है। इसी सोच के चलते कई लोग 10 से 12 या उससे भी ज्यादा फंड्स में एसआईपी शुरू कर देते हैं। लेकिन हकीकत इससे उलट है। जरूरत से ज्यादा फंड्स रखने से न तो जोखिम कम होता है और न ही रिटर्न बढ़ता है, बल्कि आपका पोर्टफोलियो उलझ जाता है और मुनाफा कम हो सकता है। खासतौर पर अगर आपकी मासिक एसआईपी 25,000 रुपये के आसपास है, तो 3 से 5 अच्छे फंड्स का चयन ही बेहतर रणनीति मानी जाती है।

ज्यादा फंड्स रखना क्यों नुकसान का सौदा

म्यूचुअल फंड निवेश का मूल सिद्धांत है विविधता, लेकिन कई निवेशक इस सिद्धांत को गलत तरीके से समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि अलग-अलग (एसेट मैनेजमेंट कंपनी) के ज्यादा फंड्स खरीदना ही विविधता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 10-12 फंड्स हैं, तो संभव है कि उनमें से कई एक ही सेक्टर या एक जैसे शेयरों में निवेश कर रहे हों। ऐसे में आपका पोर्टफोलियो देखने में तो बड़ा लगता है, लेकिन असल में वह विविध नहीं होता। विशेषज्ञ मानते हैं कि सीमित और चुने हुए फंड्स के जरिए बेहतर नियंत्रण और संतुलन बनाना ज्यादा आसान होता है। इससे निवेश की दिशा स्पष्ट रहती है और अनावश्यक जटिलता से बचाव होता है।

आदर्श पोर्टफोलियो कैसा हो

विशेषज्ञों के अनुसार 25,000 रुपये की एसआईपी के लिए 3 से 5 फंड्स का पोर्टफोलियो पर्याप्त होता है। इससे निवेश में संतुलन बना रहता है और जोखिम भी नियंत्रित रहता है। एक संतुलित पोर्टफोलियो के लिए आप इन कैटेगरी पर विचार कर सकते हैं।

- लार्ज-कैप या इंडेक्स फंड स्थिरता के लिए
- लार्ज एंड मिड-कैप फंड ग्रोथ और स्थिरता का मिश्रण
- मल्टी-कैप या फ्लेक्सि-कैप फंड अलग-अलग मार्केट कैप में निवेश
- इक्विटी हाइब्रिड फंड इंटिविटी और डेट का संतुलन
- इंडेक्स-एसेट फंड (टैक्स सेविंग) टैक्स बचत के साथ निवेश
- हर निवेशक अपनी जोखिम क्षमता, लक्ष्य और समय अवधि के अनुसार इन कैटेगरी में 3-5 फंड्स चुन सकता है।

स्मॉलकैप एक माह में 10% उछला जोखिम भी उतना ही बढ़ा

निवेश मंत्रा बिजनेस डेस्क

पिछले एक महीने में स्मॉलकैप म्यूचुअल फंड्स ने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। औसतन 10% तक का रिटर्न देकर इस सेगमेंट ने लार्ज और मिडकैप फंड्स को पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में कई निवेशकों के मन में सवाल उठ रहा है क्या यह तेजी लंबे समय के बुल रन की शुरुआत है या फिर यह सिर्फ गिरावट के बाद आई एक अस्थायी रिकवरी? विशेषज्ञों का मानना है कि इस तेजी को समझदारी से देखना जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान भी करा सकता है।

हालिया आंकड़ों के मुताबिक, स्मॉलकैप म्यूचुअल फंड्स ने पिछले एक महीने में औसतन करीब 10% रिटर्न दिया है। कुछ फंड्स ने तो इससे भी ज्यादा प्रदर्शन किया है, जिससे निवेशकों का मनोसा इस सेगमेंट में फिर से बढ़ा है। हालांकि, सभी फंड्स का प्रदर्शन एक जैसा नहीं रहा। जहां कुछ फंड्स ने दो अंकों का रिटर्न दिया, वहीं कुछ ने नेगेटिव रिटर्न भी दिखाया। इससे साफ है कि यह तेजी पूरे सेगमेंट में समान रूप से नहीं फैली है।

तेजी की वजह: लिक्विडिटी और एसआईपी का सहारा

विशेषज्ञों के अनुसार, स्मॉलकैप फंड्स में आई इस तेजी के पीछे कई कारण हैं। बाजार में बढ़ती लिक्विडिटी, निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता में सुधार और लगातार आने वाला एसआईपी निवेश इस उछाल को सपोर्ट कर रहा है। जब बाजार में नकदी ज्यादा होती है, तो उसका असर छोटे शेयरों पर जल्दी दिखाई देता है। इसी वजह से स्मॉलकैप शेयरों में तेजी अक्सर तेज और अचानक होती है।

व्या यह स्थायी बुल रन है या शॉर्ट टर्म रिकवरी?

यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल यह तेजी एक शॉर्ट टर्म रिकवरी ज्यादा लगती है, न कि लंबी अवधि की स्थायी तेजी। स्मॉलकैप सेगमेंट में उतार-चढ़ाव ज्यादा होता है। गिरावट के बाद तेज उछाल आना आम बात है। इसलिए केवल एक महीने के रिटर्न के आधार पर निवेश का फैसला लेना जोखिम भरा हो सकता है।

पीछे भागना क्यों खतरनाक

अक्सर निवेशक हालिया प्रदर्शन देखकर आकर्षित हो जाते हैं और तेजी से निवेश कर देते हैं। लेकिन 10% जैसे अपेक्षाकृत रिटर्न का पीछा करना सही रणनीति नहीं है। बाजार में ऐसे मुलूमेंट अस्थायी होते हैं और समय के साथ संतुलित हो जाते हैं। इसलिए केवल हालिया रिटर्न देखकर निवेश करना नुकसान का कारण बन सकता है।

अवसर है, पर अलर्ट रहें

स्मॉलकैप म्यूचुअल फंड्स में हालिया तेजी निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य है, लेकिन इसे 'पैसे छापने का मौका' मानना जल्दबाजी होगी। लंबी अवधि के निवेशक एसआईपी के जरिए इसमें धीरे-धीरे निवेश कर सकते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है।

वैल्यूएशन बनी चिंता

हालिया तेजी के बाद स्मॉलकैप शेयरों की वैल्यूएशन फिर से ऊंची नजर आने लगी है। उदाहरण के तौर पर, निफ्टी स्मॉलकैप 100 का फॉरवर्ड पीई अपने लंबे औसत से ऊपर चल रहा है। इसका मतलब है कि शेयरों की कीमतें उनकी कमाई के मुकाबले ज्यादा हो चुकी हैं। ऐसे में आगे रिटर्न सीमित हो सकता है या फिर बाजार में करेक्शन देखने को मिल सकता है।

हर निवेशक के लिए सही नहीं

स्मॉलकैप फंड्स हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। इनमें तेजी के साथ-साथ गिरावट भी उतनी ही तेज होती है। इसलिए यह हर निवेशक के लिए उपयुक्त नहीं है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अगर आपका निवेश समय 7 से 10 साल या उससे ज्यादा है, तभी इस सेगमेंट में निवेश करना चाहिए।

एसआईपी और एसेटीपी से पंटी

स्मॉलकैप में एकमुश्त निवेश करने के बजाय एसआईपी या एसेटीपी के जरिए धीरे-धीरे निवेश करना बेहतर रणनीति मानी जाती है। इससे बाजार के उतार-चढ़ाव का असर कम होता है और आप अलग-अलग स्तरों पर निवेश कर पाते हैं, जिससे औसत लागत संतुलित रहती है।

पोर्टफोलियो में सीमित हिस्सा

एक संतुलित निवेश रणनीति के तहत स्मॉलकैप फंड्स का हिस्सा पोर्टफोलियो में सीमित रखना चाहिए। आमतौर पर 10% से 20% तक का एक्सपोजर पर्याप्त माना जाता है, जो जोखिम और रिटर्न के बीच संतुलन बनाए रखता है। इसके अलावा, फ्लेक्सि कैप और मल्टीकैप फंड्स जैसे विकल्प भी बेहतर संतुलन प्रदान कर सकते हैं।

पैसे धरने का मौका

अक्सर निवेशक हालिया प्रदर्शन देखकर आकर्षित हो जाते हैं और तेजी से निवेश कर देते हैं। लेकिन 10% जैसे अपेक्षाकृत रिटर्न का पीछा करना सही रणनीति नहीं है। बाजार में ऐसे मुलूमेंट अस्थायी होते हैं और समय के साथ संतुलित हो जाते हैं। इसलिए केवल हालिया रिटर्न देखकर निवेश करना नुकसान का कारण बन सकता है।



कठिन समस्याएं अब न होंगी

क्योंकि सच्ची सहेली में है **67** खास आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां जो मुश्किल तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करें।

24x7 Helpline: 77108 44444 • www.sachisaheli.in

67 दुर्लभ प्राकृतिक जड़ी-बूटियों से बना

‘सच्ची सहेली’ आयुर्वेदिक टॉनिक एवं टेबलेट्स

Helps in:

कठिन दर्द

चिड़चिड़ापन

थकान

कमजोरी

कमर कटना

इम्यूनिटी



सच्ची सहेली

एलपीजी आपूर्ति को लेकर नहीं होगी समस्या सरकारी तेल कंपनियों ने 15 देशों में स्पॉट मार्केट से खरीदारी शुरू की

एजेसी नई दिल्ली

मिडिल ईस्ट युद्ध में अमेरिका और ईरान के बीच संघर्षविराम चल रहा है, होर्मुज पर अमेरिका और ईरान की नाकेबंदी के चलते तेल-गैस की आपूर्ति पर संकट बरकरार है। भारत में खासतौर पर एलपीजी संकट से निपटने के लिए सरकार ने घरेलू एलपीजी उत्पादन में इजाफे के साथ ही सिर्फ खाड़ी देशों पर निर्भरता न रखकर अन्य देशों से गैस का आयात शामिल है। अब भारतीय सरकारी तेल कंपनियों ने स्पॉट मार्केट से खरीदारी भी शुरू कर दी है।

किसी भी स्थिति में देश के लोगों को आपूर्ति में कमी की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। स्पॉट मार्केट से एलपीजी कार्गो जून और जुलाई में भारत पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें, स्पॉट मार्केट में तुरंत जरूरत के हिसाब से बाजार से खरीद की जाती है।

भारत को वर्तमान में 34,000 टन एलपीजी की जरूरत है जो अब कई देशों से आ रही है। पहले जहां 10 देशों से एलपीजी आयात किया जाता था, तो अब ऐसे देशों की संख्या बढ़कर 15 हो गई

स्पॉट मार्केट से एलपीजी कार्गो जून और जुलाई में भारत पहुंचने की उम्मीद



घरेलू एलपीजी उत्पादन करीब 20 फीसदी बढ़कर 46,000 टन पर पहुंचा

देश में प्रतिदिन 80,000 टन एलपीजी की जरूरत

भारत में रोजाना करीब 80,000 टन एलपीजी की जरूरत है। वहीं देश में घरेलू एलपीजी उत्पादन करीब 20 फीसदी बढ़कर अब 46,000 टन किया जा चुका है। भारत को वर्तमान में 34,000 टन एलपीजी की जरूरत है जो अब कई देशों से आ रही है। पहले जहां 10 देशों से एलपीजी आयात किया जाता था, तो अब ऐसे देशों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है।

जहां से मिलेगी, हम खरीदेंगे: सुजाता

बता दें, भारत अपनी एलपीजी मांग का लगभग 60% आयात करता है। एलपीजी संकट के बीच सरकार द्वारा घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए गैस आदेश के चलते उत्पादन में बड़ा इजाफा हुआ है और भारत की आयात पर निर्भरता कम हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता घरेलू आपूर्ति को पूरा करना है और इसके लिए जहां से भी मुम्किन होगा, वहीं से कार्गो मंगाया जाएगा।



उर्वरक कमी के दावे निराधार

केंद्र सरकार ने कहा है कि उर्वरकों की कमी के दावे निराधार हैं। उर्वरक विभाग के अनुसार, अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 के बीच यूरिया की उपलब्धता 257.59 लाख मीट्रिक टन (एलएफटी) थी, जबकि जरूरत 196.06 एलएफटी थी। डीएपी की उपलब्धता 75.40 एलएफटी, जरूरत 53.43 एलएफटी थी। एमओपी की उपलब्धता 19.64 एलएफटी थी जरूरत 15.69 एलएफटी थी।

अमेरिका, रूस, नावें से हो रही खरीदारी

युद्ध से पहले भारत की जरूरत की 90% एलपीजी तमाम खाड़ी देशों से होती थी। इनमें यूएई, कतर, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और ओमान शामिल थे। वहीं एलपीजी संकट के बीच इंपोर्ट डेस्टिनेशंस में विविधकरण के सरकार के प्लान बी के चलते अब लैटिन अमेरिका, नावें, कनाडा, अल्जीरिया और रूस जैसे देशों से हो रही है। बीते दिनों सरकार ने बताया था कि कार्गो 8 लाख टन एलपीजी का कार्गो पहले ही सुरक्षित कर लिया गया।

खबर संक्षेप

तुर्की में पकड़ाया ड्रग माफिया सलीम डोला

इस्तांबुल। तुर्की की सुरक्षा एजेंसियों ने इस्तांबुल में बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय



कुख्यात ड्रग माफिया सलीम डोला को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी के नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी पुष्टि की है। सलीम डोला का कनेक्शन ग्लोबल सिंथेटिक ड्रग नेटवर्क से था और उसका जाल कई देशों तक फैला हुआ था। इस ड्रग रैकेट के तार भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क से भी जुड़े बताए जा रहे हैं।

जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े साढ़े तीन करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। यह कार्रवाई मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस अभियान और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत की गई। संगम पुलिस थाने ने आरोपियों की पहचान नूरजाम में केशव इलाके के निवासी शकील अहमद गनी और फारूक अहमद मीर के रूप में की है। पुलिस ने गनी के दो सखल आवासों घर और उसके साथ लगी एक कनाल भूमि को कुर्क कर दिया है, जिसकी कीमत दो करोड़ रुपए से अधिक है।

भारत-अमेरिका साझेदारी गहरी होने से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ेगी देश की ताकत

सीडीएस अनिल चौहान ने अमेरिकी इंडो-पैसिफिक कमांड के वरिष्ठ अधिकारियों संग की अहम बैठक

एजेसी नई दिल्ली

भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है। इसी कड़ी में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अमेरिकी इंडो-पैसिफिक कमांड के वरिष्ठ अधिकारी जनरल केविन बी. शनाइडर के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में दोनों देशों ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया।

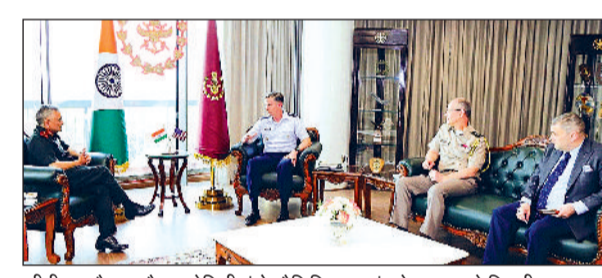
साथ ही, क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर सहयोग को और गहरा करने पर जोर दिया गया। बैठक के दौरान भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रणनीतिक तालमेल पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने यह स्पष्ट किया कि वे क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।

इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय के अनुसार, इस बातचीत में द्विपक्षीय और त्रि-सेवा सहयोग को और विस्तारित करने पर भी सहमति बनी। बैठक के दौरान दोनों देशों ने इस बात को स्वीकार किया कि आधुनिक समय में तकनीक सैन्य शक्ति का अहम आधार बन चुकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए रक्षा सहयोग को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम करने पर बल दिया गया।

बैठक के दौरान भारत और अमेरिका ने इस बात को स्वीकार किया कि आधुनिक समय में तकनीक सैन्य शक्ति का अहम आधार बन चुकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए रक्षा सहयोग को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम करने पर बल दिया गया

दोनों देश इंडो-पैसिफिक में शांति, स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखेंगे

द्विपक्षीय और त्रि-सेवा सहयोग को और विस्तारित करने पर सहमत



सीडीएस चौहान और अमेरिकी इंडो-पैसिफिक कमांड के जनरल केविन बी. शनाइडर

अमेरिकी सेना का बड़ा बयान

चीन पर दबाव बढ़ाने की अमेरिकी रणनीति में भारत बन रहा ताकत

अमेरिकी इंडो-पैसिफिक कमांड के प्रमुख एडमिरल सैमुअल पापारो ने अमेरिकी सांसदों से कहा कि भारत के साथ जुड़ाव उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। पापारो ने बताया कि चीन की सैन्य गतिविधियां, साथ ही रूस और उत्तर कोरिया के साथ उसके गहरे होने संबंध, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जटिल चुनौती पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए उसके सहयोगी देश और साझेदार ही सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत हैं। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं और यह अमेरिका की सबसे सशक्त सैन्य साझेदारियों में से एक है। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, खुफिया साझेदारी और अंतरराष्ट्रीय डोमेन अवेयरनेस जैसे क्षेत्रों में तेजी से सहयोग बढ़ा है। उन्होंने भारत द्वारा एमक्यू-9बी ड्रोन खरीद योजना का भी जिक्र किया। यह ड्रोन लंबी दूरी की निगरानी, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक मिशनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

भारत हिंद महासागर में मजबूत स्थिति में
पापारो के अनुसार, भारत न केवल अपने क्षेत्र में संतुलन बनाए हुए है, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भी अपनी रणनीतिक उपस्थिति मजबूत कर रहा है। पापारो ने श्रीलंका में भारत के निवेश और मॉरीशस के साथ हुए समझौते का उल्लेख किया। उनका कहना था कि इन कदमों का मकसद समुद्री सहयोग बढ़ाना और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को प्रतिकूल शक्तियों के प्रभाव से मुक्त रखना है।

व्हाट्स में भारत की भूमिका अहम
अमेरिकी कमांडर ने व्हाट्स में भारत की भूमिका को भी अहम बताया। इस समूह में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। यह मंच इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में मुक्त, सुरक्षित और संतुलित व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि साझेदार सैन्य अत्यास जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास चारों देशों के बीच तालमेल बढ़ाने, तकनीकी क्षमता साझा करने और संयुक्त सैन्य तैयारी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा की 31450 सीट बुक

देहरादून। केदारनाथ हेलीकॉप्टर शटल सेवा की 22 अप्रैल से 15 जून के बीच उपलब्ध सभी 31,450 सीट पोर्टल खुलने के महज 90 मिनट के भीतर बुक हो गईं। अधिकारियों ने बताया कि बुकिंग प्रक्रिया 15 अप्रैल को शाम छह बजे शुरू हुई और शाम सात बजेकर 28 मिनट पर अंतिम टिकट जारी हुआ। इस दौरान भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम के आधिकारिक पोर्टल पर कुल 10,855 टिकट बुक किए गए। यह सेवा 16 किलोमीटर के दुर्गम पैदल मार्ग से राहत दिलाती है।

चीन में ऑनलाइन फूड स्टैम का खुलासा

67 हजार फर्जी दुकानें, कंपनियों पर लगाया 4400 करोड़ जुर्माना



एजेसी नई दिल्ली

चीन में ऑनलाइन फूड डिलीवरी के नाम पर चल रहे एक बहुत बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। एक ग्राहक की शिकायत के बाद हुई जांच में 67,000 से ज्यादा ऐसी दुकानें मिलीं जिनका असंलयित में कोई अस्तित्व ही नहीं था। इस खेल को चलते रहने के लिए अलीबाबा

‘पीडीएस’ घोटाले पर इंडी की बंगाल में रेड

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के कथित पीडीएस घोटाले से जुड़े मामले में इंडी ने शनिवार को कई ठिकानों पर छापेमारी की। मनी लॉइंग की जांच के तहत कोलकाता और बर्धमान में कई स्थानों पर छापेमारी की गई। कोलकाता, बर्धमान और हाबरा में निरंजन चंद्र साहा समेत आपूर्तिकर्ताओं और निर्यातकों के लगभग नौ परिसरों पर तलाशी अभियान जारी है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत की जा रही है।



सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बड़ा खुलासा किया। सरकार ने बताया कि रूस-यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना की ओर से लड़ते हुए 10 भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि इनमें से अधिकांश ने अपनी मर्जी से गए थे, जिसके चलते वे इस संघर्ष के बीच पहुंच गए। मारे गए लोगों में ज्यादातर युवा हैं और भारत में उनकी 25-26 वर्षीय पत्नी

यूक्रेन की आड़ में पश्चिम ने मॉस्को के खिलाफ छेड़ा युद्ध: रूसी विदेश मंत्री लावरोव

मॉस्को। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पश्चिमी देशों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि यूक्रेन की आड़ में रूस के खिलाफ खुला युद्ध छेड़ा जा चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश यूक्रेन को मोर्चे पर आने रखकर रूस को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। लावरोव ने यह बयान रूसी गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में किया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश माले की नोक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वे पश्चिमी हथियारों, खुफिया सूचनाओं, सैटेलाइट सिस्टम, सैन्य प्रशिक्षण और आर्थिक मदद के बिना टिक नहीं सकते। रूस के खिलाफ यह संघर्ष अब केवल परोक्ष नहीं बल्कि खुला और संगठित अभियान बन चुका है। उन्होंने दावा किया कि कुछ यूरोपीय सैन्य अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी की बात कही है, जबकि यूक्रेन इस बीच पश्चिमी देशों के लिए समय जुटाने का माध्यम बना हुआ है।

रूस की जंग में भारत के 10 बेटों की मौत, 25 की उम्र में विधवा हुई पत्नियां

सरकार बोली- मर्जी से गए थे, कोर्ट का आदेश ‘स्टेटस रिपोर्ट’ दें

एजेसी नई दिल्ली

विधवा हो गई हैं। विदेश मंत्रालय ने यह जवाब उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया, जो रूस-यूक्रेन युद्ध में फंसे 26 भारतीय पुरुषों के परिवारों द्वारा दायर की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सुर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलों सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह अब तक उठाए गए कदमों पर एक विस्तृत ‘स्टेटस रिपोर्ट’ दाखिल करें।



परिवारों की ओर से प्रेश हूप वकील ऋत्विक् मंगोट ने विदेश मंत्रालय पर लापरवाही और निष्क्रियता के आरोप लगाए। वकील ने स्पष्ट किया कि इन लोगों को रूस में नौकरी का झूठा झंझा देकर ठगना गया था। वहां पहुंचने पर उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए और उन्हें जबरन युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। विदेश मंत्रालय से कई बार गुहार लगाने के बावजूद कोई त्वरित कार्रवाई नहीं हुई। मुक्तकों की सही पहचान और पार्थिव शरीर वापस लाने के लिए याचिकाकर्ताओं ने अदालत से निर्देश देने की मांग की कि परिवारों के डीएनए सैपल लिए जाएं।

पोड़ितों के परिवारों के डीएनए सैपल की मांग

मामला अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया

विदेश मंत्रालय निष्क्रिय: याचिकाकर्ता

परिवारों की ओर से प्रेश हूप वकील ऋत्विक् मंगोट ने विदेश मंत्रालय पर लापरवाही और निष्क्रियता के आरोप लगाए। वकील ने स्पष्ट किया कि इन लोगों को रूस में नौकरी का झूठा झंझा देकर ठगना गया था। वहां पहुंचने पर उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए और उन्हें जबरन युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। विदेश मंत्रालय से कई बार गुहार लगाने के बावजूद कोई त्वरित कार्रवाई नहीं हुई। मुक्तकों की सही पहचान और पार्थिव शरीर वापस लाने के लिए याचिकाकर्ताओं ने अदालत से निर्देश देने की मांग की कि परिवारों के डीएनए सैपल लिए जाएं।

कुछ एजेंट नौकरी के लिए उकसा रहे

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या गाटी ने सरकार का पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि 26 में से 10 भारतीयों की मौत हो चुकी है। एक व्यक्ति पर आपराधिक मामला दर्ज है, जबकि एक अन्य व्यक्ति जानबूझकर वहीं उका हुआ है। उन्होंने बताया कि ये लोग अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं और कुछ एजेंट/बिरोलिया उन्हें ऐसा करने के लिए उकसा रहे हैं। केंद्र बहु-उद्योगी रणनीति पर काम कर रहा है और लोगों को ऐसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार न करने की सलाह दे रहा है।